पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

Wish You all a Very Happy New Year

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Vision -
To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-
To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तद् लक्ष्यम्

Admission Open
For The Academic Session 2024-25
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्युच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

नवंबर 2025

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

₹:40

मोदी में पटेल जैसे गुण

नीतीश की बहार

कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा न होती तो शायद खाता भी नहीं खुलता, राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस खुद तो डूबती है साथ में गठबंधन करने वाली पार्टियों को भी डुबो देती है, बिहार में तेजस्वी की राजद को डूबोने के बाद राहुल गांधी का अगला टारगेट क्या यूपी के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी होगी?

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

Nupur Creations

Jute Hand Bags, Craft & Many More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की **वोकल फॉर लोकल** नीति से प्रेरित उत्तराखंड के हस्तकला के क्षेत्र में उभरता नाम

नुपूर

उत्तराखंड की हस्तकला को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य
उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रयास
जूट से बने फेंसी आइटम, होम डेकोरेशन की फेंसी सामग्री, गिफ्ट आइटम की बड़ी रेंज ऑन लाइन उपलब्ध

SHAKTI PURAM GALI,
NAWABI ROAD, HALDWANI
(NAINITAL), Uttarakhand

CALL:
05946 220841, +91 9410334041
Paytm +91 9760590897

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurcreations.co.in

Log in for purchase Items ONLINE:

मासिक
उत्तरांचल दीप पत्रिका

वर्ष:8, अंक 7, नवंबर 2025

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो

दिल्ली	: शालिनी चौहान
लखनऊ	: पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग	: हिमांशु पुरोहित
नैनीताल	: अफजल फौजी
अल्मोड़ा	: कमल कपूर
पिथौरागढ़	: ललित जोशी
बागेश्वर	: नरेंद्र बिष्ट
चंपावत	: मनोज राय
बरेली	: अनुज सक्सेना
मुरादाबाद	: आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला	: चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा	: राजकुमार राज
रामनगर	: एचसी भट्ट
थत्यूड़	: मुकेश रावत
रुद्रपुर	: मुकेश गुप्ता
बाजपुर	: इंद्रजीत सिंह

ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम को प्राइज मनी के अलावा मेगा टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों की फीस भी मिलेगी, यानी प्लेइंग-11 में खेलने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच 6 लाख और बाहर बैठने वाले को 3 लाख फीस मिलेगी, तीनों स्त्रोतों से मिलने वाली रकम को जोड़ा जाए, तो हर खिलाड़ी के हिस्से में करीब पांच करोड़ रुपये आएंगे।

उत्तराखंड
1000 करोड़ की बिजली चोरी

हरिद्वार के गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल के बिजली घर के बाहर से पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर पूछताछ की तो ...

राजनीति
नाकामी छिपा रहे राहुल गांधी?

राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका चुनाव आयोग से या भाजपा ...

रजत जयंती
25 वर्षों में यूके ने क्या पाया

अलग राज्य बनने से पहाड़ का जंगल, जमीन, जवानी और पानी राज्य के विकास के काम आएंगा, लेकिन ...

उत्तराखंड

कुमाऊं का आत्मनिर्भर सूपी गांव

गुमनाम रहा सूपी गांव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की नजरों में आया तो इसकी पहचान उत्तराखंड के कृषि और ...

साकेत अग्रवाल

जेन जी ने निकाला जनाजा

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जता और बता दिया कि अब वंशवादी अथवा खानदारी राजनीति का जमाना लद गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जेन जी के नाम की माला लेकर जप और तप कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि जेन जी के सहारे ही कांग्रेस की नैया पार लगेगी, लेकिन बिहार के जेन-जी ने पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया। क्योंकि चुनाव बिहार में हो रहे थे और राहुल गांधी मलेशया और कोलंबिया में मस्ती कर रहे थे। बिहार में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा बुलंद करने वाले और 'वोट चोरी' की मुनादी करने वाले राहुल गांधी की हसरतों का जनाजा बिहार के जेन जी ने ही निकाल दिया। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आह्वान कर रहे थे कि देश का लोकतंत्र बचाने के लिए जेन जी को आगे आना होगा। वोट चोरी रोकने के लिए भी जेन जी को ही आगे आना होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मान रहे थे कि उनके एक आह्वान पर जेन जी सड़कों पर निकलेगा और नेपाल की तरह अराजकता फैला देगा, लेकिन जेन जी राहुल गांधी से ज्यादा समझदार है। उसे पता है कि राहुल गांधी अपने जेन जी भांजे और भांजी को विदेश में पढ़ा रहे और उन्हें भड़काकर जेल भिजवाने या लाठी खाने का इंतजाम कर रहे हैं। जेन जी समझ चुका है कि राहुल गांधी को मोदी के नाम का मोतियाबिंद हो गया है इसलिए उन्हें राजनीति में अपना भविष्य भी नजर नहीं आ रहा है। जेन जी समझता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता कभी विकसित भारत की बात क्यों नहीं करते? कभी भारत के आत्मनिर्भर बनाने की बात क्यों नहीं करते? युवाओं में स्किल की बात क्यों नहीं करते? राष्ट्रभक्ति की बात कभी ये नेता नहीं करते, सनातन का सदैव अपमान करते हैं। सनातन से नफरत करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। विपक्षी नेता सरकार की जनहित की योजना का विरोध करते है। वक्फ कानून फाड़ने का ऐलान करते है। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से राजद को बिहार में 20 साल से और कांग्रेस को देश में 10 साल से क्या हासिल हुआ? इस पर मंथन करने की कांग्रेसियों को फुर्सत नहीं है। जो मंथन करते हैं उनकी पार्टी में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए लगातार कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। बिहार के नतीजे तो कांग्रेस के लिए शर्मनाक हैं। जहां देश की सबसे बूढ़ी कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम से भी बदतर हालत में पहुंच गई। बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसमें से सिर्फ 6 पर जीत मिली औसत निकाला जाए तो 10 में से एक सीट पर जीत मिली। जबकि एआईएमआईएम सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 जीती। ये आकड़ें बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन एआईएमआईएम का रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी बेदम हो चुकी है।

कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के दल सभी नकारात्मक राजनीति का शिकार हैं। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए यहां तक कह देते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। गरीबों के लिए जनधन खाता खोलने की योजना का विपक्ष ने विरोध ही नहीं किया बल्कि मजाक भी उड़ाया था। 2016 में नोट बंदी का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने अपने कुर्ते की फटी जेब तक दिखा दी थी। गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए गए तो सबसे ज्यादा विपक्ष ने छाती पीटी थी। पीएम मोदी का स्वच्छ भारत अभियान हो या हर घर बिजली पहुंचाने वाली उजाला योजना इनका विपक्ष ने ही विरोध किया था। केंद्र सरकार की अंत्योदय योजना के विरोध में भी विपक्ष खड़ा देखा गया। वायु सेना के लिए राफेल फाइटर जेट खरीदने का विरोध करते हुए चौकीदार चोर तक का नारा भी राहुल गांधी ने दिया था। सीएए कानून के विरोद में तो दिल्ली को बंधक तक बनाया गया जबकि ये कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू और अल्पसंख्यक सिख, बौद्ध आदि को भारत की नागरिकता देने के लिए था। देश में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए के खिलाफ अभियान चलाने, वापस उनके देश भेजने के लिए एनआरसी कानून लाया गया तो विरोधी दलों ने छाती पीटने का काम किया। जनता जानती है कि जब सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भारत ने पहली बार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाई तो उस पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और अखिलेश जैसे ही नेता थे। कोरोना काल मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दूसरे देशों की भी मदद की, लेकिन मानवता के इस कार्य में भी बाधा डालने से विपक्ष बाज नहीं आया। किसानों के उत्थान और उनकी आय को दोगुना करने के लिए लाए गए कृषि कानून का विपक्ष ने जोरदार तरीके से विरोध किया। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ट्रिपल तलाक कानून का भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने ही विरोध किया था। अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर का विरोध हो या काशी और मथुरा का मुद्दा सब में कांग्रेसी नेता गलत लोगों के साथ खड़े मिले। कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में पत्थरबाजों पर कार्रवाई का विरोध हो या अतिक्रमण हटाने का अभियान विपक्ष हमेशा विपक्ष ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35ए हटाने के राष्ट्रहित के काम में विपक्ष अड़ंगा डालता रहा, लेकिन नाकाम रहा। इसके विपरीत जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी बताते हुए विश्व का बॉस बताते हैं, तब देश का गौरव बढ़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही देश भारत में विपक्षी दलों के नेता अपशब्द कहते हैं। सार्वजनिक मंचो से गाली तक देते हैं। उनके उठाए गए हर कदम पर विपक्षी दल विरोध का बिगुल फूंकने लगते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या विरोध ही भारत की राजनीति का हिस्सा बन गया है, चाहे मुद्दा सही हो या गलत? इसलिए ही कांग्रेस हो या राजद अथवा समाजवादी पार्टी लगातार हार का दीदार कर रही हैं।

100 करोड़ का सीओ सस्पेंड

स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम की जांच में सामने आया है कि सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है, इनमें आर्यनगर की 11 दुकानें भी शामिल हैं, जो कथित रूप से उनके सहयोगी देवेंद्र दुबे के नाम पर बेनामी संपत्ति के रूप में दर्ज हैं।

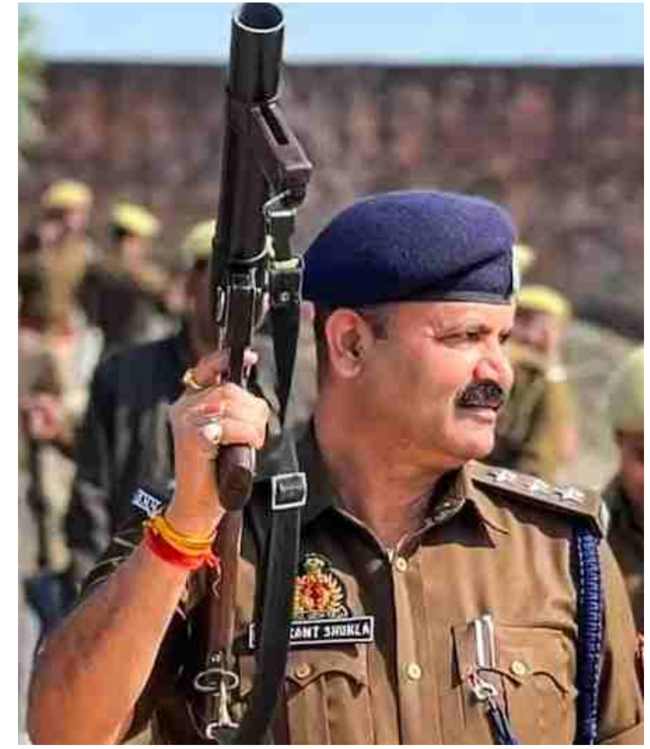

कानपुर में तैनात रहे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने करीब 10 साल की सेवा के दौरान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। अब उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई है जिससे पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची है। शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत पुलिस उप निरीक्षक के रूप में की थी और लगातार प्रमोशन पाते हुए सर्किल ऑफिसर (सीओ) के पद तक पहुंच गए। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने सेवाकाल के करीब 10 वर्ष कानपुर में ही बिताए और कानपुर में रहते हुए ही अवैध संपत्ति खड़ी की। ऋषिकांत शुक्ला 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक। कानपुर में तैनात रहे। इस दौरान चर्चित वकील अखिलेश दुबे उनके करीब आया। आरोप है कि अखिलेश दुबे के साथ मिलकर शुक्ला ने फर्जी मुकदमे दर्ज करने, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने का खेल शुरू किया। अखिलेश दुबे फिलहाल जेल में बंद हैं। उन पर झूठे पॉक्सो के मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से करोड़ों रुपयों की रंगदारी वसूलने का आरोप है। पिछले महीने ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनका साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों की भी कुंडली खंगाली जा रही थी। इसमें ऋषिकांत शुक्ला का नाम सामने आया। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अखिलेश दुबे पर शहर में एक गिरोह बनाकर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली करने और जमीन कब्जाने का खेल किया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दुबे का कुछ पुलिस अधिकारियों और अन्य विभागों से भी गठजोड़ है। स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम की जांच में सामने आया है कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है। इनमें आर्यनगर की 11 दुकानें भी शामिल हैं, जो कथित रूप से उनके सहयोगी देवेंद्र दुबे के नाम पर बेनामी संपत्ति के रूप में दर्ज हैं। जांच में मिली संपत्तियां, ऋषिकांत शुक्ला की घोषित आय से कई गुना ज्यादा कीमत की हैं। जांच रिपोर्ट में 12 संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 92 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि अन्य तीन संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर मांग की है कि सीओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ सतर्कता (विजिलेंस) जांच कराई जाए। फिलहाल गृह मंत्रालय ने ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया है।

सीओ की सफाई

मैनपुरी जिले के भोगांव में तैनात रहे निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि मेरे अखिलेश दुबे से एक लीगल एडवाइजर और पुलिस अधिकारी के रूप में संबंध है। जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था तो उस संबंध में मैं उनसे लीगल सलाह लेने के लिए जाता था। कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरी उनसे बातचीत हुई। मेरे उनसे संबंध केवल लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। निलंबित सीओ ने सफाई दी कि दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से हैं, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास आर्य नगर में बताई जा रही है। मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं। उनकी 92 करोड़ की प्रॉपर्टी और 11 दुकानें मेरी बताई जा रही हैं। यह सारे दावे झूठे हैं। उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर्य नगर में नहीं है। मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का आरोप लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश दुबे के साथ मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका 100 करोड़ टर्नओवर है। यह सरासर गलत है। मुझे लगता है कुछ अपराधी और माफिया गैंग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, हो सकता है कि उनके पैरोकार किसी माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों। मैंने डिटो गैंग, जिसने एसटीएफ के धर्मेंद्र सिंह को मारा था उसको मैंने कोलकाता से पकड़ा था। तब सरकार ने मुझे 1 लाख का रिवॉर्ड दिया था। इसका एक भाई भी था, जिसके ऊपर 2 लाख का इनाम था। उसको मैंने दिल्ली में स्पेशल सेल के साथ मिलकर पकड़ा था। इसके अलावा मैंने डिटो गैंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है जो कि 3 दशक से आतंक फैलाए हुए था। निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने आगे कहा कि मैंने कई ड्रग तस्करों को पकड़ा। मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर्स को मैंने एनकाउंटर में मारा। इसके अलावा बहुत से ऐसे अपराधी थे जो समाज के लिए और कानून के लिए दुश्मन थे। उनके खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की। हो सकता है कि ऐसा गैंग संगठित होकर के मेरे खिलाफ साजिश कर रहा हो।

ऋषिकांत शुक्ला ने दावा किया कि मनोहर शुक्ला एक झूठा षड्यंत्र मेरे खिलाफ कर रहा है। मनोहर शुक्ला के बारे में मैंने जो कुछ जानकारी की, वह माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला का पड़ोसी है। उसके गांव का रिश्तेदार है। वह इसके रिलेशन में भी आता है। वह अपराधी है। मुखबिरी करता था, जिसकी आड़ में वह मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसकी जो बातें बताई जा रही हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि जहां तक एसआईटी की तरफ से मुझे संपत्ति की जांच के बारे में नोटिस देने की बात है, वह भी झूठी है। मुझे ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जहां तक पूर्व सीपी अखिल कुमार या एसआईटी की बात है, उनको कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया है। तभी उन्होंने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट भेजी है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं उनको स्पष्टिकरण देता तो वह संतुष्ट हो जाते। मुझे अपने उच्च अधिकारियों पर, जांच अधिकारी पर और सरकार पर पूरा भरोसा है। मुझे जहां बुलाया जाएगा, वहां पर जाऊंगा और अपनी बातों को तथ्य सहित रखूंगा।

सुर्खियां

उत्तराखंड का 'लेखक गांव'

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक लेखक गांव भी है। इस गांव का राज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ा हुआ हैदेहरादून के निकट सुरम्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित थानो गांव में देश के पहले 'लेखक गांव' का लोकार्पण किया गया। देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव का लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस गांव की अवधारणा से लेकर उसका विकास उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, जो स्वयं एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में भी पहचान रखते हैं। उनका दावा है कि इस गांव में लेखकों को अपनी कृतियों के सृजन के लिए जरूरी एवं शांत और रचनाशील वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव 'स्पर्श हिमालय महोत्सव-2024' के दौरान निशंक द्वारा लिखी गई लेखक गांव की पहली रचना 'हिमालय में राम' पुस्तक का विमोचन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति ने 'लेखक गांव' को लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और अन्य रचनाकारों द्वारा महसूस की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों का निवारण करने की ओर एक अभिनव पहल बताया और इसके लिए निशंक की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड में स्थित यह पहला लेखक गांव भविष्य का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। राज्यपाल ने कहा कि यह मंच उन लेखकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने शब्दों के माध्यम से समाज को नई राह दिखाने का सामर्थ रखते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अनेक विद्वानों व लेखकों की जन्मभूमि रही है और लेखक गांव के वातावरण में सृजनशीलता का प्रवाह अनेक लेखकों और कवियों को प्रेरित करेगा। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रहा है और यहां के पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने लेखकों, कवियों तथा विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लेखक गांव महोत्सव में देश-विदेश से जुटे साहित्यकार और कलाकार अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

समारोह में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि सृजनात्मक माहौल के लिए लेखक गांव जैसा एकांत स्थान चाहिए जहां आप स्वयं के अस्तित्व में डूबकर मोती निकाल सकते हैं। लेखक गांव में लेखन कुटीर, संजीवनी वाटिका, नक्षत्र और नवग्रह वाटिका, पुस्तकालय, कला दीर्घा, प्रेक्षागृह, योग-ध्यान केंद्र, परिचर्चा केंद्र, गंगा और हिमालय का मनमोहक संग्रहालय, भोजनालय आदि सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेखक गांव आकर लेखक एक ही स्थान पर प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान से साक्षात्कार कर विविध विषयों पर नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। 65 से अधिक देशों के लेखन, कला और संस्कृति से जुड़े लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं जिनमें से 40 देशों से लोग यहां आए हैं। इनमें देश और दुनिया से आए छात्र भी शामिल हैं, जो लेखकों से जुड़ना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पीड़ा से लेखक गांव का जन्म हुआ है। एक किताब के विमोचन के दौरान वो खो गए थे। उनकी आंखें छलक आई थी। तब उन्होंने कहा था कि देश में लेखकों को कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता। निराला, श्यामनारायण पांडेय जैसे लेखकों की मौत गरीबी में हुई। उनके पास दवा तक के पैसे नहीं थे। अटल जी ने कहा था कि क्या कोई इस दिशा में सोचेगा। लेखक गांव उन्हें श्रद्धांजलि है। अटल जी एक संवेदनशील व्यक्ति थे इसलिए संवेदना को बचाना जरूरी है।

हाईवे से पशु हटाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश देते हुए हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं। कोर्ट ने इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निकायों को भी ये काम करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि राजमार्ग के लिए गश्ती दल गठित किया जाए, जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखें जहां उनकी देखभाल की जा सकें। दरअसल आवारा पशुओं का आतंक देशभर में लगातार बढ़ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि हाईवे पर गाय-भैंसों के झुंड या तो बैठे रहते हैं या फिर खुले घूमते नजर आते हैं। जिनकी वजह से कई बार हाईवे से गुजरने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों को हादसे का शिकार होना पड़ता है, जिसमें लोगों की दुखद मौत की घटनाएं तक भी सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं को देखते हुए ही अब सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आवारा कुत्तों को स्कूलों-बस अड्डों के पास से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों जैसे संस्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए।

21वीं सदी की लघुकथाएं

रावेल पुष्प

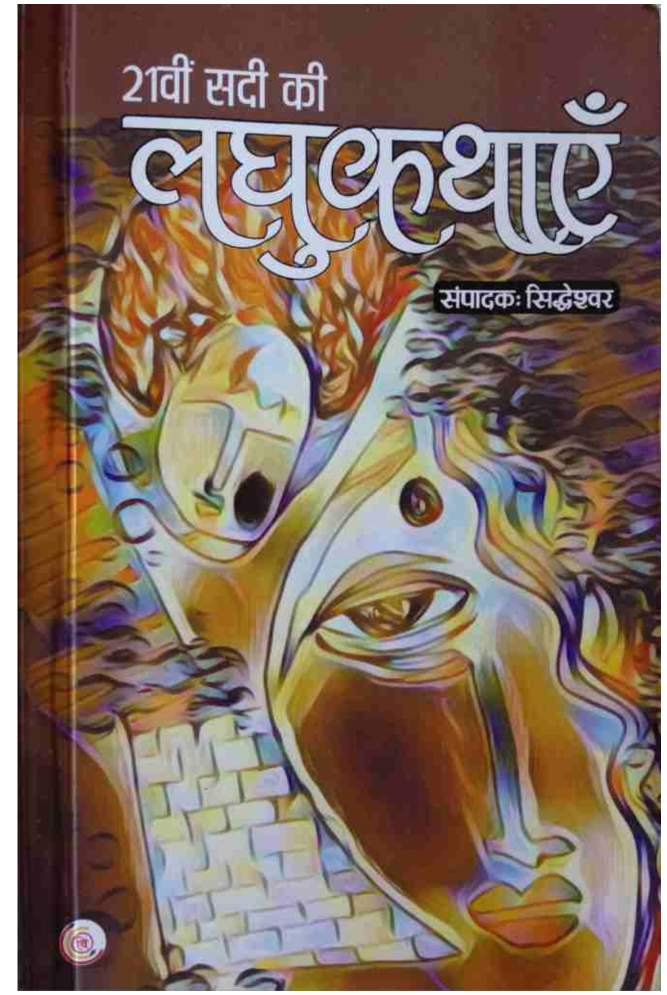

हिंदी लघुकथा का इतिहास लगभग एक सदी पुराना है, परंतु इसकी जड़ें भारतीय कथा परंपरा में बहुत गहरी हैं। लोककथाएं, दृष्टांत, नीति-कथाएं व पंचतंत्र की संक्षिप्त रूपात्मकता ही आगे चलकर लघुकथा की आधारभूमि बनी। आधुनिक हिंदी साहित्य में लघुकथा का रूप स्वतंत्र विधा के रूप में उभरता है सन् 1960 के दशक के बाद, जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने मनुष्य की संवेदनाओं को झकझोर दिया। उस समय कहानी का स्वरूप लंबा और विस्तारपूर्ण था, किंतु शहरी जीवन की आपाधापी में लेखक और पाठक दोनों ही संक्षेप और प्रभाव की तलाश में थे। परिणामस्वरूप 'लघुकथा' ने आकार लिया...कम शब्दों में गहरी बात कहने की कला। 1970 और 80 के दशक में लघुकथा आंदोलन के रूप में उभरी। यूं तो लघुकथा को परिपक्व बनाने में तथा उसे एक नई दिशा देने में देश भर के सैंकड़ों लघु कथाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लघुकथा के विकास में देश की कई संस्थाओं का योगदान भी अच्छा खासा रहा है। उसमें सबसे पहला नाम आता है, डॉ. सतीशराज पुष्करणा का जिनके नेतृत्व में पटना (बिहार) की साहित्य संस्था-अखिल भारतीय प्रगतिशील लघुकथा मंच ने लगभग तीन दशकों तक लगातार देश भर के लघु कथाकारों को जुटाने और लघुकथा को साहित्य में उचित स्थान दिलाने का सफल प्रयास किया। इसी क्रम में फिर प्रमुख लघु कथाकार तथा समीक्षक सिद्धेश्वर लगातार इस विधा को प्रसिद्धि दिलाने में लघुकथा पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाते रहे। अपने जमाने में राजेंद्र यादव अपने संपादन में प्रकाशित 'हंस' पत्रिका में लघुकथा को प्रमुखता से स्थान देते रहे। इसके अलावा जहां लघुकथाओं को पहले महज 'फिलर' के तौर पर लिया जाता था वहीं अब पाठकों की सर्वाधिक प्रिय स्वीकृत विधा हो गई है।

अब तो लघु कथाओं पर पत्रिकाओं के विशेषांक और इस पर बाकायदा प्रतियोगिताएं भी होने लगी हैं। लघु कथाओं पर लेखकों के जहां साझा संकलन निकल रहे हैं वहीं एकल संकलन भी लगातार आ रहे हैं। इसके अलावे लघुकथाओं पर समीक्षात्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं। जहां बीसवीं सदी की लघुकथाएं साहित्य में अपना स्थान बना रहीं थीं, वहीं अब 21 वीं सदी की लघुकथाएं तो पूरे दम-खम के साथ साहित्य जगत में अपनी खास जगह बनाने में सक्षम हुई हैं। इसी क्रम में सिद्धेश्वर के संपादन में बिल्कुल ताजा-तरीन एक पुस्तक आई है-'21वीं सदी की लघुकथाएं।' इसमें अलग- अलग खंडों में सामग्री को समेटा गया है। पहले खंड में कुछ महत्वपूर्ण सर्वोचनात्मक आलेख हैं, जिनमें लघुकथाओं के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई है, जिसमें सिद्धेश्वर का '21वीं सदी की लघुकथाएं' शामिल हैं-तथा लघुकथा को समर्पित पत्रिकाएं, ऋचा वर्मा की कथा में एक यात्रा जरूर होनी चाहिए, एकलव्य केसरी का लघुकथा का हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान तथा योगेंद्र नाथ शुक्ल का लघुकथा को अति बौद्धिकता और समूहबाजी से बचाना जरूरी।

इन आलेखों से जो खास बातें उभरकर सामने आई हैं वो हैं-लघुकथा एक सशक्त विधा के रूप में अब स्वीकार ली गई है। आज लघुकथा कविता के निकट होते हुए भी पाठकों के बीच कविता से अधिक लोकप्रिय और पठनीय विधा है। दरअसल लघुकथा कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ने वाली विधा होने के कारण पाठकों की पहली पसंद बन गई है। आज स्थिति ये है कि लघुकथा ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर लिया है। अब तो लघुकथाओं पर लघु फिल्में भी लगातार बन रही हैं। आज जब बहुसंख्यक लघु कथाकार सामने आ रहे हैं तो इस लघुकथा के साहित्याकाश में सितारों के बीच से नक्षत्रों को चुनना तो वाकई एक चुनौती भरा कार्य ही कहा जाएगा और इस पर बखूबी टीका-टिप्पणी का खतरा तो स्वाभाविक है और अपेक्षित भी, लेकिन इस पुस्तक में एक बड़े समूह द्वारा किए गए ऐसे सर्वेक्षण का जिक्र है जिसमें से 21 ऐसे नक्षत्रों को चुना गया है, जिनमें शामिल हैं, कमल चोपड़ा, डॉ सतीशराज पुष्करणा, सतीश राठी, चित्रा मुद्गल, बलराम अग्रवाल, सिद्धेश्वर, रामयतन यादव, भगवती प्रसाद द्विवेदी, रामनिवास मानव, शंकर पुणतांबेकर, रामकुमार घोटड़, महाश्वेता चतुर्वेदी, डॉ योगेंद्र नाथ शुक्ल, कांता राय,मधुकांत, डॉ सूर्यकांत नागर, योगराज प्रभाकर, अशोक जैन, ज्ञानदेव मुकेश और डॉ सतीश दुबे। इन सब के अलावा सैंकड़ों ऐसे लघु कथाकार नक्षत्र हैं जिनकी चमक से पत्र पत्रिकाएं रौशन हो रही हैं। पुस्तक के दूसरे खंड में जिक्र किए गए 21 नक्षत्रों की दो-दो लघुकथाएं ली गई हैं। पुस्तक के तीसरे खंड में 157 लघु कथाकारों की एक-एक लघुकथा शामिल की गई है। इस तरह ये एक नितांत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई है,जिसे हर नए-पुराने लघु कथाकार के पास अवश्य होना चाहिए तथा इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं के लिए तो ये एक अनुपम संदर्भ ग्रंथ ही है। इस तरह सचमुच सिद्धेश्वर के संपादन तथा ऋचा वर्मा के सह-संपादन में प्रकाशित लघुकथाओं के साहित्याकाश का जाज्वल्यमान नक्षत्र है ये पुस्तक 21वीं सदी की लघुकथाएं!

नीतीश की बहार

कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा न होती तो शायद खाता भी नहीं खुलता, राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस खुद तो डूबती है साथ में गठबंधन करने वाली पार्टियों को भी डुबो देती है, बिहार में तेजस्वी की राजद को डूबोने के बाद राहुल गांधी का अगला टारगेट क्या यूपी के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी होगी?

कृष्ण कुमार चौहान

51 साल पहले 1974 में फिल्म 'रोटी' का ये गीत 'ऐ बाबू ये जो पब्लिक है सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है...हिट हुआ था। जी हां राजनीति में कौन भरोसे लायक है और कौन नहीं ये भी पब्लिक जानती और पहचानती है, लेकिन वंशवादी नेता राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव अथवा तेजस्वी जैसे नेता ये पब्लिक के मूड को समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसलिए लगातार हार पर हार का दीदार कर रहे हैं। ताजा और शर्मनाक हार तो बिहार में हुई है। बिहार में एनडीए की बंपर जीत ने साबित कर दिया कि नकारात्मक राजनीति करने से मतदाता का दिल नहीं जीता जा सकता। बिहार चुनाव ने एक बार फिर साबित किया कि कांग्रेस परजीवी दल है, यदि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा न होती तो शायद खाता भी नहीं खुलता। राहुल गांधी ने ये भी साबित कर दिया कि कांग्रेस खुद तो डूबती है साथ में गठबंधन करने वाली पार्टियों को भी डुबो देती है। बिहार में तेजस्वी की राजद को डूबोने के बाद राहुल गांधी का अगला टारगेट क्या यूपी के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी होगी? राहुल गांधी हों या तेजस्वी और अखिलेश यादव ये वो नेता हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, इनका पार्टी को खड़ा करने में कोई योगदान नहीं है। इसलिए इन्हें पता ही नहीं है कि राजनीति कैसे होती है? सकारात्मक और नकारात्मक राजनीति का क्या प्रभाव होता है? लिहाजा वंशवाद की राजनीति का खेला खत्म होते देश देख रहा है। राहुल गांधी तो वो नेता बन चुके हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है और शतक लगाने की तरफ बढ़ रही है। 2026 में पांच राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस क्या चमत्कार कर पाएगी? ये जल्दी ही पता चल जाएगा। फिलहाल तो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और राहुल की कांग्रेस में घमासान मचा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इन्हें नकारा और नकाम नेता का खिताब दिया जा रहा है।

- **वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, तेजस्वी का 18 नवंबर को मैं बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा जैसे ऐलान का जवाब जनता ने दे दिया, इस चुनाव में जेन जी ने भी राहुल गांधी को बता और जता दिया कि वो सकारात्मक विचारधारा के साथ कदमताल कर रहा है, लिहाजा अब वोट चोरी का विलाप शुरू हो गया है।**
- **बिहार विधानसभा चुनाव में 1951 के बाद दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है, पुरुष मतदाताओं ने 62.98 प्रतिशत तथा महिला मतदाताओं में 71.78 प्रतिशत मतदान किया, आम मतदाता जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है।**

एनडीए की बंपर जीत

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 202 विधानसभा सीटें जीतकर अपना राजनीतिक जलवा-ए-जलाल कायम रखा है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मतदाताओं के भरोसे और नीतीश कुमार के दो दशकों के सुशासन की सफलता को दर्शाती है। एनडीए की यह बंपर जीत जनता के भरोसे की जीत है, यह जीत सरकारी योजनाओं की जनता तक डिलीवर होने की जीत है यानी एनडीए ने एक बड़ा वोट बैंक लाभार्थियों का तैयार कर लिया है। क्योंकि लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए भी बिहार में पसमांदा मुस्लिम समाज ने एनडीए का समर्थन किया जबकि कट्टरपंथी वोट बैंक ने एनडीए को हराने वाले दलों का समर्थन किया। लाभार्थी वर्ग ने इसलिए भी एनडीए को वोट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि एनडीए की सरकार नहीं बनी तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है। इसलिए भी मतदान के सारे रिकार्ड टूट गए या ये कहें कि बिहार की जनता ने पहली बार छप्पर फाड़ मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव में 67.13 प्रतिशत ऐतिहासिक और उच्चतम मतदान हुआ। यह 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदाताओं ने 62.98 प्रतिशत तथा महिला मतदाताओं में 71.78 प्रतिशत मतदान किया। आम मतदाता जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, मोदी राष्ट्रहित में फैसले लेते हैं, जबकि विपक्ष राष्ट्रहित के फैसलों का विरोध करता है।

लाभार्थी नीतीश व मोदी के दीवाने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय योजनाओं में महिला को प्राथमिकता दी है। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्जवला, शौचालय योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना ये वो योजनाएं हैं जिनसे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए योजना का पिटारा खोल रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, खासकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपना छोटा व्यवसाय या आजीविका शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसे वापस नहीं करना होता है। यदि महिलाएं इस राशि से शुरू किए गए काम को सफलता पूर्वक 6 महीने तक चलाती हैं तो उसके प्रदर्शन के आकलन के आधार पर सरकार 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता देती है। चुनाव से पहले 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को पहली किस्त मिल चुकी है। नीतीश कुमार ने ही सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। पंचायत और नगर निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया। छात्राओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे लड़कियों की शिक्षा दर में वृद्धि हुई है। राज्य में शराब बंदी का निर्णय भी महिलाओं के व्यापक समर्थन पर आधारित था। इनके दम पर ही नीतीश कुमार की जदयू ने इस बार के चुनाव में शानदार वापसी की है। विपक्ष का सत्ता विरोधी लहर का शोर, नीतीश की उम्र और राजनीतिक थकान के साथ एनडीए में कमजोर प्रदर्शन को झुठा साबित करते हुए नीतीश ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भाजपा को भी बता दिया कि आखिर किंगमेकर वही हैं और रहेंगे। भाजपा के साथ कदमताल करते हुए जेडीयू 45 सीटों से 85 सीटों पर पहुंच गई है। नीतीश की पार्टी ने 2020 के चुनाव में मात्र 45 सीटें जीती थीं।

गर्दा उड़ा दिया

बिहार में एनडीए को जिस तरह की बंपर जीत मिली उसकी कल्पना तो एनडीए नेताओं ने भी नहीं की थी। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी मान रहे थे कि 160 के आसपास उन्हें सीटें मिलेंगी। यह बयान कई बार टीवी न्यूज चैनलों पर प्रसारित भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से बिहार में मतदान हुआ और जो नतीजे आए उससे एनडीए का जश्न दोगुना होना स्वभाविक है। चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री, संगठन से जुड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रचंड जीत जनता के अटूट विश्वास की है, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। जय छठी मईया के जयकारे के साथ अपनी बात शुरू करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम एनडीए के लोग तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। चुनाव में जब मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो राजद नेता इसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था, लेकिन मैं फिर कहना चाहता कि कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी। बिहार के लोगों ने विकसित व समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एनडीए को लैंडस्लाइन जीत दी।

यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मतदाताओं के भरोसे और नीतीश कुमार के दो दशकों के सुशासन की सफलता को दर्शाती है, एनडीए की यह बंपर जीत जनता के भरोसे की जीत है, यह जीत सरकारी योजनाओं की जनता तक डिलीवर होने की जीत है यानी एनडीए ने एक बड़ा वोट बैंक लाभार्थियों का तैयार कर लिया है।

महागठबंधन की हार की वजह

बिहार की जनता ने एक बार फिर लालू यादव के जंगलराज पर ठप्पा लगाया है। एनडीए भी प्रचार के दौरान जनता को जंगलराज की याद दिलाता रहा। पूरे चुनाव में शायद ही कोई ऐसी रैली रही हो जिसमें एनडीए ने बिहार को जंगलराज की याद ना दिलाई हो। जनता को जंगलराज की बातें भले याद न हों लेकिन राजद पर लगा जंगलराज का ठप्पा, उसकी छवि पर बड़ा डेंट बना। पहले चरण के लिए जहां नामाकंन हो रहे थे वहीं महागठबंधन सीटों को लेकर उलझा हुआ था। राजद, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी के बीच एक दर्जन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी। कुटुंबा, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा जैसी कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में संघर्ष करते नजर आए। महागठबंधन का कंफ्यूजन वोटों को भी कंफ्यूज करता रहा। तेजस्वी ने हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन यह वादा लोगों के गले से नीचे नहीं उतरा और इस वादे की व्यवहारिकता पर सवाल उठते रहे। एनडीएन ही नहीं जनता ने भी तेजस्वी से नौकरी देने का ब्लूप्रिंट मांगा लिया लेकिन ब्लूप्रिंट होता तो देते। लिहाजा तेजस्वी का यह दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी की कुछ सभाएं रद्द हो गई थीं। इसके बाद खबरें चलने लगी कि चुनाव के बाद मुकेश सहनी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया था। हीर की एक प्रमुख वजह राजद का 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना भी रहा, जिससे पार्टी की जातिवादी छवि और अधिक मजबूत हुई। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण अहम होते हैं। यादव भले ही राजद का कोर वोट बैंक हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टिकट देने से अन्य जातियों, विशेषकर अगड़े और अति पिछड़े वर्गों में असंतोष पनपा। जिससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन की मुस्लिम-परस्त छवि ने भी नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम बहुल सीटों पर भले ही राजद और उसके सहयोगियों को बढ़त मिली हो, लेकिन राज्यव्यापी स्तर पर इसका उल्टा असर पड़ा। यहां तक कि कई क्षेत्रों में यादव मतदाता भी राजद से दूर नजर आए। तेजस्वी यादव द्वारा सत्ता में आने पर वक्फ बिल लागू न करने का वादा भी विवादों में रहा, जिससे यादव मतदाता छिटक गए। रही सही कसर महागठबंधन के नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी कर दी। राहुल गांधी ने छठ पूजा को ड्रामा बताकर बिहार की आस्था पर चोट पहुंचाई। बिहारियों को अपमानित करने वाले नेताओं को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच देने का जवाब बिहार की जनता ने दे दिया। वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, तेजस्वी का 18 नवंबर को मैं बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा जैसे ऐलान का जवाब जनता ने दे दिया। इस चुनाव में जेन जी ने भी राहुल गांधी को बता और जता दिया कि वो सकारात्मक विचारधारा के साथ कदमताल कर रहा है। लिहाजा अब वोट चोरी का विलाप शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर हार का ठिकरा फोड़ने का कार्यक्रम चालू है। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया था कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी रोकने में भी फेल हो गए।

बेटियां बनी विश्व विजेता

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम को प्राइज मनी के अलावा मेगा टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों की फीस भी मिलेगी, यानी प्लेइंग-11 में खेलने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच 6 लाख और बाहर बैठने वाले को 3 लाख फीस मिलेगी, तीनों स्त्रोतों से मिलने वाली रकम को जोड़ा जाए, तो हर खिलाड़ी के हिस्से में करीब पांच करोड़ रुपये आएंगे।

उत्तरांचल दीप डेस्क

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल का इंतजार खत्म किया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप-2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके बाद तो भारतीय बेटियों पर धन की वर्षा होने लगी। आईसीसी द्वारा करीब 38 करोड़ का इनाम दिया गया है जबकि बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया। यह राशि खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों और सिलेक्टर्स में बांटी जाएगी। ये वही बेटियां हैं जो कभी भारत में महिला क्रिकेट की वित्तीय स्थित से संघर्ष कर रही थी। भारतीय महिला क्रिकेटर्स का शुरूआती समय काफी संघर्ष वाला था। एक समय था जब इस खेल को जिंदा रखने के लिए पैसे नहीं, जुनून हुआ करता था। 2005 में वनडे विश्व कप में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, तब खिलाड़ियों को एक मैच खेलने के लिए सिर्फ 1000 रुपये फीस मिलती थी। इसका खुलासा भारत की पूर्व कप्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे सफल महिला बल्लेबाज मिताली राज ने किया था। मीडिया को दिए इंटरव्यू में मिताली ने खुलासा किया था कि उस वक्त हमारे पास सालाना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे, हमारे लिए मैच फीस जैसी कोई चीज भी नहीं थी। 2017 में भी मिताली की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। मिताली का कहना था कि 2006 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेट को अपने हाथ में लिया। इससे बहुत पहले महिलाओं का क्रिकेट सीमित संसाधनों के सहारे चलता था। 2006 से पहले भारत में महिला क्रिकेट का संचालन वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था। खिलाड़ी अक्सर ट्रेन के सामान्य डिब्बों में सफर करते थे। लेकिन अब भारत में महिला क्रिकेट काफी बदल चुका है। बीससीआई ने महिलाओं की टी-20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट, वुमेंस प्रीमियर लीग की शुरूआत की और 2022 में ऐतिहासिक ऐलान हुआ। जिसके बाद से महिला और पुरुष क्रिकेटर दोनों को समान फीस मिलती है। एक टेस्ट के 15 लाख, वनडे मैच के लिए 6 लाख और टी-20 इंटरनेशनल के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं। अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम को प्राइज मनी के अलावा खिलाड़ियों को मेगा टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों की फीस भी मिलेगी। इसके तहत प्लेइंग-11 में खेलने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच 6 लाख और बाहर बैठने वाले को आधी यानी 3 लाख फीस मिलेगी। इसी तरह अगर तीनों ही स्त्रोतों से मिलने वाली रकम को जोड़ लिया जाए, तो हर खिलाड़ी के हिस्से में करीब पांच करोड़ रुपये आएंगे। इससे अलग कुछ निजी कंपनियां और राज्य सरकारें भी अपने-अपने खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम का ऐलान कर रही हैं। ये सब जय शाह के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद संभव हो पाया। मुंबई में फाइनल मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर जय शाह के पैर छूना चाहती थी, लेकिन शाह ने पैर नहीं छूने दिए।

भारतीय महिला टीम की जीत पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, इंडिया को जीत के लिए मुबारकबाद, इंडिया की लड़कियां अच्छा खेलीं और जीत की असली हकदार थी, उन्होंने लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया, टीम इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग भी काफी अच्छी थी।

क्योंकि हिंदू धर्म में लड़की या स्त्री से पैर नहीं छुवाए जाते हैं। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। हिंदू धर्म में महिला को पूजने योग्य माना जाता है। हालांकि महिलाओं को बड़े-बुजुर्गों के पैर छूते देखा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार महिलाएं पिता, गुरु और बुजुर्गों के ही पैर छूती आई हैं। जय शाह और हरमनप्रीत की उम्र लगभग समान है, ऐसे में अगर शाह भारतीय कप्तान से पैर छुवा लेते, तो इसे स्त्री अपमान की दृष्टि दे देखा जाता। ऐसा करने पर जय शाह की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी हुई। कहा गया कि जय शाह ने पैर ना छुवाते हुए नारी शक्ति का सम्मान किया। जो उनके अच्छे संस्कारों को प्रदर्शित करता है।

जय शाह ने बढ़ाया उत्साह

राजनीतिक घरानों के दो चिरागों यानी कांग्रेस के राहुल गांधी और भाजपा के जय शाह की तुलना की जाए तो 54 साल के राहुल गांधी एक नाकाम, विफल और कांग्रेस बेड़ा गर्क करने वाले नकारा नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं, इसके विपरीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र 37 वर्ष के जय शाह ने जिम्मेदारी संभालते ही भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया है। चाहे वह पुरुष टीम हो या महिला टीम हो। फिर भी कांग्रेसी और विपक्षी दल जय शाह की आलोचना करने से बाज नहीं आते हैं। विपक्षी नेता कहते रहते हैं कि बिना क्रिकेट खेले वह बीसीसीआई के अध्यक्ष कैसे बन गए हैं? कैसे आईसीसी के अध्यक्ष बन गए? लेकिन शरद पवार, वैभव गहलोत, लालू प्रसाद यादव और राजीव शुक्ला की कोई आलोचना नहीं करता कि वो कैसे बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई और राज्यों के क्रिकेट संघों के अध्यक्ष रहे हैं? राजीव शुक्ला तो अभी भी बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष हैं। बात जयशाह और क्रिकेट की है तो बताते हैं कि जय शाह ने क्रिकेट के लिए कौन से शानदार कदम उठाए और महिला क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाने के लिए हर सुविधा दी। जिससे उत्साहित भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी। 7 बार वर्ल्ड कप विजेता रही आस्ट्रेलिया को भारत की बेटियां ने पराजित किया और दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप जीता। दुनिया में महिला क्रिकेट विश्व कप का इतिहास 52 वर्ष पुराना है और इत्तेफाक देखिए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 रनों से ही दक्षिण अफ्रीका को हराया और भारत का विश्व विजेता बनने का इंतजार 2025 में खत्म किया। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम विश्व विजेता बन गई। महिला टीम की यह पहली आइसीसी ट्राफी है। जबकि 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में पुरुष टीम ने वनडे विश्व कप जीता था। अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में बेटियों ने भी विश्व चैंपियन का तमगा हासिल कर लिया है। भारतीय बेटियों की यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वनडे विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 297 रन का स्कोर खड़ा किया था जो महिला वनडे विश्व कप फाइनल का दूसरा सर्वोच्च स्कोर था, जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर आलआउट हो गई। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने 101 रन की शतकीय पारी खेली, पर टीम को जीत नहीं दिला पाई।

7 बार की विश्व विजेता आस्ट्रेलिया को भी हराया

जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफइनल में सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड रनों से हराकर फाइनल में पहुंची है तब से यही उम्मीद थी कि हमारी बेटियां विश्व कप विजेता बनेंगी। महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1973 में हुई। तब से भारत दो बार 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचा मगर चैंपियन नहीं बना। महिला क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों का दबदबा ऐसा रहा कि विश्व खिताब सात बार ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में और चार बार इंग्लैंड के हिस्से में गया। 2000 में केवल एक बार न्यूजीलैंड ने विश्व कप पर कब्जा करने में सफलता पाई थी। यह तीसरा मौका था जब भारत की महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची थी। इसका श्रेय जेमिमा रोड्रिग्स (127 नाबाद) और कप्तान हरमनप्रीत (89 रन) को दिया जाना चाहिए जिनकी तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत और दूसरे खिलाड़ियों की छोटी लेकिन उपयोगी पारियों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को हराया था। इससे एक बार फिर 2017 की याद ताजा हो गई जब हरमनप्रीत ने सेमी फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 171 रनों की नाबाद पारी खेली थी और टीम फाइनल में पहुंच गई थी। इस बार भारतीय महिला टीम के तेवर देखकर लग रहा था कि भारतीय बेटियां वर्ल्ड कप को अपने हाथों में जरूर उठाएंगी। वर्ल्ड कप जीतने के लिए वास्तव में भारत में महिला क्रिकेट टीम ने एक लंबी दूरी तय की है। सबसे पहले तो बेटियों में यह विश्वास जगाने में समय लगा कि वे भी लड़कों की तरह शानदार क्रिकेट खेल सकती हैं। क्योंकि महिला क्रिकेट की उपेक्षा का क्या हाल था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत में महिला टीमों को छोटे स्टेडियम दिए जाते थे। 2013 में जब महिला क्रिकेट मैच का प्रसारण शुरू हुआ तो स्टेडियम में स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में बैठाया गया था। कई बार ऐसी भी खबरें आईं कि महिला क्रिकेट के मुकाबले की जगह अंतिम समय में बदल दी गई। लेकिन जैसे-जैसे महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि वे किसी से कम नहीं हैं तो दर्शकों को महिला क्रिकेट रास आने लगा।

- **भारत दो बार 2005 व 2017 में फाइनल में पहुंचा पर चैंपियन नहीं बना, महिला क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों का दबदबा ऐसा रहा कि विश्व खिताब सात बार ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में और चार बार इंग्लैंड के हिस्से में गया, 2000 में न्यूजीलैंड ने विश्व कप पर कब्जा किया था।**
- **2005 में वनडे विश्व कप में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, तब खिलाड़ियों को एक मैच खेलने के लिए सिर्फ 1000 रुपये फीस मिलती थी, इसका खुलासा भारत की पूर्व कप्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे सफल महिला बल्लेबाज मिताली राज ने किया था।**

पाकिस्तान ने तारीफ की

भारत की बेटियों के विश्व कप विजेता बनने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है। उनका परफॉर्मेंस सॉलिड है। वे लोग रिलैक्स रहते हैं, ये नहीं था कि कोई डेस्पेरेट सिचुएशन थी। यह भारत की एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। वे लोग एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और रिजल्ट्स देख लें आपके सामने है। ये किसी भी यंगस्टर के लिए सीखने की बात है कि आप जिस वजह से क्रिकेट खेलते हैं वो मत भूलें। हम सब क्रिकेट इसलिए खेले हैं कि हमें इससे प्यार है, मोहब्बत है। हम स्पोर्ट को एंजॉय करते हैं। भारतीय महिला टीम की जीत पर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, इंडिया को जीत के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद। इंडिया की लड़कियां अच्छा खेलीं और जीत की असली हकदार थी। उन्होंने लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया। टीम इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग भी काफी अच्छी थी। उन्होंने इसकी मदद से मेक श्योर किया कि वे मैदान में पूरे एटीट्यूड के साथ आए। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि मुझे ये अच्छा लगा कि टीम इंडिया ने कॉम्प्रेहेंसिवली जीत हासिल की है। उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। उन्होंने खुद पर काफी इन्वेस्ट किया है।

भारतीय बेटियों को बधाई

2025 वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी है जबकि 5 नवंबर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से मिठाई खिलाकर बधाई दी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे एक अभिभावक की तरह खूब बातें की। पहली बार महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह सहित तमाम नेताओं ने बधाई दी है। सोशल मीडिया पर महिला क्रिकेट टीम के सम्मान में तमाम पोस्ट की जा रही हैं। बेटियों को विश्व विजेता बनने पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई अपने हिसाब से पोस्ट कर बधाई दे रहा है।

1000 करोड़ की बिजली चोरी

हरिद्वार के गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल के बिजली घर के बाहर से पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर पूछताछ की तो बिजलीघर में लगे वासू स्टील फैक्ट्री के मीटर में छेड़छाड़ की बात सामने आई, विभागीय टीम ने जांच की तो मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी किए जाने की पुष्टि हुई, लिहाजा टीम ने मीटर सील कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।

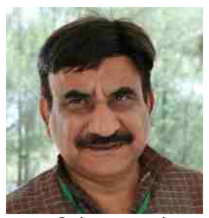

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

यूं ही नहीं उत्तराखंड पावर कारपोरेशन घाटे में चल रहा है। छोटे से इस पहाड़ी राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के दावे सरकारें करती रही है। लेकिन जिस राज्य में 1000 करोड़ रुपये की सालाना बिजली चोरी होती हो वो कैसे ऊर्जा प्रदेश बन सकता है? बिजली चोरी का सनसनीखेज खुलासा होने पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसी जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा बिजली चोरी औद्योगिक क्षेत्रों व मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हो रही है। जबकि राज्य के बिजली उपभोक्ता जो ईमानदारी से नियमित रूप से अपने बिजली बिलों का भुगतान करते हैं, वो इस चोरी का खामियाजा उठा के लिए विवश हैं, जिससे उन्हें महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये की बिजली चोरी का वित्तीय बोझ वहन करने में असमर्थ है, लिहाजा इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। उत्तराखंड के सिर्फ आठ शहरों का ही एटी एंड सी लॉस राज्य के अन्य 114 शहरों पर भारी पड़ रहा है। इन आठ शहरों में 27 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत तक लाइन लॉस हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी और बिजली बिलों का भुगतान न करना है। इस नुकसान के मामले में पहाड़ का सिर्फ एक शहर जोशीमठ और अन्य सात शहरों में हरिद्वार जिले के लक्सर, लंढौरा, मंगलौर और ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, खटीमा, गदरपुर, जसपुर व खटीमा शहर शामिल हैं। खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह नगर है। बिजली चोरी का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के एटी एंड सी लॉस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का ब्यौरा अपने विस्तृत टैरिफ ऑर्डर में जारी किया। बताया गया है कि सबसे ज्यादा वित्तीय एवं ट्रांसमिशन में घाटा हो रहा है। इसके साथ ही इन शहरों में सबसे अधिक पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। इसका सीधा खामियाजा उत्तराखंड के 114 शहरों की जनता को महंगी बिजली के रूप में भुगतना पड़ रहा है। 2021-22 में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल) का कुल डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 14.70 प्रतिशत रहा। 2022-23 में ये बढ़ कर 16.39 प्रतिशत पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये कुछ कम होकर 15.63 प्रतिशत पर आ गया था।

यूपीसीएल करा रहा बिजली चोरी

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल) के 46 डिवीजन हैं। इन 46 डिवीजनों में 19 पहाड़ी क्षेत्र में और 27 मैदानी क्षेत्र में हैं। इसी तरह कुल 122 सब डिवीजन हैं। इनमें 51 पहाड़ी क्षेत्र में और 71 मैदान क्षेत्र में हैं। विधि सदस्य नियामक आयोग की रिपोर्ट है कि टैरिफ ऑर्डर में यूपीसीएल को सख्त लहजे में कह दिया गया है कि हर हाल में लाइन लॉस को कम किया जाए। इसके लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी। नियमित रूप से कार्यों का ब्योरा लिया जाएगा। एनर्जी ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा। ओ एंड एम और कैपिटल मद में होने वाले खर्चों पर भी नजर रखी जाएगी। उत्तराखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए यूपीसीएल द्वारा सख्त अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लाइन लॉस को कम किया जा सके। यूपीसीएल ने तकनीक का सहारा लेकर ये पता लगाना शुरू कर दिया है कि किस ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी हो रही है। इसके लिए ड्यूल मीटर लगाए गए हैं जिससे हर उपभोक्ता की जानकारी अब विभाग के पास रहती है कि बिजली चोरी कहां हो रही है। इस तकनीक के बाद पता चला कि गदरपुर में 30.58 प्रतिशत, जसपुर 27.00 प्रतिशत, खटीमा 53.00 प्रतिशत, लक्सर 27.00 प्रतिशत, लंढौरा 69.40 प्रतिशत, मंगलौर 47.62 प्रतिशत, सितारगंज में 27.25 प्रतिशत का लाइन लॉस हुआ है। इसमें गौर करने की बात है कि ये सभी उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र के डिविजन है और इनमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाके है। जहां बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाने से उत्तराखंड पावर कारपोरेशन बचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जब-जब मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बिजली चोरों के खिलाफ कारवाई हुई भीड़ ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की टीम पर संगठित होकर हमला किया है। हाल ही में हरिद्वार में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन ने हिम्मत दिखा कर पिरान कलियर क्षेत्र में 23 बिजली चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया, ये सभी मुस्लिम है। हरिद्वार जिले में ही गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल के बिजली घर में वासू स्टील फैक्ट्री के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की पुष्टि हुई। जांच के बाद यूपीसीएल ने एसडीओ व प्रभारी अधिशासी अभियंता गुलशन बुलानी और मंगलौर के जेई अनुभव सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं उपनल कर्मी अकरम अली समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

स्टील फैक्ट्री में बिजली चोरी

दरअसल कुछ दिन पहले गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल के बिजली घर के बाहर से पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर पूछताछ की तो बिजलीघर में लगे वासू स्टील फैक्ट्री के मीटर में छेड़छाड़ की बात सामने आई। यूपीसीएल की मापक टीम ने जांच की तो मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी किए जाने की पुष्टि हुई। लिहाजा टीम ने मीटर सील कर दिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इस मामले में यूपीसीएल के उपनल के कर्मचारी अकरम अली समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें दो फैक्ट्री के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने लंढौरा के एसडीओ और विद्युत वितरण खंड रुड़की के प्रभारी अधिशासी अभियंता गुलशन बुलानी को निलंबित कर दिया और मुख्य अभियंता विद्युत वितरण को रुद्रपुर क्षेत्र से संबद्ध कर दिया। उनकी जगह सहायक अभियंता हरिद्वार अमित तोमर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीओ मंगलौर जेई अनुभव सैनी को निलंबित कर मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी से संबद्ध किया है। उनकी जगह एसडीओ झबरेड़ा मोहम्मद रिजवान को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक एसडीओ गुलशन बुलानी को आखिर अधिशासी अभियंता का प्रभार कैसे दिया गया था? हालांकि विद्युत चोरी की जांच के लिए निदेशक परिचालन ने मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें एक अधीक्षण अभियंता व एक डिप्टी सीएफओ हैं। इनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव का कहना है कि अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर जांच बैठा दी गई है। पूरी एनर्जी अकाउंटिंग कराई जाएगी। कहीं भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाएगी तो सीधे कार्रवाई होगी। एमडी ने आदेश दिया है कि रुड़की, भगवानपुर समेत पूरे क्षेत्र में उच्च बिजली खपत वाली सभी स्टील फैक्ट्री और अन्य उद्योगों का एनर्जी अकाउंटिंग ऑडिट किया जाएगा। इससे स्पष्ट होगा कि बिजली की किस स्तर पर खपत हो रही है। कहीं किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी पकड़ में आई तो उस हिसाब से भी कार्रवाई होगी। यूपीसीएल के एमडी से लेकर निदेशक तक बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई करने के बड़े-बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन गुरुकुल नारसन स्थित वासू स्टील फैक्टरी के मीटर में छेड़छाड़ करने पर फैक्ट्री के कर्मचारियों पर तो बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन मालिक का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिजली चोरी करने से कर्मचारियों को कोई लाभ हो रहा था या बिजली चोरी से फैक्टरी मालिक मुनाफा कमा रहा था? करोड़ों की बिजली चोरी का फायदा तो सीधे सीधे फैक्टरी मालिक को हुआ है लिहाजा उसके खिलाफ पहले एक्शन होना चाहिए था। इसलिए ही उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड विवादों में रहता है।

यूपीसीएल के एमडी पर गंभीर आरोप

यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव पर कई गंभीर आरोप हैं। जिनकी जांच भी हुई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई न ही अनिल यादव के खिलाफ काई कार्रवाई हुई। विवादों में रहने वाले अनिल यादव के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर सरकार ने कुछ महीने पहले ही उन्हें सेवा विस्तार का तोहफा दिया जिसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था। सेवा विस्तार को काफी समय तक गोपनीय भी रखा गया था। इससे सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में बड़े-बड़े उद्योगों के साथ ही हरिद्वार जिले के मुस्लिम बाहुल्य पिरान कलियर में बिजली चोरी के एक-दो नहीं दर्जनों चोरी के मामले सामने आए हैं। देहरादून यूपीसीएल विजिलेंस और रूड़की विद्युत विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कलियर में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया तो बिजली चोरी का खुलासा हुआ। संयुक्त टीम ने विभिन्न मुस्लिम मोहल्लों में छापेमारी कर 23 घरों में बिजली चोरी पकड़ी हैं। यूपीसीएल की एसडीओ अनिता सैनी का कहना है कि रूड़की क्षेत्र के कलियर में विद्युत चोरी के 23 मामले पकड़े गए हैं। बिजली चोरी करने वाले अफजाल पुत्र शौकत, गुलशर पुत्र वहीद, समून पुत्र मशरूर, जावेद पुत्र इकबाल, जमशेद पुत्र सद्दु, रफीक पुत्र शाहद, कय्यूब पुत्र मुदा, विशाल पुत्र गुलजार, शाह मंजर पुत्र हसमत, शाकिब पुत्र शमशाद, मुस्लिम पुत्र असगर, आजम पुत्र मोहम्मद अहमद, दानिश पुत्र रशीद प्रधान, सुहैल पुत्र इमरान, नसीम पुत्र हासिम, परवेस पुत्र शराफत अली, छोटा पुत्र शराफत, मनुवार पुत्र इंतजार, नफीस पुत्र रहीस, मेहरबान पुत्र भूरा, दानिश पुत्र नजीर, अरशद पुत्र अख्तर, फययाज पुत्र जहांगीर आदि के खिलाफ स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसी साल हल्द्वानी के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया था, इस दौरान झुग्गियों में रहने वाले परिवारों द्वारा बिजली चोरी करने की जानकारी मिली थी, पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि इलाके का लाइनमैन बिजली चोरी कराता है, बदले में पूरी बस्ती से वसूली करता है। हल्द्वानी पुलिस ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को बिजली चोरी की जानकारी दी, अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की लीपापोती कर लौट गए थे। जबकि हल्द्वानी के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है।

- **इसी साल हल्द्वानी के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया था, इस दौरान झुग्गियों में रहने वाले परिवारों द्वारा बिजली चोरी करने की जानकारी मिली थी, पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि इलाके का लाइनमैन बिजली चोरी कराता है, बदले में पूरी बस्ती से वसूली करता है।**
- **यूपीसीएल को लाइन लॉस से नुकसान पहुंचाने के मामले में पहाड़ का सिर्फ एक शहर जोशीमठ है जबकि अन्य सात शहरों में हरिद्वार जिले का लक्सर, लंढौरा, मंगलौर और ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, खटीमा, गदरपुर, जसपुर व खटीमा शहर शामिल हैं, इन शहरों में सबसे ज्यादा पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है।**

उत्तराखंड के सिर्फ आठ शहरों का ही एटी एंड सी लॉस राज्य के अन्य 114 शहरों पर भारी पड़ रहा है, मैदानी क्षेत्र के आठ शहरों में 27 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत तक लाइन लॉस हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी और बिजली बिलों का भुगतान न करना है।

25 वर्षों में यूके ने क्या पाया

अलग राज्य बनने से पहाड़ का जंगल, जमीन, जवानी और पानी राज्य के विकास के काम आएगा, लेकिन जंगलों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, खनन से धरती खोखली हो रही है और पहाड़ की जवानी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर हैं, पलायन की वजह से गांव खाली हो चुके हैं।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल राज्य बना, जिसका नाम 2007 मे बदलकर उत्तराखंड रखा गया। नवंबर 25 में उत्तराखंड राज्य 25 साल का युवा प्रदेश बन गया है। ऐसे में पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में क्या बदलाव आए हैं। उत्तराखंड ने क्या हासिल किया और क्या हासिल करना था? क्या खोया जिसका सदैव प्रदेशवासियों को मलाल रहेगा? क्योंकि मैदानी जिलों में शहरीकरण और विकास हुआ तो पहाड़ों पर विकास के नाम पर बरसात में आपदाएं बढ़ी हैं। इस साल गांव के गांव बादल फाड़ बारिश से तबाह और बर्बाद हो गए। कई गांवों का तो नाम निशान तक नहीं रहा। पहाड़ी राज्यों के लोग मान रहे हैं कि उत्तराखंड अलग राज्य बन गया ठीक है, लेकिन बेहतर होता कि यह यूपी से अलग न होता, क्योंकि जिस तरह से राजधानी सहित प्रदेश के 13 जिलों में डेमोग्राफी चेंज हुई, गुंडागर्दी और क्राइम का ग्राफ बढ़ा है वो डराने वाला है। 25 वर्षों में भले ही सड़कें न बनी हों, स्कूल और अस्पताल न बने हों लेकिन अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे धड़ल्ले से बने हैं। वन विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं। अलग राज्य बनाने से क्या चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की तस्वीर बदली है? जिस राज्य में कभी लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे उस पहाड़ी राज्य में चोरी, लूट, रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराध होने लगे हैं। राजधानी से लेकर धर्मनगरी और पर्यटन क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति सैलानियों को कचोटती है। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल आता है कि अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों के क्या सपने टूट गए? क्योंकि जिस सपने को लेकर आंदोलन हुआ था वो 25 साल बाद भी अधूरा है। पहाड़ का जंगल, जमीन, जवानी और पानी राज्य के विकास के लिए काम आएंगी, लेकिन जंगलों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, भूमि खनन से धरती खोखली की जा रही है और पहाड़ की जवानी यानी युवा बेरोजगारी और भ्रटाचार को लेकर सड़कों पर हैं। पलायन की स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हुई है। गांव के गांव खाली हो चुके हैं। दुर्गम गांवों में आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। सड़क नहीं है तो चिकित्सा और शिक्षा भी नहीं है। कई बार मरीजों को चारपाई पर ले जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद तो हैं पर डॉक्टर नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि राज्य बनने के बाद बहुत से लोगों की उद्योग लगाने और अच्छी नौकरी पाने से आजीविका चल रही है। जो कभी जिला पंचायत का चुनाव नही जीते वो मंत्री बन गए। जो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीते वो ब्लाक प्रमुख बन गए। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम 2019 शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया।

आंदोलनकारियों की दशा

9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। सरकार द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन आंदोलन से हासिल हुए उत्तराखंड राज्य में जिन लोगों ने राज्य गठन के लिए लाठी डंडे और गोलियां खाई, वे लोग आज खुद का महत्व खत्म होने का दर्द बयां करते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे भी रहे, जिन्होंने राज्य आंदोलन के समय लड़ाई लड़ी और वे पुलिस से संघर्ष करते हुए घायल हो गए। उन घायलों में कुछ आंदोलनकारी ऐसे हैं, जो राज्य गठन के 25 साल होने पर भी बिस्तर पर ही हैं। इन शैयाग्रस्त राज्य आंदोलनकारियों को जिंदा शहीद कहा जाता है। लंबे समय से राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि शैयाग्रस्त राज्य आंदोलनकारियों का इलाज कराया जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। शैयाग्रस्त जिंदा शहीदों में देहरादून के प्रगति विहार निवासी अमित ओबेरॉय भी शामिल हैं। अमित ओबेरॉय 46 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन 30 वर्षों से बिस्तर पर एक पैरालाइज पेशेंट का जीवन बसर करने का विवश हैं। 16 वर्ष की आयु में वो अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों की जमात में बढ-्चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे तभी यूपी पुलिस की बर्बता के कारण अमित ओबेरॉय घायल हुए और उनकी गर्दन से नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया। इसलिए आज वो शारीरिक रूप में निष्क्रिय हैं।

25 साल का युवा उत्तराखंड 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्जदार हो चुका है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास की रफ्तार को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार को पहाड़ी जिलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

कर्ज का बोझ बढ़ा

27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड अब अपनी रजत जयंती मना रहा है। 25 सालों की यात्रा में यह राज्य कई सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी मोर्चों पर बदलाव का गवाह बना है। इन वर्षों में राज्य का वित्तीय ढांचा न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि विकास की रफ्तार ने इसे देश के तेजी से आगे बढ़ते राज्यों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड का बजट महज साढ़े 4 हजार करोड़ रुपये था। आज यह आंकड़ा बढ़कर एक लाख एक हजार करोड़ रुपये से भी ऊपर पहुंच गया है। 25 वर्षों में राज्य की जीडीपी 14,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख 29 हजार करोड़ रुपये पहुंच गई है जबकि प्रति व्यक्ति आय का आकंड़ा चौकाने वाला है। यानी प्रति व्यक्ति आय 15 हजार रुपये से बढ़कर 2 लाख 74 हजार रुपये पहुंच गई है। बैंकिंग, आईटी और व्यापारिक सेवाओं ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत से ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। यह आंकड़ा इसलिए भी सुखद है क्योंकि हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय 2,57,212 है, यानी उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिमाचल से आगे निकल चुका है। हालांकि आर्थिक विकास के साथ छोटे से पहाड़ी राज्य पर कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ा है। यानी 25 साल का युवा उत्तराखंड अब लगभग 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्जदार हो चुका है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास की रफ्तार को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार को पहाड़ी जिलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी का योगदान 2000-01 में 30.99 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 9.83 प्रतिशत रह गया है। फिर भी कृषि और बागवानी राज्य की मुख्य आजीविका स्रोत बना है। सच ये भी है कि पूरी तरह मौसम पर आधारित पहाड़ की खेती से नई पीढ़ी मुंह मोड़ चुकी है। इस लिए बंजर जमीन का रकवा लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में बासमती चावल देशभर में प्रसिद्ध था, लेकिन इसके उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। हालांकि फल और सब्जी उत्पादन इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इन फसलों को जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ मैदानी क्षेत्र को छोड़ दें तो उत्तराखंड को गन्ना बेल्ट नहीं कहा जा सकता। मैदानी क्षेत्र की सोना उगलने वाली तराई वाले सितारगंज, पंतनगर, रुद्रपुर, किच्छा, हरिद्वार जिले की कृषि योग्य भूमि पर औद्योगिक इकाइयां खड़ी हो गई। इसलिए भी खाद्यन्न उत्पादन में उत्तराखंड पिछड़ा है। सर्विस सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बना है। चारधाम यात्रा, नैनीताल-मसूरी और जिम कॉर्बेट ने पर्यटन को मजबूती दी है। उत्तराखंड के औद्योगिक केंद्र हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई ने राज्य की आर्थिक तस्वीर बदली है। 2000 में उद्योग का योगदान 18.55 प्रतिशत था, जो बढ़कर दोगुना से ज्यादा 43.46 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ऑटोमोबाइल फार्मास्युटिकल्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। जबकि उत्तराखंड की फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है।

अपराध के आंकड़े लगातार बढ़े

उत्तराखंड में बीते 25 सालों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वैसे कभी ये माना जाता था कि देवभूमि में अपराध न के बराबर है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 2023 में आई एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में महिला व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले में नंबर वन राज्य रहा है। राज्य में 2023 व 2024 की तुलना 2025 के अप्रैल माह तक के रिकॉर्ड की नजर से देखे तो 2025 में अप्रैल महीने तक अपराध के 4980 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें डकैती, लूट ,वाहन लूट, चेन स्नेचिंग, गृह भेदन, वाहन चोरी, चोरी, हत्या, फिरोती के लिए अपहरण, हत्या के लिए अपहरण, महिला व्यपहरण तथा अन्य अपहरण, दहेज हत्या, बलात्कार और अन्य बीएनएस की धाराओं के मामले हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 5098 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। जो 2024 में बढ़कर 5161 हो गए थे। 2025 में अप्रैल तक सिर्फ चार महीनों में 4980 मामले दर्ज किए जा चुके थे। इन सभी मामलों में महिला अपराध से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई। 252 बलात्कार की घटनाएं हुई, महिला अपहरण के मामले 158 दर्ज किए गए अन्य अपहरण के मामले 50 दर्ज किए गए हत्या के 60 केस दर्ज किए गए। वाहन चोरी के 372 केस शामिल हैं। जबकि 2024 में 5161 आपराधिक केस दर्ज किए गए जिसमें बलात्कार के मामले 271 केस दर्ज हुए। यानी बलात्कार के केस 2023 से 2024 में ज्यादा हुए। महिला व्यपहरण के 175 केस दर्ज किए गए जो 2023 के मुकाबले ज्यादा थे। अन्य अपहरण के मामले 48 दर्ज किए गए। 2024 में 66 हत्या के केस दर्ज किए गए। चोरी के मामलों में 426 मामले दर्ज किए गए। वाहन चोरी के मामलों में 497 मामले दर्ज किए गए और यह भी 2023 से ज्यादा थे। अप्रैल 2025 तक 4980 केस दर्ज किए गए। पिछले दोनों सालों की तुलना में देखे तो 2025 में 334 बलात्कार के केस दर्ज किए गए, जो दोनों सालों की तुलना में बेहद चिंताजनक हैं। महिला व्यपहरण के 196 मामले दर्ज हुए जो पिछले दो सालों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। वाहन चोरी के 377 केस, चोरी के 343 केस, अप्रैल 2025 तक हत्या के 59 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2023-24 में 408 बालक व 802 बालिकाएं कुल 1205 किशोर लापता हुए हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है। इनमें से पुलिस 276 को ही बरामद कर पाई। इनमें 128 बालक और 148 बालिकाएं हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि उत्तराखंड में चोरी के मामलों में रिकवरी दर 52 फीसदी रही है जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। इसके अलावा साइबर ठगी में भी रिकवरी के मामले में उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उत्तराखंड पुलिस इस मामले में देश में छठे नंबर पर है। सालभर में साइबर पीड़ितों के 47.2 करोड़ रुपये वापस कराने में पुलिस सफल रही। पुलिस का दावा है कि महिला संबंधी अपराधों के मामले में सभी पुलिस अधिकारियों खासकर महिला पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी गई है। ताकि कोई भी अपराधी सबूत के अभाव में बच न सके। ●

- **कुछ लोगों का मानना है कि राज्य बनने के बाद बहुत से लोगों की उद्योग लगाने और अच्छी नौकरी पाने के बाद आजीविका चल रही है, जो लोग कभी जिला पंचायत का चुनाव नही जीते वो मंत्री बन गए, जो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीते वो ब्लाक प्रमुख बन गए।**
- **16 वर्ष की आयु में अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों की जमात में शामिल अमित ओबेरॉय 30 वर्षो से शैयाग्रस्त हैं, वो आंदोलनकारियों के साथ थे तभी यूपी पुलिस की बर्बता के कारण अमित ओबेरॉय घायल हुए और उनकी गर्दन से नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया, इसलिए आज तक वो शारीरिक रूप में निष्क्रिय हैं।**

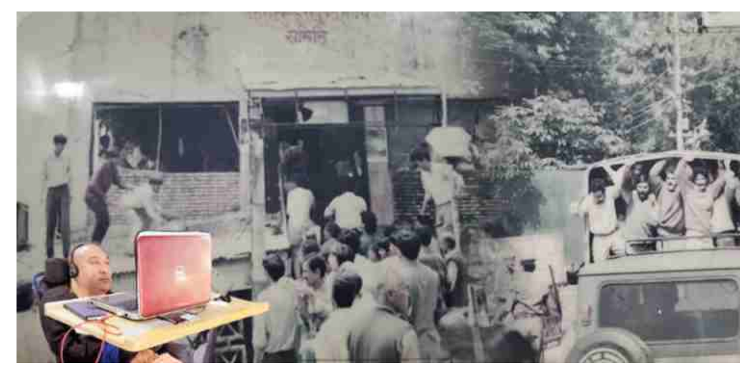

नाकामी छिपा रहे राहुल गांधी?

राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका चुनाव आयोग से या भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ये सवाल तो खुद राहुल गांधी के राजनीतिक करियर से जुड़ा है, राहुल कांग्रेसियों को ये बताना और जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार-बार हार के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं, कांग्रेस को तो वोट चोरी कर हराया जाता है।

अफलज फौजी
नैनीताल

बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा चुनावों को लेकर ऐसा राजनीतिक 'हाइड्रोजन बम' फोड़ा है, जिसने चंद पलों के लिए पूरे देश की राजनीति को हिला दिया, लेकिन राहुल गांधी के दावों को फिर उन्हीं मतदाताओं ने पलीता लगा दिया जिन्हें राहुल ने हथियार बनाया था। राहुल गांधी ने हरियाणा के जिस नरेंद्र पुत्र शायर का जिक्र किया, वह 30 वर्षों से दादरी के वार्ड 4 स्थित अपने मकान में रहता है। इसी मकान का नंबर शून्य दिखाया गया है। सच में नरेंद्र के मकान का कोई नंबर नहीं है। बाकी पता व वोटर लिस्ट में नाम सही हैं। नरेंद्र और उसके माता-पिता व परिवार के मतदाता पहचान-पत्र 7 जनवरी 2013 को बने हैं। तब से उनके वोटर कार्ड में भी मकान नंबर शून्य ही है। उनके माता-पिता, नरेंद्र की पत्नी ज्योति, भाई सोनू और भाभी पूजा के मतदाता पहचान-पत्रों में भी मकान नंबर शून्य ही है। आधार कार्ड में भी मकान संख्या शून्य है। इस परिवार के सभी सरकारी दस्तावेजों में भी मकान नंबर शून्य है। नरेंद्र का कहना है कि मकान नंबर शून्य होने से उन्हें फर्जी वोटर कैसे कहा जा सकता है? हरियाणा के ही मच्छरौला गांव की जिस पिंकी के नाम का उल्लेख राहुल गांधी न प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो पिंकी मीडिया ने खोज निकाली। पिंकी ने मीडिया को बताया कि जब वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट डालने गई तो वोटर लिस्ट में किसी और की फोटो लगी होने का पता लगा था। मैंने वोटर आई कार्ड दिखाया तो वोट देने की छूट मिल गई। बरोटा गांव की जिस विमला का नाम राहुल गांधी ले रहे थे उस विमला ने मीडिया के कैमरे पर बताया कि जब वोट डालने गई तो मुझे किसी ने नहीं टोका। मैंने अपना वोट डाला। हालांकि वोटर लिस्ट में किसी अन्य महिला का फोटो लगा था। मच्छरौला गांव की मुनेश देवी का नाम भी राहुल गांधी ने लिया था। मनेश का कहना है कि मैंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, राहुल गांधी ने जो दिखाया, उसमें मेरा नाम, पति का नाम और पता बिल्कुल सही है। मेरी जगह फोटो किसी मॉडल की लगी है। हालांकि मेरे पास जो पहचान पत्र है उसमें मेरा फोटो है।

बहानेबाज बन गई कांग्रेस?

राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करने का आरोप लगा दिया। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजों का भारी भरकम पुलिंदा लेकर पहुंचे। फिर प्रेजेंटेशन के जरिए साबित करने की कोशिश की कि पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वोट चोरी से चुनाव जीता था। हरियाणा की राई विधानसभा सीट के 10 अलग अलग मतदान केंद्रों पर 22 वोटर ऐसे हैं जिनके वोटर कार्ड पर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है और इन सभी वोटर्स ने हरियाणा के चुनाव में वोट डाला है। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स थे, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को जोड़ रहा है। 25 लाख फर्जी वोटर का दावा करने वाले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसे 250 फर्जी वोटर्स पेश नहीं कर पाए। राहुल गांधी के दावों पर चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट के बारे में अपने सारे सबूत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश करें। लेकिन सबूत हों तो राहुल गांधी कोर्ट जाएं। दरअसल जिस राहुल गांधी को पप्पू या नाकाम नेता कहा जाता है वो असल में एक शातिर स्टेटर्जी के तहत राजनीति करता है। राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका चुनाव आयोग से या भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल तो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर से जुड़ा है। राहुल कांग्रेसियों को ये बताना और जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार-बार हार के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। कांग्रेस को तो वोट चोरी कर हराया जाता है। राहुल गांधी जानते हैं, जिस दिन कांग्रेसियों को ये लगने लगेगा कि वह चुनाव नहीं जिता सकते तो पार्टी नेता ऐसे नेता की तलाश करेंगे जो उन्हें चुनाव जिता सके। चुनाव हराने वाले को कोई लीडर नहीं मानता। इसलिए पहली बार 2014 में राहुल ने लोकसभा चुनाव में हार के लिए अपनी ही पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। 2019 उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ईवीएम हैक करके जीत गए। 2024 में ईडी, सीबीआई और आईटी की मदद से भाजपा के चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। अब वो भाजपा पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीत कर कांग्रेस को उम्मीद बंधी थी कि उसे महाराष्ट्र और हरियाणा में बढ़त मिलेगी, लेकिन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार ने राहुल गांधी को तोड़ दिया। अब अगर बिहार भी हार गए, तो फिर नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। इसलिए चुनाव नतीजों से पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो नहीं हारते, उन्हें तो वोट चोरी कर हराया जाता है।

> **नरेंद्र उसके माता-पिता व परिवार के मतदाता पहचान-पत्र 7 जनवरी 2013 को बने हैं, तब से उनके वोटर कार्ड में भी मकान नंबर शून्य ही है, उनके माता-पिता, नरेंद्र की पत्नी ज्योति, भाई सोनू और भाभी पूजा के मतदाता पहचान-पत्रों में भी मकान नंबर शून्य है आधार कार्ड और परिवार के सभी सरकारी दस्तावेजों में भी मकान नंबर शून्य है।**

जेन जी को भड़का रहे राहुल

राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ा। इस बार राहुल गांधी का संदेश केवल विपक्ष या चुनाव आयोग के लिए नहीं, बल्कि भारत के जेन जी के लिए भी था। यानी 13 से 28 साल के वो 37 करोड़ युवा, जो देश की कुल आबादी का करीब 26 प्रतिशत हिस्सा हैं। जेन-जी वोटर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 18 से 28 साल के वोटर्स की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा हो सकती है और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी भारत के जेन जी को चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़का रहे हैं? क्या राहुल गांधी जेन जी को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारत सरकार का तख्तापलट कराना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी जेन जी को भड़का कर भारत की अर्थ व्यवस्था को चौपट कराना चाहते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष का यही इरादा है तो देश के लिए राहुल गांधी से बड़ा खतरा कोई और नहीं हो सकता। लिहाजा उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना ही चाहिए। देश जलाने से पहले राहुल का इलाज करना आवश्यक है। क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए भारत के जेन जी से कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो जेन जी को आगे आना होगा और उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जेन जी का जिक्र तो किया, लेकिन नेपाल की तरह हिंसा के लिए नहीं भड़काया था। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को जेन जी ने सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया और 24 घंटों में तख्तापलट कर दिया था, तब से राहुल गांधी लगातार अपने बयानों में जेन जी का उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल ने 18 सितंबर 2025 को कहा था कि देश के जेन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को जेन जी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया और 5 नवंबर को उन्होंने फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेन जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत के लोकतंत्र को बचाने में अपनी ताकत दिखाएं। हालांकि भारत का जेन जी जानता है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर की थी। भारत में लोकतंत्र की हत्या जवाहर लाल नेहरू ने बिना समर्थन के देश का पहला प्रधानमंत्री बनकर की थी। भारत का जेन जी जानता है कि राहुल गांधी विश्वसनीय नेता नहीं हैं। जेन जी ये भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जीते हैं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है जबकि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। जेन जी ये भी जानता है कि नरेंद्र मोदी खुद मेहनत कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं जबकि राहुल गांधी परिवारवाद की वजह से राजनीति में हैं। ऐसे आरोप भाजपा समय समय पर राहुल गांधी पर लगाती रही है।

> - **क्या राहुल गांधी जेन जी को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारत सरकार का तख्तापलट कराना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी जेन जी को भड़का कर भारत की अर्थ व्यवस्था चौपट कराना चाहते हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष का यही इरादा है तो देश के लिए राहुल से बड़ा खतरा कोई और नहीं हो सकता।**
> - **भारत का जेन जी जानता है कि भारत में लोकतंत्र व संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर की थी, भारत के लोकतंत्र की हत्या नेहरू ने बिना समर्थन के देश का पहला प्रधानमंत्री बनकर की थी, भारत का जेन जी जानता है कि राहुल गांधी विश्वसनीय नेता नहीं हैं, वो ये भी जानता है कि पीएम मोदी देश के लिए जीते हैं।**

भाजपा का जवाब

राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ा जिसकी आवाज सुनने वालों ने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि जिन 22 वोटर कार्ड पर एक ही मॉडल की तस्वीर है, उन वोटर कार्ड से चुनावों में वोट डाले गए हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर लिस्ट को दिखाकर वोट चोरी का दावा कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट मतदान के बाद की नहीं बल्कि मतदान से पहले की है। जरा सोचिए मतदान से पहले की वोटर लिस्ट से राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि इन वोटर कार्ड से चुनावों में वोटिंग भी की गई है। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एच फाइल्स वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जवाब दिया है। रिजिजू ने राहुल गांधी के वोट चोरी व वोटर लिस्ट में गड़बड़ी वाले दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले संसद सत्र में एक महिला की फोटो टी-शर्ट पर छपवाई थी। वह इसे पहनकर जगह-जगह घूमे। चुनाव के समय वह थाईलैंड, कोलंबिया चले जाते हैं। रिजिजू ने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव से पहले उपलब्ध होती है। अगर कोई नाम छूट जाता है, तो उसे जुड़वाने की व्यवस्था होती है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी ने न्यायपालिका को भी लपेट लिया था। राहुल ने कहा था कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो न्यायपालिका भी टीवी पर देख रही है, इसलिए न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी सिर्फ प्रोपेगैंडा करते हैं, उनके पास आरोप लगाने का कोई ठोस आधार नहीं होता इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने से बचते हैं। जबकि उनके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील भी हैं। वो जानते हैं कि कोर्ट में जाने से उनका झूठ बेनकाब हो जाएगा। इसलिए मीडिया के सामने या रैली में ही वोट चोरी का दावा कर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है। एक दिन आएगा जब कांग्रेस किताब में पढ़ाई जाएगी, एक थी कांग्रेस।

कुमाऊं का आत्मनिर्भर सूपी गांव

गुमनाम रहा सूपी गांव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की नजरों में आया तो इसकी पहचान उत्तराखंड के कृषि और पर्यटन गांव के रूप में हुई, सूपी गांव कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कम पलायन और पर्यटन व कृषि के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के कारण पर्यटन के मानचित्र में स्थान पा सका है।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड के नैनीताल जिले का शहर हो या गांव हर तरफ कुदरती सौंदर्य की चादर बिछी है। नैनीताल जिले में ही एक खूबसूरत गांव सूपी है, जो अपनी जैविक खेती, बागवानी और पारंपरिक कृषि के लिए जाना जाता है। यह गांव 'देवताओं का गांव' भी कहलाता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा पिछले साल सूपी गांव को 'सर्वश्रेष्ठ कृषि पर्यटन ग्राम' घोषित किया था। सूपी गांव रामगढ़ ब्लॉक में आता है, इस गांव की खासियत ये है कि यहां 12 महीने मौसम के अनुरूप बदलाव आते रहते हैं जिससे यहां का नजारा बेहद आकर्षक और मनमोहक होता है। यही खासियत इस गांव को उभरते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। कभी गुमनाम रहा सूपी गांव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की नजरों में आया तो इसकी पहचान उत्तराखंड के कृषि और पर्यटन गांव के रूप में हुई। सूपी गांव अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कम पलायन और पर्यटन व कृषि के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के कारण पर्यटन के मानचित्र में स्थान पा सका है। यह गांव न केवल अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, बल्कि समृद्ध कृषि, फल उत्पादन और स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों के लिए नई पहचान बना रहा है। सूपी गांव जनसंख्या की दृष्टि से गहना गांव के बाद रामगढ़ विकासखंड का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। यह कसियालेख और सतबुंगा के बीच नगाधिराज हिमालय पर्वत के दृश्यों के साथ स्थित है। सरोवर नगरी नैनीताल से मल्ला रामगढ़ के रास्ते मुक्तेश्वर को जाने वाली मुख्य सड़क पर लगभग 40 किलोमीटर दूर व मुक्तेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर पहले है। यह गांव कोसी की सहायक नदी रामगाड़ से लेकर पहाड़ के दूसरी तरफ धारी विकास खंड की सीमा तक फैला हुआ है। सूपी ग्रामसभा की जनसंख्या लगभग 3500 है और मतदाताओं की संख्या 1800 हैं। इस सूपी गांव को आधुनिकता से भी जोड़ा जा सकता हैं क्योंकि गांव में 'कुमाऊं वाणी' सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी है। इस रेडियो स्टेशन से प्रगतिशील किसानों व विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों को जैविक कृषि की आधुनिक जानकारी दी जाती है। साथ ही मनोरंजन भी कराया जाता है।

खेती आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था

सूपी गांव की पहचान इसकी जैविक आधारित खेती से खड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी है। यहां आलू, गोभी, मिर्च, सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी जैसी मौसमी सब्जियां और फल जैविक तरीके से उगाए जाते हैं। वैसे सभी जानते हैं कि रामगढ़ फल पट्टी है, जिसमें सूपी गांव की बड़ी भूमिका है। यहां सालाना सेब, आड़ू तथा ककड़िया व जागनैल प्रजाति की नाशपाती का उत्पादन मार्च से अगस्त के बीच बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन गांव में कोल्ड स्टोरेज के अभाव में फल उत्पादकों को अपने फल कम कीमतों पर बेचने पड़ते है। हैरानी की बात ये है कि कृषि पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलने के बावजूद गांव में सैलानियों को ताजे फल नहीं मिलते। इसकी वजह ये है कि फल उत्पादक फलों

- **सूपी गांव को आधुनिकता से भी जोड़ा जा सकता हैं क्योंकि गांव में 'कुमाऊं वाणी' सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी है, इसी रेडियो स्टेशन से प्रगतिशील किसानों व विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों को जैविक कृषि की आधुनिक जानकारी दी जाती है, साथ ही मनोरंजन भी कराया जाता है।**
- **गांव में कोल्ड स्टोरेज के अभाव में फल उत्पादकों को अपने फल कम कीमतों पर बेचने पड़ते है। हैरानी की बात ये है कि कृषि पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलने के बावजूद गांव में सैलानियों को ताजे फल नहीं मिलते, इसकी वजह ये है कि फल उत्पादक फलों को स्थानीय स्तर पर नहीं बेचते।**

को स्थानीय स्तर पर नहीं बेचते, बल्कि सबसे करीब की हल्द्वानी कृषि उत्पादन मंडी ले जाकर या सरकार को 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देते हैं। सैलानियों को जो फल मिलते हैं वो गांव के बच्चों द्वारा एकत्र किए गए पेड़ से नीचे गिरे हुए बासी और दोयम दर्जे के फल होते हैं। हालांकि सूपी गांव में कोल्ड स्टोरेज और स्थानीय बाजार की कमी जैसी चुनौतियां हैं। फिर भी गांव के फल उत्पादकों की मेहनत और सरकार की योजनाओं से यह गांव भविष्य में और भी बेहतर बन सकता है। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से भी यहां की कृषि व बागवानी को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ताकि गांव की आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सके। हालांकि जागरूक किसान फल-सब्जियों व जड़ी-बूटियों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी सच है कि इस गांव से फलों की पुरानी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। इनकी जगह हिमाचली प्रजाति के उच्च तापमान में पैदा होने वाले सेबों के बगीचे यहां तेजी से विकसित हो रहे हैं। सेब उत्पादक भी हिमाचली प्रजाति को विकसित करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। जिससे गांव का फल उत्पादन तेजी से बढ़ सके और फल उत्पादकों की अर्थ व्यवस्था मजबूत हो सके।

गांव की संपन्नता की निशानी

सूपी गांव की नैसर्गिक खूबसूरती को देखते हुए दिल्ली और गाजियाबाद के अलावा दूसरे राज्यों से आए लोगों ने यहां अपने लिए कोठियां बना ली है, होमस्टे बना रहे हैं। सूपी में सड़क से दूर के गांवों के परिवार अपने घरों को छोड़ सड़क किनारे बस रहे हैं और कई बाहरी लोग उनके घरों को खरीदकर या लीज पर लेकर उन पर मिट्टी की लिपाई और पारंपरिक शैली में दर्शाकर उन्हें होम स्टे में बदल रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को सरकार की होम स्टे योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों के होम स्टे में नौकरी कर रहे हैं। गांव की संपन्नता के पैमाने सूपी गांव में मौजूद है। गांव में चार प्राथमिक विद्यालय, एक इंटर कॉलेज, को-आपरेटिव सोसाइटी, 5 आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ कई महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। प्रगतिशील किसान बागवानी और खेती के साथ कदमताल करते हुए फलों की पुरानी प्रजातियों को छोड़ कर नई प्रजातियों को अपना रहे है। स्थानीय लोग नौकरी का रास्ता अपनाने के बजाये

गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से भी यहां की कृषि व बागवानी को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ताकि गांव की आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सके।

स्वरोजगार के साथ तरक्की कर रहे हैं। गांव में जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या के समाधान के लिए परियोजना तैयार की गई है। गांव में वर्षा जल संग्रह के लिए पेयजल टैंक भी बने हैं, जिससे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस सबके बीच दूसरे गांवों की तरह सूपी गांव के लोग भी तेजी से शहरीकरण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिससे गांव का पारंपरिक स्वरूप और संस्कृति को खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि हिमालय के दृश्यों वाली अधिकतर भूमि बाहर से आए लोगों ने धन का प्रलोभन देकर खरीद ली है। इससे ग्रामीणों के पारंपरिक जीवनशैली पर प्रभाव पड़ रहा है।

सांस्कृतिक विरासत

पहाड़ों में अमूमन घर दूर-दूर बने होते हैं, जो खेत और जंगलों से घिरे एक शांतिपूर्ण माहौल बनाते हैं। सूपी गांव में भी घर दूर-दूर ही बने हैं। यहां की संस्कृति में देवताओं के मंदिर की पूजा की परंपरा है, जो विशेष रूप से पशुधन की रक्षा के लिए की जाती है। यह प्रथा ग्रामीणों के जीवन में आध्यात्मिकता और पशुपालन के प्रति महत्व को दर्शाती है। यह गांव साल भर अपनी खूबसूरती बनाए रखता है। सूपी गांव बसंत में खिलते फूलों और सर्दियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए भी पहचाना जाता है। हालांकि अनियमित बारिश जैसी मौसमी चुनौतियां किसानों के लिए चिंता का विषय भी बनी रहती हैं। गांव में कार्यरत स्वयं सहायता समूह द्वारा हर्बल उत्पाद जैसे रोजमैरी, पार्सली और तुलसी से बने उत्पाद सूपी सुगंध ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। गांव में कई जलधाराएं जिन्हें स्थानीय भाषा में नौला कहा जाता है, हैं। ग्रामीण इन नौलों से पेयजल और खेती के लिए सिंचाई के तौर पर उपयोग करते हैं। ये नौले न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए गांव वालों ने दीवारें बना रखी हैं। गांव का हर घर जंगल में है, जो साबित करता है कि यहां के लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। यहां के पूर्वजों ने जमीन का विकास इस तरह किया है कि हरियाली, खेत और घर आस-पास ही हैं। सूपी के निवासियों के त्योहारों में कुमाऊं की झलक साफ नजर आती है। ग्रामीण बसंत पंचमी, हरेला, घी संक्रांति (घ्यूं त्यार), फूलदेई और घुघुतिया जैसे त्योहार प्रकृति के चक्र और कृषि से जुड़े हैं। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकपर्व है, जो हरियाली का प्रतीक है। सूपी गांव के लोग भी इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पर्व में अच्छी फसल की कामना के लिए नौ दिन पहले से घरों में सात प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, जिसे हरेला कहा जाता है। 10वें दिन इसे काटा जाता है। घी संक्रांति इसे ओलगिया त्यौहार भी कहते हैं। यह भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। सूपी गांव में लोग पारंपरिक वेशभूषा में इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। मुक्तेश्वर के पास सूपी गांव में स्थित जैन मंदिर में हर साल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों के जैन श्रद्धालु भाग लेते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर भी भव्य आयोजन होता है। यहां के लोग इस महोत्सव को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। खतड़वा त्यौहार उत्तराखंड में बारिश के मौसम के अंत और सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने पालतू जानवरों की अच्छी सेहत की कामना करते हैं और पारंपरिक रूप से आग जलाकर बुराई को भस्म करने का अनुष्ठान करते हैं। सूपी गांव को देवताओं का गांव भी कहते हैं। यहां के लोग पशुधन की रक्षा के लिए अपने स्थानीय लोक देवताओं की पूजा की परंपरा का पालन आज भी करते हैं।

भरोसे के हत्यारे डॉक्टर

आपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी, अपनों की लाशें देखने के बाद मसूद अजहर आपा खो बैठा था, आपरेशन सिंदूर के बाद ही उसकी बहन सादिया अजहर ने महिला विंग जमात-उल-मोमिनात का गठन किया और भारत में महिलाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी डॉ.शाहीन शाहिद को सौंपी।

केके चौहान

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सुसाइड बम बन कर तीव्र गति का विस्फोट करने वाले डॉ.उमर नबी मोहम्मद की बात करें या डॉ.आदिल अहमद, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ.अहमद मोहियुद्दीन सैयद, डॉ.शाहीन शाहिद व उसके भाई डॉ.परवेज अंसारी की अथवा फरार डॉ. निसार उल हसन की। ये सभी मानवता और भरोसे के हत्यारे हैं। ये सारे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं तथा जैश-ए-मोहम्मद और अंसार-गजवत-उल-हिंद के लिए काम करने वाले हैं। इनका इरादा भारत में खासतौर से 6 दिसंबर को अयोध्या में सीरियल ब्लास्ट कर लाशों के ढेर लगाना था, देश में तबाही मचाना था, लेकिन उससे पहले ही जैश-ए-मोहम्मद के भारत विरोधी पोस्टर ने इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल को बेनकाब कर डाला। आतंकियों का अड्डा बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो डॉ.निसार उल हसन भी नौकरी कर रहा था जिसे जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2023 में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के पूर्व सहायक प्रोफेसर पद से बर्खास्त कर दिया था। उस पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। लेकिन उसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आसानी से नौकरी कैसे मिल गई? डॉ.निसार उल हसन दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती हमले के बाद से फरार है। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से सुसाइड बम बना डॉ. उमर नबी मोहम्मद जुड़ा था। वह बिना बताए यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे ही यूनिवर्सिटी का एक और डॉ. मुजम्मिल शकील है जिसके यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी खुद ही जांच के घेरे में आ जाती है। यह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में तब आई जब इसमें काम करने वाले डॉक्टरों के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े मिले। जांच एजेंसियों ने करीब 20 डॉक्टरों व दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया और 50 से ज्यादा डॉक्टर पुलिस के रडार पर हैं। कुछ संदिग्ध डॉक्टर अपने मोबाइल फोन बंद कर गायब हो चुके हैं।

महिला डॉक्टर बनी आतंकी कमांडर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली डॉ.शाहीन शाहिद कितनी खतरनाक है यह उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला। डॉ.शाहीन शाहिद अपने डॉक्टर पति डॉ. जफर हयात से तलाक लेने के बाद 2013 में दुबई चली गई थी। जहां वह कट्टरपंथियों के संपर्क में आई। आमतौर पर हिजाब नहीं पहनने वाली डॉ. शाहीन हिजाब पहनने लगी। दुबई से उसने पाकिस्तान की यात्रा की और 10 साल पहले जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आई। जहां उसे जैश की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात की महिला कमांडर बनाया गया। इस संगठन का संचालन जैश प्रमुख मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है। आपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। अपनों की लाशें देखने के बाद से मसूद अजहर आपा खो बैठा था। आपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए ही उसकी बहन सादिया अजहर ने महिला विंग जमात-उल-मोमिनात का गठन किया और भारत में गरीब मुस्लिम महिलाओं रेडिकलाइज करके आतंकी संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी डॉ.शाहीन शाहिद को सौंपी। दो साल पहले फरीदाबाद शिफ्ट हुई डॉ.शाहीन के संपर्क में जो भी डॉक्टर आया उसे रेडिकलाइज कर आतंकी संगठन से जोड़ने का काम किया। डॉ.शाहीन शाहिदा का पहला शिकार उसका ही छोटा भाई डॉ.परवेज हुआ। वह सामान्य डॉक्टर से कट्टरपंथी बन गया। इसके बाद डॉ.मुजम्मिल शकील हो या डॉ. उमर नबी मोहम्मद सब के सब आतंकी संगठन जैश के हिस्सा बनते गए। रेडिकलाइज करने के लिए उसे जैश से फंडिंग भी होती थी। ऐसा डॉ.शाहीन के खाते की जांच के बाद पता चला है यानी उसके सात बैंक खातों में 1.55 करोड का लेनदेन हुआ है। जांच के दौरान पता चला है। पूछताछ में डॉ.शाहीन शाहिद ने जांच एजेंसियों के सामने चौकाने वाले खुलासे किए हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में डॉ.शाहीन शाहिद ने कबूला कि वह पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करती है। जैश के सदस्य पिछले दो सालों से फरीदाबाद में विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे, ताकि दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी सहित प्रमुख शहरों में सीरियल ब्लाएट किए जा सकें। पूछताछ में उसने कबूला कि वह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के जरिए हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही थी। वो मेडिकल की आड़ में आतंकी नेटवर्क को फंडिंग का काम भी करती थीं। पूछताछ में डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल ने कबूला कि उनका प्लान दिल्ली, अयोध्या व प्रयागराज में दिवाली पर सीरियल ब्लास्ट करने का था, लेकिन वो चूक गए। इसके बाद 6 दिसंबर और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर विस्फोट करने की योजना बनाई गई, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों ने डॉक्टरों के इस टेरर गैंग को दबोच लिया। लिहाजा एनआईए, दिल्ली स्पेशल पुलिस, हरियाणा और यूपी एसटीएफ अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल के छात्र जम्मू-कश्मीर के हैं। जांच एजेंसियां सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सभी लैब भी जांच के दायरे में हैं। क्योंकि जांच एजेंसियो ने दिल्ली ब्लास्ट को आत्मघाती बम विस्फोट माना है, जिसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डॉ. उमर नबी मोहम्मद ने अंजाम दिया है। ईडी ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी है।

भारत सरकार अथवा किसी भी एजेंसी ने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान में पैनिक है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर है।

मोदी की ललकार

राजधानी दिल्ली में लालकिले के पास 10 नवंबर को विस्फोट की घटना के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से विस्फोट के जिम्मेदार, साजिश रचने वालों व दोषियों को ललकारते हुए सख्त लहजे में कहा कि भारतीय जांच एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने यह चेतावनी दी। उन्होंने हिंदी में अपनी बात रखी, लेकिन बाद में अंग्रेजी में दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत दिल्ली में किए गए विस्फोट को आतंकी घटना मान रहा है। यह पहली बार नहीं है, जब पीएम मोदी ने इस प्रकार की किसी बड़ी घटना पर सख्त बयान दिया हो। इसी साल बिहार के मधुबनी में एक रैली के दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि भारत आतंकवादी और उसके समर्थकों को ढूंढेगा, पकड़ेगा और सजा देगा। तब भी उन्होंने अचानक हिंदी से अंग्रेजी में अपना भाषण देना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर स्पष्टता के साथ भारत का पक्ष रखते हैं। भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस बयान से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में हुए ब्लास्ट को आतंकवादी हमला मान रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी भारत की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहा है। क्योंकि इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट कहा था कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को अब युद्ध माना जाएगा।

पाकिस्तान में दहशत

दिल्ली में हुए ब्लास्ट की एक-एक कड़ी जोड़ी जा रही है। भारत सरकार ने या फिर किसी भी एजेंसी ने अभी तक डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बौखलाहट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर है। पाकिस्तानी यूट्यूबर बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ने भारतीय सीमा पर सेना तैनात कर दी है, एयरवेस से लेकर आतंकी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का कहना है कि पाकिस्तान सरकार इस वक्त खौफ में है क्योंकि उसे डर है कि भारत पाकिस्तान को कठघरे में जरूर खड़ा करेगा। आरजू ने कहा-दिल्ली अटैक के बाद हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर भारत की तरफ से खुलकर तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किसी किस्म का कोई सबूत मिला तो भारत पाकिस्तान को फिर से फोड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबराया है। पाकिस्तान सरकार खौफ में है कि कहीं भारत फिर पाकिस्तान का नाम न ले ले। भारत व पाकिस्तान के बीच पहले से ही टेंशन है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक दिल्ली धमाकों पर अफसोस नहीं जताया है। ऐसे में शक की सुई पाकिस्तान की तरफ क्यों ना जाए? दिल्ली में के बाद पाकिस्तान के पीएम को फौरी तौर पर अफसोस का इजहार करना चाहिए था।

- **महिला डॉ.शाहीन शाहिद ने अपने डॉक्टर पति से तलाक लिया और जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात की महिला कमांडर बन गई, इस संगठन का संचालन जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है।**
- **एनआईए, दिल्ली स्पेशल पुलिस, हरियाणा, यूपी एसटीएफ और ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच कर रही है, इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल के छात्र जम्मू-कश्मीर के हैं, जांच एजेंसियां सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सभी लैब भी जांच के दायरे में हैं।**

मौलाना भर रहे जहन में जहर

देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल जितने भी किरदार गिरफ्तार किए गए हैं वो सब शिक्षित और पेशे से डॉक्टर हैं। शिक्षित आतंकी जाहिल आतंकियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि जाहिल आतंकी को सिर्फ टारगेट मिलता है जबकि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अपना टारगेट खुद फिक्स करते हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि डॉक्टर और इंजीनियर या प्रोफेसर कैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ते हैं तो इसका जवाब ये है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा मदरसों में होती है और मदरसों में कट्टरपंथी बनाए जाते हैं। जिहाद की शिक्षा दी जाती है, इस्लाम को न मानने वालों को काफिर बताया जाता हैं। बचनपन में जो जहर जहन में भरा जाता है वो व्यस्क होने के बाद भी नहीं निकलता, भले ही कोई डॉक्टर बन जाए या फिर इंजीनियर अथवा प्रोफेसर ही क्यों न बन जाए। शायद इसलिए डॉक्टर मॉड्यूल बनाकर देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। डॉ.उमर नबी मोहम्मद जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा में उसके घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया है।

पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले युवा के आतंक की राह क्यों चुन रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर देश के विकास में योगदान देने के बजाए देश में आतंक क्यों फैलाना चाहते हैं? शिक्षित युवाओं के आतंकी संगठनों से जुड़ने के इतिहास पर नजर डालें तो 2021 में बेंगलुरु में आईटी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने ऑनलाइन विदेशी फंडिंग के जरिए दो लाख डालर की क्रिप्टो करेंसी आतंकी समर्थकों को दी थी। 2022 में दिल्ली में एक जूनियर डाक्टर पर कट्टरपंथी समूह को शरण देने का आरोप लगा था। 2023 में मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डार्क वेब से बम बनाने की कोडिंग सीखने के बाद तीन अन्य युवकों को प्रशिक्षण दिया था। 2024 में केरल में एक मेडिकल छात्रा को आईएसआईएस के ऑनलाइन सेल से जुड़ने और फंडिंग में मदद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2025 में तो डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल ही बेनकाब हुआ और एक डॉक्टरों उमर नबी तो फिदायीन निकला। पुरुष ही नहीं महिला डॉक्टर तो जैश के महिला विंग की कमांडर निकली।

मोहन का सम्मोहन

बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व ने राजनीति के अखाड़े में एक बड़ी लकीर खींच दी, वहीं यदुवंशियों की बेल्ट और पिछड़े वर्ग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सम्मोहन का जोरदार असर भी देखने को मिला है।

आलोक एम इंदौरिया
वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार

बिहार विधानसभा के आम चुनावों के नतीजों ने एक ओर जहां भाजपा गठबंधन की आशातीत सफलता की एक नई इबारत लिख डाली, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की रणनीति और नेतृत्व की निर्णायक भूमिका को भी राजनीतिक परिदृश्य में सामने लाने और स्थापित करने का काम किया है। निश्चित ही इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व ने राजनीति के अखाड़े में एक बड़ी लकीर खींच दी है, वहीं यदुवंशियों की बेल्ट और पिछड़े वर्ग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सम्मोहन का जोरदार असर भी देखने को मिला है। यकीनन भाजपा अलाकमान ने जिस मुराद और उम्मीद से एमपी के सीएम मोहन यादव को बिहार के चुनावी समर में उतारा था उस पर वे न केवल खरे उतरे बल्कि देश में भाजपा की ओर से वे अब सबसे बड़े यादव नेता के चेहरे और ब्रांड के तौर पर स्थापित भी हो गए हैं, जो स्थान भाजपा में लगभग खाली था। बिहार चुनाव में सीएम मोहन यादव के सम्मोहन ने यदुवंशी बाहुल्य क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट बैंक को खंड-खंड कर दिया, अपितु युदवंशी बाहुल्य क्षेत्र में यादव वोटों को पहली बार कमल के फूल वाला बटन दवाने के लिए प्रेरित भी किया। यह सच है कि मोहन यादव के सघन और धुंआधार प्रचार से एनडीए के पक्ष में बड़ा ही सकारात्मक माहौल उनके दायित्व वाले विधानसभा क्षेत्रों में बना जिसका प्रभाव पूरे बिहार में पड़ा। ये सब बिहार के चुनाव नतीजों में भी स्पष्ट रूप से झलक रहा है। भाजपा अलाकमान अब मोहन यादव का सदुपयोग 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी करेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाजपा आलाकमान जानता है कि उसका कौन सा कार्यकर्ता कहां उपयोगी है। किस कार्यकर्ता को कहां इस्तेमाल किया जाना है।

भाजपा में मोहन बने यादव चेहरा

बिहार के प्रतिष्ठापूर्ण चुनावों में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार किया और बेहतर से बेहतर काम एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया। निश्चित ही पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी का नेतृत्व अपना करिश्मा दिखा रहा था. लेकिन राजद का कोर वोटर (एमवाई) यानी यादव और मुस्लिम वोटों की युति को भंग करने और इन्हें विभाजित करने की तरकीब भाजपा आलाकमान तलाश रहा था और उसकी यह तलाश आखिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पर आकर ठहर गई। यदि भाजपा को खंगालें तो उसके पास पूरी भाजपा में अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव को टक्कर देने वाला एक भी यादव नेता नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में यादव वोटर 18 प्रतिशत और बिहार में 15 प्रतिशत हैं। यादव वोट दोनों राज्यों यूपी व बिहार में पूरी तरह से सत्ता में डोमिनेट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तथा बिहार में लम्बे समय तक लालू यादव राज में यादव समाज ने राजनीति में खासा ऊंचा मुकाम बना लिया था और सत्ता की कहानी हमेशा इनके ईद-गिर्द घूमती रहती थी। एमवाई समीकरण यानी यादव और मुस्लिम वोट बैंक की युति के दम पर सत्ता में आने का सीधा रास्ता इनके पास था। मगर एमवाई समीकरण के कारण भाजपा को सत्ता में आने के लिए न केवल कड़ा परिश्रम करना पड़ा बल्कि यादव वोट बैंक को अपने पक्ष में करने लिए राजनीतिक इलाज भी तलाशना पड़ा।

बिहार के मतदाताओं ने डॉ. मोहन यादव के सादगी पूर्ण स्वभाव, जमीनी जुड़ाव, मजबूत संगठन कौशल, सहृदय व्यवहार के साथ लच्छेदार भाषण शैली को दिल की गहराई से स्वीकारा, मोहन यादव का करिश्माई व्यक्तित्व बिहार में एक नई ऊर्जा लेकर आया और बिहार को अपना दूसरा घर बताकर उन्होंने आम जनता का दिल भी जीत डाला।

मोहन ने यादवों का मन मोहा

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा अलाकमान ने यादव समाज के कद्दावर नेता के रूप में स्थापित हो चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उतारा। उन्हें बिहार के अखाड़े में यह सोचकर भी उतारा गया कि मोहन यादव बिहार के यादव वोटों में आसानी से सेंघ लगाकर भाजपा की तरफ मोड़ लेंगे। मोहन यादव के लिए निश्चित ही यह बड़ी चुनौती थी। लेकिन भाजपा का उद्देश्य चुनाव में बंपर जीत हासिल करना था, लिहाजा देश भर में भाजपा के एक मात्र यादव मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव एनडीए के लिए सबसे ज्यादा मुफीद लगे। इसलिए उन्हें बिहार की यादव बाहुल्य 50 से अधिक सीटों पर प्रचार और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन कराने तक की जिम्मेदारी दी गई। इसके अतिरिक्त दो दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों की सीधी कमान उन्हें सौंपी गई। बिहार के मतदाताओं ने डॉ. मोहन यादव के सादगी पूर्ण स्वभाव, जमीनी जुड़ाव और मजबूत संगठन कौशल, सहृदय व्यवहार के साथ लच्छेदार भाषण शैली को दिल की गहराई से स्वीकार किया। मोहन यादव का करिश्माई व्यक्तित्व बिहार में एक नई ऊर्जा लेकर आया और बिहार को अपना दूसरा घर बताकर उन्होंने आम जनता का दिल भी जीत डाला। मोहन यादव की सभाओं में भारी भीड़ ने उनकी लोकप्रियता का अहसास तो कराया साथ ही बिहार के यादव वोटों में उनकी स्वीकारोक्ति को भी पुख्ता किया। मोहन यादव ने जिन सीटों पर प्रचार किया वहां नतीजों में जीत की मोहर भी लगी। क्योंकि उन्होंने यदुवंशी समाज को यह अहसास कराया और विश्वास दिलाया कि यदुवंशी समाज का भाजपा में अहम और बेहद महत्वपूर्ण स्थान हैं। देश में भाजपा ही एक मात्र ऐसी पार्टी हैं जिसने मध्य प्रदेश में तमाम योग्य और अनुभवी नेताओं के बाद भी युदवंशी समाज से मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो बनाया ही साथ ही मध्य प्रदेश में काम करने की खुली छूट भी दी। जिसके कारण उन्होंने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया और औद्योगिक विकास की एक नई और शानदार इबारत लिख डाली।

यादव वोट भाजपा में डायवर्ट

राजनीति के पंडितों की मानें तो उनके अनुसार डॉ. मोहन यादव का बिहार में डेरा जमाना और लगातार ईमानदारी से किए गए प्रयास भी चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए। एक यादव मुख्यमंत्री को देखकर यदुवंशी उनकी ओर ऐसे आकर्षित हुए की यादव वोट पहली बार ऐसा बंटा की लालू यादव और तेजस्वी यादव की लालटेन बुझी ही नहीं बल्कि लालू परिवार खंड खंड भी हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव का प्रयास रहा कि जाति से ऊपर उठकर विकास और उसमें अपनी भागीदारी को आमजन सुनिश्चित करे और बिहार के लोगों ने ऐसा किया भी। देश का एक मात्र यादव मुख्यमंत्री भाजपा से...यह एक ऐसा बड़ा संदेश बना जिसने यदुवंशियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और यही भाजपा अलाकमान भी चाहता था। पटना से लेकर पूर्णिया तक तमाम जिलों की विधानसभाओं को उन्होंने नाप डाला और इंडिया गठबंधन के एमवाई की जगह उन्होंने मोदी के एमवाई यानी महिला और यूथ पर फोकस किया। मोहन यादव की सभाओं में महिलाओं और युवाओं की भारी भीड़ उनकी लोकप्रियता पर मोहर लगती रही। इस तरह उन्होंने राजद के गढ़ में सेंघ लगाकर उनके कोर वोट बैंक को भाजपा की तरफ डायवर्ट कर दिया। पहली बार यादव बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा ने भारी बढ़त हासिल की लिहाजा यह तो स्वीकारना ही होगा कि कहीं न कहीं इसमें मोहन के सम्मोहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोहन यादव ने 26 विधानसभाओं का दायित्व और सीधा प्रचार संभाला था। जिसमें 22 पर एनडीए गठबंधन जीता। इसमें 13 सीट भाजपा के खाते में गई जबकि 9 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों को मिलीं। यानी यादव बाहुल्य क्षेत्र में पहली बार भाजपा की बड़ी जीत का परचम लहराया। खास बात यह है कि बिहार में यादव बाहुल्य बाली 88-90 सीटें हैं और डॉ. मोहन यादव ने इसमें से 26 सीटों का जिम्मा संभाल रहे थे और हाड़तोड़ मेहनत के साथ प्रचार किया। इस प्रचार का एनडीए को सीधे फायदा यह हुआ कि पूरी 88 सीटों में यदुवंशियों के बीच यह संदेश गया कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सकल समाज को सम्मान दिया है। यही कारण है कि इन 88 सीटों में से तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन केवल 12 सीटें जीत सका। शेष 76 सीटें भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन ने जीती। मोदी फैक्टर के बाद इन यादव बाहुल्य 88 विधानसभा क्षेत्रों में मोहन यादव का फैक्टर भी खूब चला जिसके चलते इंडिया गठबंधन को जिस क्षेत्र से सर्वाधिक उम्मीद थी उनकी वो उम्मीद और सत्ता पाने का सपना चकनाचूर हो गया।

जात-पात से बाहर निकला बिहार

बरहाल बिहार का चुनाव परिणाम मात्र जीती और हारी हुई सीटों की गणना मात्र नहीं है। जिसमें जनता ने जंगलराज की जगह विकास और सामाजिक समरसता की ओर कदम बढ़ाया यह एक नए सामाजिक परिवर्तन का संकेत इसलिए है क्योंकि पहली बार बिहार के चुनाव में जात-पात से ऊपर उठकर बिहार के विकास पर केंद्रित रहा। बिहार की जनता ने राजद के तेजस्वी ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का ऐसा वादा किया जिस पर यादवों को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए भी यादव बाहुल्य क्षेत्र की 88 से 90 सीटों पर लालू यादव और उनके परिवार का जो दखल और दबदबा था उसे तोड़ना मुमकिन हो सका। बिहार में तमाम शब्द बने जैसे एमवाई, यानी महिला, यूथ, एमवाई मुस्लिम यादव, एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, एमएन मोदी-नीतीश इसी तरह डबल एम यानी मोदी-मोहन अर्थात मोदी के नेतृत्व और मोहन के सम्मोहन ने लालटेन के तिलस्म को तोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में एनडीए की जीत का परचम लहराकर बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाया कि विकास और समरसता न केवल एक साथ चल सकते हैं बल्कि दौड़ भी सकते हैं। ●

मोदी में पटेल जैसे गुण

वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के परिवार की तुलना की जाए तो नेहरू का परिवार देश बर्बाद करने के लिए पहचाना जाता है, जनता के टैक्स पर ऐश करने वाला है, भोग विलासिता का जीवन जी रहा वहीं दूसरी तरफ भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिवार बेहद सादा जीवन जीता है।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

भारत के स्वाधीनता संग्राम में अनेक विभूतियां हुई जिन्होंने अपने बलिदान, त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प से देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। किंतु आजाद भारत की एकता और अखंडता की जो संरचना की, उसका श्रेय सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जिन्हें सारा राष्ट्र 'लौह पुरुष' और 'राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार' के रूप में सम्मानित करता है। उन्होंने जिस विवेक, कुशलता, रणनीति और दृढ़ता से रियासतों के विलय का कार्य किया, वह भारत के इतिहास में अप्रतिम और प्रेरणास्पद है। हालांकि देश की आजादी का श्रेय आज भी कांग्रेस लेती है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा धोखाधड़ी, छल, कपट, विश्वासघात, पाखंड, चालाकी, धूर्तता और दोहरापन की राजनीति की, इसलिए जवाहर लाल नेहरू का खानदान देश का पहला परिवार बना बैठा है। जिस महात्मा गांधी को देश की आजादी का श्रेय दिया जाता है उन्होंने देश को आजाद कराने में योगदान देने वालों को सत्याग्रह के नाम पर ब्लैकमेल किया। इसी ब्लैकमेल की वजह से सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यदि वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के परिवार की तुलना की जाए तो नेहरू का परिवार देश बर्बाद करने के लिए पहचाना जाता है, जनता के टैक्स पर ऐश करने वाला है। भोग विलासिता का जीवन जी रहा वहीं दूसरी तरफ भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिवार बेहद सादा जीवन जीता है। उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बच्चों ने तो आगे बढ़ाया, लेकिन उनके पोते-पोतियां राजनीति की चकाचौंध से दूर हैं। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने पूरे परिवार की तस्वीर शेयर की तो देश का पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिवार कहां और कैसा है? सरदार पटेल के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा थे। बेटी का नाम मणिबेन पटेल है जो बड़ी थी, बेटा छोटा दह्याभाई पटेल था। सरदार पटेल के दोनों बच्चे स्वतंत्रता के बाद राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन दोनों में से किसी को भी कांग्रेस ने बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं बनने दिया। जबकि नेहरू ने अपने परिवार को राजनीति में हावी किया।

पटेल के पौत्र का सादा जीवन

सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल सांसद थीं, वो आजीवन अविवाहित रहीं और अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वहीं भाई दह्याभाई पटेल ने 1939 में पहली बार बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य चुने गए और 18 साल तक निगम के सदस्य बने रहे। दह्याभाई पटेल ने दो शादियां कीं थी। उनकी पहली पत्नी यशोदा बेन थीं, जिनके निधन के बाद उन्होंने भानुमति बेन से दूसरी शादी की। दह्याभाई और भानुमति बेन के दो बेटे हुए विपिन पटेल और गौतम पटेल। सरदार पटेल के पोते विपिन पटेल और गौतम पटेल, दोनों भाई राजनीति से दूर रहे। विपिन पटेल के निधन के बाद गौतम पटेल ही सरदार पटेल के निकट संबंधियों में से एक रह गए हैं, जो आमतौर पर अपनी विरासत की शोहरत से दूर एक सादा जीवन जीते हैं। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल लंबे समय तक कांग्रेस की सांसद रहीं। बाद में वह मोरारजी देसाई के साथ स्वतंत्र पार्टी में शामिल हुईं। फिर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। उनकी पहचान सरदार पटेल के ही नाम से थी। 70 के दशक में पटेल के बेटा और बेटी दोनों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। पटेल की बेटी मणिबेन बेहद ईमानदार थीं। 1988 में उनका निधन हुआ। अमूल के संस्थापक कूरियन वर्गीज ने अपनी किताब में विस्तार से मणिबेन पटेल का जिक्र किया है। कूरियन जब आणंद में रहते थे, तब मणिबेन से उनकी अक्सर मुलाकातें होती थीं, वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती थीं। वह किताब में लिखते हैं, मणिबेन ने उनसे बताया था कि जब सरदार पटेल का निधन हुआ तो उन्होंने एक किताब और एक बैग लिया। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से मिलने चली गईं। उन्होंने नेहरू को इसे सौंपते हुए कहा कि पिता ने निर्देश दिए थे कि उनके निधन के बाद इसे केवल नेहरू को सौंपा जाए। इस बैग में पार्टी फंड के 35 लाख रुपये थे और बुक पार्टी की खाताबुक थी। नेहरू ने इसे ले लिया और मणिबेन को धन्यवाद कहा। इसके बाद वह इंतजार करती रहीं कि शायद नेहरू कुछ और बोलें, जब ऐसा नहीं हुआ तो वह उठीं और चली आईं। कूरियन ने उनसे पूछा, आप नेहरू से क्या सुनने की उम्मीद कर रही थीं? जवाब था-मैंने सोचा था शायद वह ये पूछेंगे कि मैं अब कैसे काम चला रही हूं या मुझे किसी मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं पूछा।

राजनीति से दूर पटेल के वंशज

जवाहर लाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ही थे जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी और बेटे को राजनीति में पहचान नहीं बनाने दी, दोनों के राजनीति में आगे बढ़ने में बाधाएं पैदा की, सरदार पटेल की जयंती पर भी सिर्फ रस्म अदा की, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तब 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मानाने की पहल की। इस साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस की भव्य परेड हुई। एकता दिवस की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष के 150वें जन्मदिन पर विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। यही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का असली चरित्र था। यह पहला मौका था जब पूरा परिवार एक साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी के साथ नजर आया। नडियाद में जन्में सरदार पटेल आणंद के करमसद स्थित घर में बड़े हुए, लेकिन पिछले काफी सालों से उनके परिवार के सदस्य सुर्खियों से दूर निजी जीवन जी रहे हैं। कई सदस्य विदेश में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल के पूरे विस्तारित परिवार भतीजे-भतीजियां में 30-35 सदस्य हैं, लेकिन प्रमुख सदस्यों में कुल पांच सदस्य ही हैं। गौतम दह्याभाई पटेल, सरदार पटेल के पौत्र हैं। उनकी उम्र 80 साल है। वह दह्याभाई के बेटे हैं और गुजरात के वडोदरा में रहते हैं। 2025 के सरदार पटेल जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया तो परिवार के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डॉ. नंदिनी पटेल, गौतम पटेल की पत्नी हैं। उनकी उम्र करीब 75 साल के आसपास है। वह गौतम के साथ वडोदरा में ही रहती हैं। वह भी राजनीति से दूर रहती हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के परिवार ने हमेशा राजनीतिक या सार्वजनिक उपस्थिति से दूरी बनाए रखी। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन में भी वे अनुपस्थित रहे थे। वे सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से उनकी विरासत को संरक्षित रखते हैं।

सरदार पटेल के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा थे, बेटी का नाम मणिबेन पटेल है जो बड़ी थी, बेटा छोटा दह्याभाई पटेल था, सरदार पटेल के दोनों बच्चे स्वतंत्रता के बाद राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन दोनों में से किसी को भी कांग्रेस ने बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं बनने दिया।

सरदार पटेल और उनकी बेटी मणिबेन

पटेल और नेहरू के बीच विवाद रहता था

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल धीर-गंभीर और गरिमामय व्यक्तित्व के धनी थे, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित, मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने वाला व्यक्तितत्व था। वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल किसान थे और माता लाडबाई धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। लेकिन सामान्य से दिखने वाले सरदार पटेल बहुत बड़े वकील भी थे, लंदन से बार-एट-लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। सरदार पटेल और नेहरू के बीच कई बिंदुओं पर विवाद रहता था। नेहरू अपनी वैश्विक छवि लेकर चलते थे। सरदार पटेल व्यावहारिक, यथार्थवादी और परंपरागत भारतीय मूल्यों पर आधारित नीति के पक्षधर थे। वे राष्ट्रीय एकता और आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहते थे। पटेल का मानना था कि भारत को अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिए, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। उन्होंने नेहरू को कई बार चीन के खतरे के प्रति आगाह भी किया था। लेकिन नेहरू उनकी बातों को अनसुनी करते रहे और हिंदी-चीनी भाई-भाई का राग अलापते रहे, जिसका दुष्परिणाम हमने 1962 में भुगता। चीन ने भारत पर हमला कर बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। आधा कश्मीर पाकिस्तान ने ले लिया।

पलेट के साथ घोर अन्याय

सरदार पटेल के साथ सबसे बड़ा अन्याय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा कर महात्मा गांधी ने किया। गांधी ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश का पहला पीएम नहीं बनने दिया। उस समय कांग्रेस के नियमों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होते थे। 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम की संस्तुति की, जबकि दो ने जेबी कृपलानी के नाम की और एक ने अपना मत जाहिर नहीं किया। नेहरू के नाम की संस्तुति किसी ने नहीं की थी। लेकिन महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की धज्जिायां उड़ाकर नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया इस तरह बेइमानी से नेहरू भारत के पहले पीएम बने। सरदार पटेल को उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने होते तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अलग होता। निश्चित ही पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता और चीन   आसानी से भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा नहीं कर पाता। यदि सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश में आतंकवाद, भाई-भतीजावाद और परिवारवाद की राजनीति जन्म ही नहीं लेती। पटेल पीएम बने होते तो वामपंथी इतिहास पढ़ाकर देश को गुमराह न किया गया होता। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति न होती, हिंदू संस्कृति को कुचलने की कोशिश न होती, राममंदिर हो या काशी मथुरा का विवाद न होता। किंतु वर्तमान राजनीति में जहां चरित्र और आदर्श गायब हैं वहीं विभाजनकारी शक्तियां देश विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर देश का बर्बाद करने पर तुली हैं। भारत विरोधी ताकतें कांग्रेस और वामपंथियों को इस्तेमाल कर देश का विभाजन करना चाहती है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का अतीत भारतीय संस्कृति का विरोधी रहा है। अब राहुल गांधी तो खुलेआम भारत को कमजोर करने वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके विपरीत पीएम नरेंद्र मोदी में वल्लभ भाई पटेल के गुण दिखाई देते हैं। सरदार पटेल की तरह पीएम नरेंद्र मोदी में दृढ़ता, निष्पक्षता, राष्ट्रहित, सामाजिक और वैचारिक एकता, देश की भौगोलिक अखंडता, दूरदर्शी प्रशासक की छवि, आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन की छवि दिखाई देती है। पीएम मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन दर्पण से प्रभावित हैं। इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विपक्षी नेताओं को भी पटेल के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि सरदार पटेल कम बोलते थे दिखावा नहीं करते थे, उनकी राजनीति में न दिखावा था, न स्वार्थ। सरदार पटेल का जीवन केवल इतिहास नहीं, वह भारत की आत्मा की आवाज है जो हमें आज भी एकता, निष्ठा और राष्टभक्ति का अमर संदेश देती है।

राहुल गांधी खुलेआम देश को कमजोर करने वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसके विपरीत पीएम नरेंद्र मोदी में वल्लभ भाई पटेल के गुण दिखाई देते हैं, पटेल की तरह पीएम मोदी में दृढ़ता, निष्पक्षता, राष्ट्रहित, सामाजिक और वैचारिक एकता, देश की भौगोलिक अखंडता की छवि, आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन की छवि दिखाई देती है।

मीडिया गुटों में बंटा

राजधानी देहरादून में पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने का काम भी वही लोग कर रहे हैं, जो गुट विशेष के नजरिये से पत्रकारिता करते हैं, विशेष रूप से दो भागों में बंटे पत्रकार, जिनमें एक को सरकार की गोदी में बैठा माना जाता है और दूसरे को सरकार के हर निर्णय में कमी उजागर करने वाला।

राजेश पांडे
देहरादून

उत्तराखंड के संदर्भ में बात की जाए तो यहां पत्रकारों के गुट दलीय राजनीति से प्रेरित दिखते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करने वाले इस दायरे से बाहर नहीं हैं, माना जाता है कि पत्रकार जनता की आवाज है, पर राजधानी में बैठे पत्रकारों के स्वघोषित मठाधीशों का जोर उस नजरिये पर ज्यादा होता है, जिसको उनका गुट विशेष हवा देना चाहता है। यहां पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने का काम भी वही लोग कर रहे हैं, जो गुट विशेष के नजरिये से पत्रकारिता करते हैं, विशेष रूप से दो भागों में बंटे पत्रकार, जिनमें एक को सरकार की गोदी में बैठा माना जाता है और दूसरे को सरकार के हर निर्णय में कमी उजागर करने वाला। सरकार कुछ अच्छा करे, जनहित में कोई सूचना प्रसारित करे तो उसका प्रसार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? सरकार या उसके तंत्र के स्तर से कमियां हैं तो उसको भी जनता के सामने लाना चाहिए। यही पत्रकारिता का सर्वमान्य नियम और धर्म है। पर जो बात गुटीय पत्रकारिता में देखने को मिल रही है, उसमें पूरी तरह से भांडगीरी, स्वामी भक्ति का आशय, दरबारियों वाला राग...साफ दिखता है। इनको न तो दिक्कतें दिखती हैं और न ही सरकारी स्तर से होने वाली कोई कमी। ये नेताओं और अफसरों को ईमानदारी, श्रेष्ठता, कमाल-बेमिसाल होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यहां सर्वार्थ नहीं बल्कि स्वार्थ की बात पहले है। कहने में कोई गुरेज नहीं, इनमें से कई तो पत्रकारिता से इसलिए जुड़े, ताकि वो सरकार और उसके सिस्टम से जुड़ सकें। अब विरोधी मोर्चे का हाल यह है कि उसके चश्मे को कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार जनहित में एक भी निर्णय नहीं ले, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। गलत का विरोध होना चाहिए, पर अच्छे की प्रसंशा भी होनी चाहिए। पत्रकारिता का काम सिर्फ खबर पेश करना है, सिस्टम में मौजूदा खामियों और अच्छाइयों को दिखाना है। जनता की आवाज को बुलंद करना है। जनता की बात सिस्टम तक पहुंचाना है। किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष की चुनावी महत्वाकांक्षा के लिए जनता को लामबंद करके सड़कों पर उतारना नहीं है। यह काम राजनीतिक दलों का है, पत्रकारों का नहीं। किसी के पक्ष में माहौल बनाना पत्रकारिता का उसूल नहीं है। पर अमूमन यहां पत्रकारिता के केंद्र में सिर्फ सरकार और उसके सिस्टम का कामकाज, गुटीय राजनीति के साथ पक्ष या विपक्ष ही है। पत्रकार या तो उस पार हो या फिर इस पार, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। पत्रकारिता का एक स्वरूप और भी है, जो व्यवस्था की खामियों पर चोट करने के साथ जनपक्ष और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करता है। यह मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जोर देता है। दुखद यह है कि उत्तराखंड की पत्रकारिता में इस विधा पर बहुत कम काम हो रहा है। पर देशभर में कई पत्रकार इस पर काम कर रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या कम है। जन पत्रकारिता के उद्देश्य को पूरा करने वाले यही पत्रकार हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की आवाज को, उनकी पीड़ा को, मुश्किलों के साथ समाधान को, बेस्ट प्रैक्टिसेज को, इनोवेशन को...और भी बहुत सारी स्टोरीज को करने में मेहनत लगती है। पर यहां राजधानी के एसी कमरों में आरटीआई, न्यूज क्लिप्स, अखबारों की कतरनें, रिपोर्ट्स को अपने हिसाब से ढालकर स्क्रिप्ट लिखना, कैमरे के सामने बोलना ज्यादा आसान मालूम पड़ता है। लेकिन सलाम है उन पत्रकारों को, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनपक्ष है, जनसंचार है, न कि किसी के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना कंधा उपलब्ध कराना है।

स्मार्ट फोन से स्मार्ट पत्रकारिता?

जब सोशल मीडिया नहीं था, उस समय प्रिंट, टीवी यानी इलेक्ट्रानिक मीडिया और रेडियो जर्नलिज्म ही थे। लेकिन तकनीक की प्रगति ने पत्रकारिता को नए आयाम दिए, जिनमें सोशल मीडिया, जिसे हम न्यू मीडिया भी कहते हैं, ने धमाल मचा दिया। अब जिनके पास स्मार्ट फोन हैं, वो सभी पत्रकारिता कर सकते हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सिर्फ स्मार्ट फोन और माइक होने भर से पत्रकारिता नहीं की जा सकती है, क्योंकि पत्रकारिता के अपने नियम और सीमाएं हैं। इन नियमों, जिनको हम आचार संहिता कहते हैं, को पहले समझना, मानना और फिर लागू करना सबसे पहली आवश्यकताएं हैं। मैंने 1996 के दौर में पत्रकारिता शुरू की, तब सोशल मीडिया नहीं था। अखबारों और पत्रिकाओं की संख्या भी इतनी अधिक नहीं थी। खबरें और फोटो कंप्यूटर सिस्टम में लगे मॉडेम के माध्यम से प्रकाशन केंद्रों तक भेजे जाते थे। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। किंतु अब तो सर्वर पर चल रहे सीएमएस, एफटीपी या इससे भी कुछ और तकनीक पर कमाल हो रहा है। बात कर रहा था, पत्रकारिता के बदलते वक्त और पत्रकारों के बदलते व्यवहार व कार्यशैली की। सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को आसान तो किया है, इसको रियल टाइम तो बनाया है, पर इसने इसको नुकसान भी कम नहीं पहुंचाया। अधिकतर लोगों में यह भ्रांति व्याप्त है कि स्मार्ट फोन ही पत्रकारिता के लिए काफी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यह सच नहीं है, यह सच के करीब भी नहीं है। इस बात की तस्दीक पत्रकारिता के नाम पर हो रहे भ्रामक प्रचार, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति, अफवाह फैलाने की घटनाएं, झूठी सूचनाएं फैलाने, तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित करने, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की छवि बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास करने, किसी का भी महिमामंडन को खबर सी शक्ल देने की प्रवृत्तियों से हो रही है। और भी बहुत कुछ गलत हो रहा है पत्रकारिता की आड़ में। सोशल मीडिया पर यह जो कुछ भी चल रहा है, उसको पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता, न ही इस कृत्य को करने वाले पत्रकार कहलाए जा सकते हैं।

गुटीय पत्रकारिता में जो बात देखने को मिल रही है, उसमें पूरी तरह से भांडगीरी, स्वामी भक्ति का आशय, दरबारियों वाला राग...साफ दिखता है, इनको न तो दिक्कतें दिखती हैं और न ही सरकारी स्तर से होने वाली कोई कमी, ये नेताओं और अफसरों को ईमानदारी, श्रेष्ठता, बेमिसाल होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।

- **सिर्फ स्मार्ट फोन और माइक होने भर से पत्रकारिता नहीं की जा सकती है, क्योंकि पत्रकारिता के अपने नियम और सीमाएं हैं, इन नियमों, जिनको हम आचार संहिता कहते हैं, को पहले समझना, मानना और फिर लागू करना पत्रकारिता की सबसे पहली आवश्यकताएं हैं।**
- **सोशल मीडिया पर पक्की, कच्ची सूचनाओं की बाढ़ ने पत्रकारों पर प्रेशर बनाया है, वहीं रियल टाइम न्यूज का दबाव अलग से हावी है, संशय इस बात का भी है कि विज्ञापन पाने के कंपटीशन में खबरों पर सेंसर लगता है, तभी तो आज का मीडिया पहले जैसा नहीं दिखता है।**

स्पॉट रिपोर्टिंग का जमाना गया

पहले दौर में, पत्रकार घटनास्थल पर जाते थे और मौके के हालात को जानते थे, वहां उनको बहुत सारे सवालों के जवाब और तथ्य मिल जाते थे। यही बात उनको सच तक ले जाती थी। पत्रकार सूचनाओं के लिए दफ्तरों में जाते थे। लोगों से मिलते थे। अखबारों के दफ्तरों में विज्ञप्तियां लेकर लोग आते थे। दूसरे दिन के अखबार में क्या प्रकाशित होगा, लोग जानने के इच्छुक रहते थे। किंतु अब यह बहुत कम देखने को मिलता है। अब तो सरकार अपने सोशल मीडिया पर सूचनाएं देती है। कई बार तो ये सूचनाएं ही खबरों की शक्ल में प्रकाशित होती हैं। पत्रकार मौके पर जाकर इन सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों को कवर नहीं करते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, जबकि पहले पत्रकार समय का रोना कभी नहीं रोते थे। अब सोशल मीडिया पर पक्की, कच्ची सूचनाओं की बाढ़ ने पत्रकारों पर प्रेशर बनाया है। वहीं रियल टाइम न्यूज का दबाव अलग से हावी है। संशय इस बात का भी है कि विज्ञापन पाने के कंपटीशन में खबरों पर सेंसर लगता है, तभी तो आज का मीडिया पहले जैसा नहीं दिखता है। सोशल मीडिया के दौर में, मौके पर जाने वाले पत्रकार कम हैं, पर खबर प्रकाशित और प्रसारित करने वालों की बाढ़ है। इनमें अधिकतर वो लोग होते हैं, जिनके फोन तो स्मार्ट होते हैं पर उनको पत्रकारिता की बुनियादी बातों का भी ज्ञान नहीं है। कई तो कंटेंट को भी एडिट किए बिना वैसा ही प्रकाशित कर देते हैं, जैसा उनको मिला है। अपने पास से वैल्यू एडिशन तक नहीं करते। वैसे भी वैल्यू एडिशन वही कर पाएगा, जिसके पास अतिरिक्त तथ्य होंगे, जिनकी रिपोर्टिंग डायरी मजबूत होगी, जो मौके पर गया होगा। यहां खबर की कवरेज से ज्यादा फोकस उसको फटाफट प्रकाशित करके व्यूज बटोरने पर है। पूरा खेल व्यूज का है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर अफरा-तफरी का माहौल है। वैसे सच तो ये भी है कि वेबसाइट्स व सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर खबरों और बाकी कंटेंट को प्रकाशित और प्रसारित करने वालों में से कई को यह भी नहीं मालूम रहता कि खबर अधिकारिक स्रोत से पुष्ट है या नहीं। उनका काम कॉपी पेस्ट, फॉरवर्ड करने तक सीमित है। हेडिंग, फोटो भी एक समान हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकारिता के सिद्धांतों की अनदेखी, रीडर्स के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अक्सर इसी तरह की पत्रकारिता में देखने को मिलता है। इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपने या किसी दूसरे के स्वार्थ को पूरा करने का माध्यम भी बनता है। यही पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

सोशल मीडिया के दौर में मीडिया का उजला पक्ष

न्यू मीडिया, जो सोशल मीडिया से संचालित होता है, वो कई मौकों पर दमदार दिखाई पड़ता है। हालांकि, यह कई दफा अनियंत्रित भी जान पड़ता है और कई बार नौसिखिये सा व्यवहार करता दिखता है, क्योंकि किसी के पास स्मार्ट फोन होना उसकी रिपोर्टिंग के स्मार्ट होने की गारंटी नहीं है। पर यहां कुछ लोग मेहनत एवं ईमानदारी और पत्रकारिता की साख एवं उच्चतम स्तर को बनाए रखे हैं, इसलिए सोशल मीडिया जर्नलिज्म के उनके कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। कई पत्रकारिता को तमाशा बनाने वाले मनोरंजन के तौर पर भी देखे जाते हैं। मेरी राय में ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, बल्कि व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आर्थिक उन्नति दिखती है। यह बात भी पूरी तरह पुख्ता तौर पर बता सकता हूं कि कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के दर्शन भी कराए हैं। इन पत्रकारों को वर्तमान दौर में पत्रकारिता का उजला पक्ष कहूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पत्रकार स्मार्ट फोन के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस का इस्तेमाल पुष्ट सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने, फैक्ट चेक के साथ अफवाहों पर विराम लगाने, प्रभावितों एवं पीड़ितों की अभिव्यक्ति को अधिकतम प्रसार देने, समस्याग्रस्त इलाकों एवं व्यक्तियों की आवाज सरकार और उसके सिस्टम तक पहुंचाने, जागरूकता बढ़ाने, सरकारी सिस्टम की खामियों, लचरता, लापरवाही को उजागर करने, गलत फैसलों के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति को प्रसार देने, हर समुदाय के हित को प्राथमिकता देने, कानून विरोधी व भ्रष्टाचार की गतिविधियों को उजागर करने जैसी कई जिम्मेदारियों को पूरा करने में कर रहे हैं। ये पत्रकार देश के संविधान में प्रदत्त अधिकारों एवं व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पीछे नहीं हैं। ये पत्रकार ही पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले, उसकी साख को बनाए रखने वाले हैं।

न्यूज पोर्टल जर्नलिज्म मेरे लिए तो अच्छी है

न्यूज पोर्टल जर्नलिज्म, जिसको अक्सर सरकारी विज्ञापन के नाम पर कोसा और बदनाम किया जाता है। दरअसल में यह मेरे जैसे पत्रकारों के लिए तो संजीवनी की तरह है। मैं अपनी जानता हूं और मानता हूं कि इसने मुझे बहुत सहयोग किया। मुझे इस पर वही विज्ञापन मिलता है, जो सरकार की टेंडर नीति के तहत सभी को मिलता है। अगर, सरकार की कोई खबर, जो इन्फारमेशन है, जनहित में है, तो उसको प्रकाशित करने में मुझे खुशी ही मिलेगी। ग्राम यात्राएं करना, उनका विस्तार से अपने पोर्टल पर स्थान देना मेरा शौक है। मुझे खुशी है कि मैं किसी दलीय या व्यक्तिगत राजनीति से संबद्ध किसी भी गुट का सदस्य नहीं हूं और न ही मुझे किसी का कंधा बनने की जर्नलिज्म आती है। मेरी तरह और भी न्यूज पोर्टल हैं, जो खबरों के लिए मेहनत करने वाले उन पत्रकार साथियों द्वारा संचालित हैं, जो पत्रकारिता को उसके दायरे और नियमों में रखकर ही करते हैं। इससे घर परिवार को चलाने में उनको मदद मिलती है, इसमें बुरा ही क्या है। क्या सरकार बड़े समूहों को विज्ञापन नहीं देती। बहुत सारे पत्रकार साथी हैं, जो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और घर परिवार की तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पर, इसके साथ ही... मैं उन लोगों का भी सख्त विरोध करता हूं, जो जबरदस्ती के पत्रकार बने हैं, न्यूज पोर्टल की आड़ में अपने धंधे चला रहे हैं, ब्लैकमेलिंग पर उतारू होते हैं, सरकारी अफसरों पर विज्ञापनों के लिए दबाव बनाते हैं, भांडगीरी करते हैं, रागदरबारी बनते हैं, दूसरे के स्वार्थ पूरे करते हैं, कुल मिलाकर पत्रकारिता का नाश करने पर तुले हैं।

कांग्रेस ने फिर एलआईसी को घेरा

अक्टूबर में वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और एलआईसी ने मिलकर अडानी ग्रुप को 33,000 करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई है, रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया गया, लेकिन किसी ठोस दस्तावेज या स्वतंत्र सत्यापन का जिक्र नहीं है, जो वॉशिंगटन पोस्ट की विश्वसनीयता को कलंकित करता है।

डा.भारत भूषण
आईएफटीएम

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाल के विदेशी दौरे का साइड इफेक्ट भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और अडानी ग्रुप महाघोटाले के रूप में सामने आ गया है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं देश विरोधी ताकतों का कोई न कोई एजेंडा लेकर लौटते हैं। इसके लिए विदेशी धरती पर पहले प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्ट भी छपती है। इस बार जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे तब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में गिने जाने वाले वॉशिंगटन पोस्ट ने एलआईसी को लेकर एक भ्रामक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे भारत विरोधी एजेंडा सेट किया जा सके एलआईसी निवेशकों में खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन अब न सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में अपनी विश्वसनीयता को कलंकित किया बल्कि गंभीर सवालों के घेरे में भी है। जिस अखबार ने वॉटरगेट स्कैंडल जैसे मामलों में सत्ताधारी ताकतों को बेनकाब किया था, वही अब भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और आर्थिक उदय को लेकर लगातार संदिग्ध और भ्रामक रिपोर्टें प्रकाशित करने के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी मीडिया द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अटकलों पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित करना उन दलों और पक्षकारों की हताशा है, जिनके नेता पिछले 11 वर्षों से चुनावी मैदान में सिर्फ हार ही देख रहे हैं और हार का शतक लगाने के करीब हैं। अक्टूबर में वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट इसका ताजा उदाहरण है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और एलआईसी ने मिलकर अडानी ग्रुप को 33,000 करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई है। रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया गया, लेकिन किसी ठोस दस्तावेज या स्वतंत्र सत्यापन का जिक्र नहीं है, जो अखबार की विश्वसनीयता को कलंकित करता है। भारत सरकार, एलआईसी और अडानी ग्रुप तीनों ने तुरंत इस खबर को 'भ्रामक और मनगढ़ंत' रिपोर्ट बताकर खारिज कर दिया। एलआईसी ने स्पष्ट किया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश उसके कुल पोर्टफोलियो का एक प्रतिशत भी नहीं है और उस निवेश पर उसे 120 प्रतिशत से अधिक का लाभ मिला है। भारतीय मीडिया ने भी इस रिपोर्ट को उसी तरह 'हिट जॉब' करार दिया, जैसे 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए भारत की कंपनियों और बाजार को निशाना बनाया गया था। अब वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और स्टाप टारगेटिंग इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि एलआईसी ने पॉलिसी धारकों के करीब 33,000 करोड़ रुपये अडानी ग्रुप में निवेश करके उसे फायदा पहुंचाया है, जयराम रमेश ने इसे 'महाघोटाला' बताते हुए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की और उससे पहले इसे लोक लेखा समिति (पीएसी) से जांच कराने को कहा है।

विदेशी अखबार पर कांग्रेस का भरोसा

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आते ही आदतन कांग्रेसी टूल किट एक्टिव हो गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने एलआईसी को लेकर आरोप लगाया है कि उसने 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए दिया है। अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपने आरोपों को नए सिरे से धार देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि एलआईसी ने पॉलिसी धारकों के करीब 33,000 करोड़ रुपये अडानी ग्रुप में निवेश करके उसे फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं सांसद जयराम रमेश ने इसे 'महाघोटाला' बताते हुए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की और उससे पहले इसे लोक लेखा समिति (पीएसी) से जांच कराने को कहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, 'मीडिया में हाल में कुछ परेशान करने वाले खुलासे हुए हैं कि 'मोदानी जॉइंट वेंचर' ने कैसे व्यवस्थित तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और इसके 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का दुरुपयोग किया है।' उन्होंने आगे लिखा, 'आंतरिक दस्तावेजों से खुलासा होता है कि मई 2025 में कैसे भारतीय अधिकारियों ने एलआईसी फंड से 33,000 करोड़ रुपये अडानी ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में निवेश कराए हैं।' जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा है, 'प्रश्न ये उठता है कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अफसरों ने किसके दबाव में एक निजी कंपनी को बचाने का काम किया है, जो आपराधिक आरोपों की वजह से फंडिंग की समस्या का सामना कर रही है? क्या ये 'मोबाइल फोन बैंकिंग' का एक क्लासिक केस नहीं है?' दरअसल कांग्रेस के लिए इस तरह की भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर भारत और भारतीय उद्योगों व कंपनियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोई पहली साजिश नहीं है, बल्कि इससे पहले अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के शेयरों के बारे में कई भ्रामक और झूठी रिपोर्ट पेश की जिससे भारतीय निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब फिर एलआईसी की भ्रामक और झूठी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस निवेशकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहती है। हालांकि एलआईसी ने वाशिंगटन पोस्ट में उसके निवेश से संबंधित छपी खबरों को झूठा बताते हुए उनमें किए गए दावों का खंडन किया है। एलआईसी ने कहा है कि उसके सभी निवेश ईमानदारी और पूरी सावधानी के साथ किए जाते हैं। एक विदेशी अखबार इस तरह की भ्रामक और झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करके खुद अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर रहा है।

एलआईसी दी नसीहत

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट एलआईसी की प्रतिष्ठा और भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूत नींव को कमजोर करने के इरादे से प्रकाशित की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलआईसी अडानी ग्रुप की कंपनियों में 33,000 करोड़ रुपये निवेश करने की तैयारी कर रही थी। एलआईसी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव या दस्तावेज उसके पास मौजूद नहीं है और सभी निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। एलआईसी ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा पूरी तरह भ्रमित करने वाला और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। एलआईसी ने अपने खंडन में कहा, रिपोर्ट में जिस तरह से एलआईसी की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश का रोडमैप तैयार करने की बात कही गई है, वैसा कोई दस्तावेज एलआईसी के पास न तो है और न कभी रहा है। कंपनी के सभी निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से और बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीतियों के अनुरूप लिए जाते हैं। इन निर्णयों में किसी भी सरकारी विभाग या बाहरी निकाय की कोई भूमिका नहीं होती। उसके निवेश संबंधी निर्णय हमेशा विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद ही लिए जाते हैं ताकि हितधारकों के हित सुरक्षित रह सकें। वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य सरकारी निकाय का निवेश संबंधी निर्णयों में कोई दखल नहीं होता। सभी निवेश फैसले निगम की आंतरिक समितियों और विशेषज्ञ टीमों द्वारा मूल्यांकन और समीक्षा के बाद लिए जाते है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करती है। ताकि हमारे ग्राहकों और निवेशकों का विश्वास बना रहे। क्योंकि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और निवेश संस्थान है, जो करोड़ों भारतीयों के जीवन बीमा से जुड़ी हुई है। सरकार के स्वामित्व वाली यह संस्था न केवल देश की वित्तीय स्थिरता में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि निवेश और बीमा क्षेत्र में भरोसे का प्रतीक भी मानी जाती है। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया से आग्रह किया कि वे तथ्यों की पुष्टि किए बिना भ्रामक रिपोर्टिंग से बचें। एलआईसी का यह बयान न केवल अडानी ग्रुप में निवेश से जुड़े विवाद पर विराम लगाता है, बल्कि भारतीय वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता और स्वायत्तता को भी मजबूती से स्थापित करता है।

भारत सरकार, एलआईसी और अडानी ग्रुप तीनों ने तुरंत वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को 'भ्रामक और मनगढ़ंत' रिपोर्ट बताकर खारिज कर दिया, एलआईसी ने स्पष्ट किया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश उसके कुल पोर्टफोलियो का एक प्रतिशत भी नहीं है और उस निवेश पर उसे 120 प्रतिशत से अधिक का लाभ मिला है।

अविश्वसनीय वॉशिंगटन पोस्ट

जून 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को गाजा पर अपनी एक रिपोर्ट का हिस्सा वापस लेना पड़ा था, जिसमें इजराइली सेना पर नागरिकों की मौत का गलत आरोप लगाया गया था। बाद में वॉशिंगटन पोस्ट ने माना कि हेडलाइन और रिपोर्ट 'तथ्यों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व नहीं थी।' जुलाई 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट को भारतीय चैनल टीवी 9 भारतवर्ष से माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उसने पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट में व्हाट्सऐप मैसेज की गलत व्याख्या करते हुए भारतीय मीडिया की गलत प्रस्तुति की थी। 2019 में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अश्वेत परिवारों की जमीन से जुड़े उसके एक लेख में 15 बड़ी त्रुटियां पाई गईं थीं। नाम, तारीख और घटनाओं का ब्यौरा तक गलत था। बाद में वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद इसे 'शर्मनाक' कहा था। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट को डोनाल्ड ट्रंप पर प्रकाशित एक रिपोर्ट सुधारनी पड़ी थी, जिसमें कथित तौर पर उनके हवाले से 'फाइंड द फ्रॉड' कहा गया था, लेकिन बाद में जारी ऑडियो में यह बात झूठी साबित हुई थी। नवंबर 2021 में ही वॉशिंगटन पोस्ट को स्टील डॉसियर से जुड़ी दो रिपोर्ट हटानी पड़ी थीं क्योंकि उनके स्रोत 'विश्वसनीय' नहीं पाए गए थे। इस सबके बाद जब वॉशिंगटन पोस्ट भारत की सरकारी संस्थाओं खासकर सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक एलआईसी पर आरोप लगाता है तो पाठकों में शक पैदा होना स्वाभाविक है। कई भारतीयों को लगता है कि यह विदेशी मीडिया अब निष्पक्ष पत्रकारिता से ज्यादा स्वार्थ पूरा करने के लिए राजनीतिक एजेंडे का मंच बन चुका है। भारत के लोगों को भरमाना अब आसान नहीं है। भारत में स्वतंत्र मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोग अब खुद तथ्यों की जांच करने लगे हैं। विदेशी अखबारों का प्रभाव वैसा नहीं रहा, जैसा कभी हुआ करता था। ऐसे में जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसी संस्थाएं भारत की नीतियों पर हमला करती हैं तो लोग पहले सबूत मांगते हैं। वैसे भी भारत में जिन संस्थाओं पर लोगों का सबसे अटूट भरोसा है, उनमें से एलआईसी एक है। वह सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और सुरक्षा का प्रतीक है। छोटे शहर में रहने वाला नागरिक हो या महानगर का निवासी, हर कोई एलआईसी को अपने भविष्य की गारंटी के रूप में देखता है। इसलिए दशकों से ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक रही एलआईसी जैसी संस्था पर बिना ठोस सबूत के सवाल उठाना लोगों के गले नहीं उतर रहा। कई लोग सोशल मीडिया पर इसे विदेशी मीडिया का 'भारत-विरोधी एजेंडा' बता रहे हैं। ऐसे समय जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की खोखली रिपोर्ट एलआईसी पर हमले की सोची समझी रणनीति है। पब्लिक का मूड देखकर कांग्रेस और विपक्षी दल भी वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को चुनाव में मुद्दा नहीं बना पाए हैं।

चुनाव या मोदी हटाओ इवेंट

बिहार में लालू प्रसाद यादव पर चारा चोरी, नौकरी के बदले जमीन हड़पने जैसे आरोप कांग्रेस के शासनकाल में लगे, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, चारा चोरी के मामले में कांग्रेस के ही कार्यकाल में लालू यादव को सजा हुई, लेकिन लालू यादव आज उसी कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं, जिसने उनका राजनीतिक करियर समाप्त किया है।

अतुल सिन्हा
टीवी जर्नलिस्ट

नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, अगले बरस 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के बाद चुनाव आयोग 12 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करा रहा है, ताकि मतदाता सूची दुरुस्त हो सकें। अयोग्य मतदाताओं को सूची से हटाया जा सके। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है वहां 2026 से 2027 तक चुनाव होने हैं। इसके बाद चुनाव आयोग बाकी बचे राज्यों में एसआईआर कराएगा। 2028 में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2029 में आम चुनाव भी होने हैं। वैसे भारत वो देश है जहां हर साल कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। लेकिन एनडीए सरकार मानती है कि देश में हर साल होने वाले चुनावों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक देश एक चुनाव की परंपरा फिर शुरू की जानी चाहिए। इससे धन का दुरुपयोग होने से बचेगा, जो देश के विकास में काम आएगा। इस पर मोदी सरकार काम भी कर रही है, आज नहीं तो कल एक देश एक चुनाव होना ही है। क्योंकि पीएम मोदी ने जो ठान लिया वो मानकर चलिए एक दिन पूरा होना ही है। खैर इस समय देश में हर विपक्षी दल की एक ही तमन्ना है कि कैसे भी हटे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। इसके लिए अलग-अलग विचारधारा की पार्टियों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बना रखा है, लेकिन इस गठबंधन तमाम झोल भी हैं। कहीं इंडिया गठबंधन संगठित दिखाई देता है तो कहीं ये खंड-खंड नजर आता है। बिहार चुनाव में ही 12 सीटों पर गठबंधन गायब था, गठबंधन के साथी ही एक दूसरी पार्टी को चुनौती दे रहे थे। हरियाणा और दिल्ली चुनाव में गठबंधन की गांठ खुलते सबने देखी थी।

सोशल मीडिया की ताकत

सोशल मीडिया का दौर है और जब बात चुनाव की हो रही है तो सोशल मीडिया कैसे चुप बैठ सकता है। सोशल मीडिया यूजर विपक्षी दलों और भाजपा विरोधियों पर तंज कस रहे है। तमाम कमेंट और पोस्ट हो रही हैं। यूजर पोस्ट कर रहे हैं कि चुनाव तो पहले होते थे। अब तो चुनाव के नाम पर मोदी हटाओ इवेंट हो रहा है। चुनाव के नाम पर सिर्फ मोदी को रोको प्रतियोगिताएं हो रही है। इंडिया गठबंधन की दुर्गति बताते हुए यूजर लिख रहे हैं कि यूपी में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी एक साथ होते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव भरी सभा में कहते हैं कांग्रेस को वोट मत देना ये बड़ी चालू पार्टी है, इसने हमे धोखा दिया है तो फिर आपको भी धोखा ही देगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया था। ऊपर से कांग्रेस नेता कमल नाथ ने 'अखिलेश-वखिलेश' कहकर सपा नेता की तोहीन की थी। बसपा सुप्रीमों मायावती कभी कभार सोशल मीडिया पर प्रकट होती हैं और अपनी बात कहकर गायब हो जाती है। सोशल मीडिया यूजर दिशा पाटली कहती है कि मायावती ने फिल्म 'मिस्टर इंडिया' की वो घड़ी पहन रखी है जो अभिनेता अनिल कपूर ने पहनी थी। क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने भी कम ही नजर आती हैं। सोशल मीडिया यूजर वैभव अग्रवाल और आदित्य किशन घई ने लिखा, 'चुनाव तो पहले हुआ करते थे, अब तो केवल मोदी रोको प्रतियोगिताएं हो रही है।' बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीच मीसा भारती ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें 'एक करोड़ नौकरी' देने का वादा किया है। मीसा ने कहा है कि, 'किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगें।' मीसा भारती को जवाब देते हुए सोशल मीडिया यूजर रजत कुमार ने लिखा कि 'तेरा भाई तेजस्वी बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी क्या फूफा के घर से पैसे लाकर नौकरी देगा।' एक अन्य यूजर अजय सक्सेना ने लिखा लालू खानदान नौकरी के बदले में बिहारियों की सारी जमीन कब्जा लेगा। पहले भी नौकरी के बदले में जमीन पर कब्जा कर चुका है। ये बात बोलने से पहले एक बार सोच लेती, तेरा बाप तो चारा चोर भी है। एक अन्य यूजर ओपी शर्मा ने मीसा भारती को जवाब दिया कि एनडीए ने 'रोजगार देने को बोला है सरकारी नौकरी नहीं, हर घर में रोजगार देने की गारंटी है।'

> **सोशल मीडिया यूजर विपक्षी दलों और भाजपा विरोधियों पर तंज कस रहा हैं तमाम कमेंट और पोस्ट हो रही हैं, यूजर पोस्ट कह रहे हैं कि चुनाव तो पहले होते थे, अब तो चुनाव के नाम पर मोदी हटाओ इवेंट हो रही है, चुनाव के नाम पर सिर्फ मोदी को रोको प्रतियोगिताएं हो रही है।**

मोदी ने विपक्ष का नचा रखा है

बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं, इस पर फेसबुक यूजर जितेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की डांस वाली वीडियो क्लिप के साथ कमेंट किया कि मोदी नाचने वाले नहीं हैं नचाने वाले हैं। पूरे खानदान को ही नहीं विपक्षी दलों को नचा रखा है। विपक्षी नेताओं को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पाकिस्तान और दुनिया के सबसे पावरफुल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को भी नचा रखा है। सोशल मीडिया यूजर कीर्ति कुमार न पोस्ट किया कि ये कैसा गठबंधन है, चुनाव में तो यदा-कदा एक साथ दिखते हैं। मोदी को हटाने के लिए इवेंट करते हैं, लेकिन चुनाव होते ही एक दूसरे को गाली देते घूमते हैं। सोशल मीडिया यूजर विवेक मौर्या ने फेसबुक पर लिखा, चुनाव रैली में मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को सुनने कोई नहीं आता है। असल में गरीब लोग अपने अरमानों के पूरा होने की उम्मीद लेकर आते हैं। सोशल मीडिया पर आरके माहेश्वरी ने राहुल गांधी को ट्रोल किया कि वो बिहार के विकास की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मानसिक रूप से खुद अपना विकास नहीं कर पाए तो देश या प्रदेश का विकास क्या ही कर पाएंगे? खैर सोशल मीडिया वो प्लेटफार्म है जहां बड़े बड़े नेताओं की चमक, धमक और अकड़ सब निकाल दी जाती है।

मोदी को हटाने के हथकंडे

विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से संसदीय विरोध और चुनावी गठबंधनों को मजबूत करना तथा सरकार की कल्याणकारी, राष्ट्रहित, लोकहित की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना शामिल है। विपक्षी दलों के सांसद कई बार ऐसे मुद्दों पर संसद में बहस की मांग करते हैं जिनका संसद से कोई वास्ता ही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू कराए गए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी सांसद लगातार संसद और संसद के बाहर इसका विरोध करते रहे। वो सरकार से एसआईआर के मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार का तर्क था कि जो काम संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग का है उस पर चुनाव आयोग ही बेहतर जवाब दे सकता है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन विपक्षी सांसदों ने मानसून सत्र में हंगामा किया और संसदीय कार्य में बाधा डाली। सरकार को घेरने के लिए संसद के सदनों से बहिर्गमन (वॉकआउट) करने की तो परंपरा सी पड़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन की बुनियाद रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सबसे पहले गठबंधन से अलग हो गए। वैसे भी इंडिया गठबंधन में इतनी गांठें लगी हैं कि आसानी से खुल नहीं सकती। क्योंकि हर दल सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है। दक्षिणी राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन तक किया। उनका तर्क था कि यह योजना उत्तरी राज्यों को अनुचित लाभ पहुंचाएगी। विपक्ष दल लगातार मोदी सरकार पर राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए कठोर रणनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहते हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी, चुनाव आयोग को सरकार का हथियार बताते हैं ताकि जनता समझे की सरकार सीबीआई, आईटी और ईडी का उपयोग विपक्षी दलों को फंसाने या डराने के लिए करती है।

विपक्षी दलों का हैसटेग प्रोपेगेंडा

कांग्रेस सहित विपक्षी दल सोशल मीडिया का उपयोग सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने के लिए करते हैं, इसके लिए प्रोपेगेंडा हैसटेग का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। सरकार के खिलाफ झूठे नैरेटिव फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी से लेकर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाकी क्षेत्रीय दलों के नेताओं का सिर्फ एक ही एजेंडा है मोदी हटाओ। इसलिए बिहार में लालू प्रसाद यादव पर चारा चोरी, नौकरी के बदले जमीन हड़पने जैसे आरोप कांग्रेस के शासनकाल में लगे। उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, चारा चोरी के मामले में कांग्रेस के ही कार्यकाल में लालू यादव को सजा हुई, लेकिन लालू यादव आज उसी कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं जिसने उनका राजनीतिक करियर ही समाप्त किया है। यह सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, मोदी को हटाने के लिए हो रहा है। कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा की बात नहीं करते। न ही इन मुद्दों पर अपनी पार्टी की नीति और रणनीति बताते हैं, विकास का कोई रोड मैप नहीं बताते, बल्कि मोदी सरकार के साथ भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की कमियां खोजते हैं। भाजपा का विरोध करते करते विपक्षी दल भारत का विरोध करने लगते हैं। लेकिन जनता देश और प्रदेश बदलते देख रही है, शासन और कुशासन की तुलना कर रही है। इसलिए भाजपा और भाजपा का गठबंधन जीतता है। विपक्षी पहले ईवीएम हैक करने का आरोप लगाते थे, लेकिन ईवीएम को हैक करने की चुनाव आयोग की चुनौती के सामने भाग खड़े होते थे। अब चुनाव आयोग पर वोट चोरी का नया आरोप लगाना शुरू कर दिया। जिस बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट चोरी का नारा दिया वो नारा बिहार के चुनाव में गायब हो गया। इससे ही जनता समझती है कि यदि वोट चोरी का आरोप सही था तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या तेजस्वी ने इस नारे को चुनाव प्रचार में बुलंद क्यों नहीं किया? कुल मिलाकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे मोदी को हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।

नजरिया

आर्य समाज एक विचारधारा

आर्य समाज ने स्वतंत्रता सेनानियों को वैचारिक शक्ति प्रदान की, लाला लाजपत राय व शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश, राजनीतिक कारणों से, स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था।

हरिप्रकाश शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में चार दिवसीय कार्यक्रम में 39 देशों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्य समाज संप्रदाय से जुड़ा नहीं है बल्कि भारत की वैदिक विरासत और पहचान से जुड़ा है। आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ केवल किसी विशेष समुदाय या संप्रदाय का अवसर नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की वैदिक पहचान से जुड़ा उत्सव है। यह भारतीय दार्शनिक परंपरा से जुड़ा है, जिसमें गंगा के प्रवाह की तरह आत्म-शुद्धि की शक्ति है। यह अवसर सामाजिक सुधार की उस महान विरासत में निहित है जिसे आर्य समाज ने निरंतर आगे बढ़ाया है। आर्य समाज ने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को वैचारिक शक्ति प्रदान की थी। लाला लाजपत राय और शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कई क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश, राजनीतिक कारणों से, स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह वास्तविक हकदार था। जबकि अपनी स्थापना के समय से ही आर्य समाज निष्ठावान देशभक्तों की संस्था रही है, आर्य समाज ने निडरता से भारतीयता के सार को कायम रखा है और उसका प्रचार-प्रसार किया है। पीएम ने कहा कि चाहे भारत-विरोधी विचारधाराएं हों, विदेशी सिद्धांतों को थोपने के प्रयास हों, विभाजनकारी मानसिकताएं हों या सांस्कृतिक ताने-बाने को दूषित करने के प्रयास हों, आर्य समाज ने हमेशा उनका डटकर सामना किया है। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो निडरता से भारतीयता की बात करता है, दृढ़ राष्ट्रवादियों का संगठन है और जिसने हमेशा भारत-विरोधी विचारधारा और सांस्कृतिक प्रदूषण के कुत्सित प्रयासों को चुनौती दी है। मोदी ने आर्य समाज के सदस्यों से युवाओं को पांडुलिपियों का अध्ययन करने और मोटे अनाजों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

- **भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब देश में कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी, इन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सुधारवादी आंदोलन और कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू समाज में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था।**
- **क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह विशुद्ध आर्य समाजी थे, भगत सिंह के विचारों पर भी आर्य समाज के संस्कारों की छाप दिखाई पड़ती थी, सांडर्स को मारकर भगत सिंह पहले तो लाहौर के डीएवी कालेज में ठहरे, फिर कोलकाता जाकर आर्य समाज में शरण ली थी।**

आर्य समाज क्या है?

आज की पीढ़ी के जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर आर्य समाज है क्या? तो बताते हैं कि 'आर्य' का अर्थ है 'श्रेष्ठ', 'सभ्य' व 'कुलीन' एवं 'समाज' का अर्थ है लोगों का समूह अथवा सभा, अतः आर्य समाज का अर्थ है 'श्रेष्ठ जनों का समाज'। आर्य समाज एक विश्वव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों से लड़ना और उनका उन्मूलन करना है। युग पुरुष, वैदिक विद्वान, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले प्रथम व्यक्ति, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को महाराष्ट्र के गिरगांव (काकड़वाड़ी) में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी, जो अब अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर चुका है। भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय देश में कई तरह की कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। इन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए कई नेताओं ने तरह-तरह के आंदोलन चलाए। ऐसे ही एक सुधारवादी आंदोलन और कार्यक्रम की शुरूआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू समाज में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाजी शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है-'कृण्वन्तो विश्वमार्यम', जिसका अर्थ है विश्व को श्रेष्ठ बनाते चलो। आर्य समाज जैसे जागरूक मंच से दयानंद ने देश में फैली कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी मातृभूमि को विदेशियों से मुक्त कराने का आह्वान किया था। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को व्यावहारिकता देने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विश्व को जागृत करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की उसे ही 'आर्य समाज' कहा जाता है। आगे चलकर व्यवहार के स्तर पर आर्य समाज में दो धाराएं चली। एक वर्ग दयानंद एंग्लो वैदिक कालेज की विचारधारा की ओर चला गया और दूसरे ने 'गुरूकुल' की राह पकड़ ली।

देश के स्वतंत्रता-संग्राम में आर्य समाज ने संस्था के रूप में तो नहीं, पर सहसंस्था के अधिकांश प्रमुख सदस्यों ने व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देश की स्वतंत्रता में आर्य समाजियों की भूमिका अग्रणी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ आर्याभिविनयः में लिखा है- 'कोई अन्य देशवासी राजा हमारे देश में न हों, हम लोग पराधीन कभी न रहे।' इससे पता लगता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की क्या भावना थी। उन्होंने राष्ट्र के संगठन के लिए जात-पात के झंझटों को मिटाकर एक धर्म, एक भाषा और एक समान वेषभूषा व खान-पान का प्रचार किया। आज हिंदी भारत राष्ट्र की राजभाषा बन चुकी है। किंतु पूर्व में जब हिंदी का कोई विशेष प्रचार नहीं था, उस समय महर्षि दयानंद ने हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की घोषणा की, स्वयं गुजराती तथा संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हुए भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों की हिंदी में रचना की थी। दीर्घकालीन दासता के कारण भारतवासी अपने प्राचीन गौरव को भूल गए थे इसलिए महर्षि दयानंद ने उनके प्राचीन गौरव और वैभव का वास्तविक दर्शन कराया।

आर्य समाजी था भगत सिंह का परिवार

1857 के बाद के क्रांतिकारियों पर महर्षि दयानंद सरस्वती का काफी प्रभाव था। क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सेनापति बापट, मदनलाल धींगड़ा जैसे महर्षि दयानंद के शिष्यों ने स्वाधीनता आंदोलन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंग्लैंड में भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने प्रयास हुए वह श्याम जी कृष्ण वर्मा के 'इंडिया हाऊस' से हुए। अमेरिका में भारत की स्वाधीनता के लिए जो प्रयास हुए, वे भाई परमानंद के समर्पण और सहयोग का फल था। डीएवी कालेज लाहौर में इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार पंजाब के क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक रहे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह विशुद्ध आर्य समाजी थे और इनके पिता किशन सिंह भी आर्य समाजी थे, भगत सिंह के विचारों पर भी आर्य समाज के संस्कारों की छाप दिखाई पड़ती थी। सांडर्स को मारकर भगत सिंह पहले तो लाहौर के डीएवी कालेज में ठहरे, फिर योजनाबद्ध तरीके से कोलकाता जाकर आर्य समाज में शरण ली और आते समय आर्य समाज के चपरासी तुलसीराम को अपनी थाली यह कहकर दे आए थे कि 'कोई देशभक्त आए तो उसको इसी थाली में भोजन कराना।' दिल्ली में भगत सिंह, वीर अर्जुन अखबार के कार्यालय में स्वामी श्रद्धानंद और पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति के पास ठहरे थे क्योंकि उस समय ऐसे लोगों को ठहराने का साहस केवल आर्य समाज के सदस्यों में ही होता था।

सशस्त्र क्रांतिकारी दल के माध्यम से आर्यसमाज देश की स्वाधीनता के लिए प्रयास करने वाले देशभक्तों की मुहिम में अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता था, जिसका परिणाम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सामने आया।

स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग सभी स्थानों पर ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को यदि कहीं आश्रय, भोजन, निवास आदि मिलता था, तो वह किसी आर्यसमाजी के घर में ही मिलता था। सरकार के डर से प्रायः दूसरे लोग आश्रय देने का साहस नहीं कर पाते थे। हैदराबाद दक्षिण में निजाम सरकार के विरूद्ध (सत्याग्रह चलाकर) जनता के हितों की रक्षा केवल आर्यसमाजियों ने की थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता थे। राजस्थान केसरी कुंवर प्रताप सिंह बारहट, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, विष्णुशरण और उनके साथी पक्के आर्य समाजी थे, इनके संबंध में मन्मथ नाथ गुप्त ने जो स्वयं क्रांतिकारी थे, ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान के 13 जुलाई 1858 के अंक में लिखा था। फांसी के बाद राजेंद्र लाहिड़ी के शव का तो आर्यसमाजियों ने जुलूस निकाला था तथा सम्मानपूर्वक उसकी अंतयेष्टि की थी। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में आर्य समाज ने बढ़-चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि नेतृत्व भी किया। नेताजी सुभाष बोष द्वारा आजाद हिंद सेना का गठन किया गया, जो एक गौरवशाली स्वर्णिम अध्याय है। आजाद हिंद सेना के तीन प्रमुख नायकों में से सहगल आर्यसमाजी परिवार की ही देन थे। उनके पिता महाशय अछरू रामजी जाने माने आर्यसमाजी तथा कानूनविद थे। जब लाल किले में आजाद हिंद सेना पर अभियोग चला, तब इसके बचाव पक्ष के वकीलों की जो कमेटी बनी थी, उसमें बख्शी टेकचंद तथा दीवान बदरी दास के रूप में आर्यसमाज ने योगदान करके अपनी राष्ट्रनिष्ठा व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त सामान्य सैनिक के रूप में इस सेना में भर्ती होकर योगदान करने वाले आर्यसमाजियों की संख्या अनगिनत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सशस्त्र क्रांतिकारी दल के माध्यम से भी आर्यसमाज देश की स्वाधीनता के लिए प्रयास करने वाले देशभक्तों की मुहिम में अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। जिसका फल 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता दिवस के रूप में सामने आया। स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अछूतो को गले लगाने का कार्य, गोरक्षा, शिक्षा-प्रसार, स्त्री शिक्षा, विधवा उद्धार आदि सभी श्रेष्ठ कार्यों में आर्य समाज अग्रणी रहा है। देश-धर्म के लिए जो भी आंदोलन और सत्याग्रह हुए हैं उनमें आर्य जन सबसे आगे रहे हैं। आर्य समाज ने देश में अनेक सुधार कार्य किए जिनकी वजह से आज आर्य समाज को देश और विदेश में काफी सम्मान मिलता है। देश को आज भी ऐसे ही एक आंदोलन की जरूरत है, जो देश में नैतिकता की बयार ला सके। ●

प्राचीन मंदिर पर्यटन के नक्शे में नहीं

डोल क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर को लेकर विडंबना यह है कि तकनीकी कारणों से पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे ऐतिहासिक व संरक्षित धरोहरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वहीं पर्यटन के नक्शे में भी इस मंदिर का उल्लेख नहीं हो पाया है।

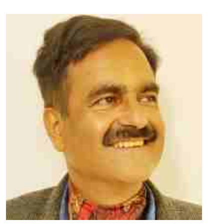
कमल कपूर
अल्मोड़ा

सनातन परंपरा में पंच देवों में से एक भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। पौराणिक कथाओं में श्री हरि पूजा से कष्टों के दूर होने और उनकी कृपा बरसने के कई प्रसंग मिलते हैं। मान्यता है कि पृथ्वी पर जब-जब पाप बढ़ते हैं उसे दूर करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। वैष्णव परंपरा को मानने वाले अपने आराध्य देव को अनंत शक्ति का धाम मानते हुए उनको अलग-अलग रूप में पूजते हैं। भगवान विष्णु के अलग-अलग स्वरूप या फिर कहें उनके अवतारों को समर्पित अनेकों मंदिर हैं, जहां पर दर्शन-पूजन करने पर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड के शहर फाटक में स्थित विष्णु भगवान का मंदिर कहने को ऐतिहासिक मंदिर है और अपार श्रद्धा का केंद्र है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर डोल क्षेत्र में भगवान विष्णु के इस प्राचीन मंदिर को लेकर विडंबना यह है कि तकनीकी कारणों से पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे ऐतिहासिक व संरक्षित धरोहरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वहीं पर्यटन के नक्शे में भी इस मंदिर का उल्लेख नहीं हो पाया है। इसके बावजूद इस घने देवदार के जंगलों के बीच इस देव दरबार के दर्शनों के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। भक्तजनों के बीच यह मंदिर श्री हरि विष्णु देव नागराज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भूमि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ नागों की भी पूजनीय स्थली है। उत्तराखंड में भगवान विष्णु के गिने-चुने मंदिर हैं जिनमें श्री हरि विष्णु देव नागराज मंदिर भी शामिल है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक व सुंदरता की दृष्टि से यह भू-भाग जितना पवित्र है उतना ही मनोरम भी है।

रहस्यमयी देवदार के वृक्षों में आस्था

यहां के हरे भरे देवदार के वृक्ष सदियों के रहस्यमयी इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। मंदिर की भांति ही देवदार के वृक्षों के प्रति भी लोगों में गहरी आस्था है। लोकमान्यता है कि इन वृक्षों को नुकसान पहुंचाने का कोई साहस नहीं करता है। यहां के देवदार के जंगल की लकड़ी भी कोई अपने घर नहीं ले जाता है। कहा जाता है कि यदि यहां की लकड़ी कोई अपने घर ले जाता है तो वहां सर्प व नागों का आवागमन होने लगता है। यही कारण है कि मंदिर क्षेत्र के वृक्ष भी पूजनीय है। मंदिर परिसर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ देवों के देव महादेव शिव की पूजा भी होती है। इस परिसर में स्थित शिवालय श्रद्धालुओं के लिए परम आस्था का केंद्र है। श्री हरि विष्णु देव नागराज मंदिर परिसर में ही अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियां व छोटे-छोटे देवी-देवताओं के स्थान भी स्थापित है। जिनके प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। इसी परिसर में मुख्य शक्ति स्थल के पास पानी का एक नौला भी है इसी नौले का जल श्री हरि विष्णु देव को समर्पित होता है। महंत अथवा पुजारी ही नौले में प्रवेश करके जल भरते है। यहां पूजा में पूर्ण शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह क्षेत्र पवित्र पावन नदी पद्मपर्णा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यह नदी अपनी महिमा के लिए प्रसिद्ध है। नदी के पास में ही एक कुंड भी हैं, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में खासतौर से मंदिर परिसर में यज्ञोपवीत कराने वाले परिवार स्नान करते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। श्री हरि विष्णु देव नाग मंदिर परिसर में एक छोटी सी गुफा भी है। जिसके अंदर देवी मां की मूर्ति विराजमान है। श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साधना की दृष्टि से यह गुफा काफी महत्वपूर्ण है।

मंदिर परिसर में देवदार के वृक्षों के प्रति भी लोगों में गहरी आस्था है, मान्यता है कि इन वृक्षों को नुकसान पहुंचाने का कोई साहस नहीं करता है, यहां के देवदार के जंगल की लकड़ी कोई अपने घर नहीं ले जाता, कहा जाता है कि यहां की लकड़ी कोई अपने घर ले जाता है तो वहां सर्प व नागों का आवागमन होने लगता है।

चमत्कारी देव दरबार

दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीनकाल में भगवान विष्णु का अभिषेक यहां एक देवदार के वृक्ष से निकलने वाले दूध से किया जाता था। जिस पेड़ से पहले दूध निकलता था वह पेड़ आज भी यहां मंदिर परिसर में मौजूद होने का दावा किया जाता है। प्राचीनकाल में यहां एक फूलों की छोटी सी बगिया भी थी, जिसके फूल भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते थे, लेकिन अब बगिया उजड़ चुकी है। इस चमत्कारी देव दरबार की एक और महिमा यह है कि जब कभी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो मंदिर परिसर के नौले से जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु मंदिर को अर्पित किया जाता है और वर्षा की प्रार्थना की जाती है। तब क्षेत्र में निश्चित ही वर्षा होती है और खुशहाली छा जाती है। मंदिर में बने हवन कुंड में जब कभी हवन अथवा यज्ञ होते है तब श्रद्धालुओं द्वारा आहूति दी जाती हैं। विशेष पर्वो पर यहां मेले भी आयोजित होते रहते है। स्कंद पुराण के मानस खंड में भगवान विष्णु के इस पवित्र धाम का वर्णन महर्षि वेद व्यास जी ने विराट आध्यात्मिक शब्दों में किया है। यहां श्री विष्णु जी के चरणों से निकली नदी को पद्मपर्णा, पदमावती कहा जाता स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख आया है। दंत कथाओं के अनुसार पद्मपर्णा नदी के उद्गम स्थल से प्रतिदिन एक रत्ती सोना उत्पन्न होकर बहने की बात भी स्थानीय बुजुर्ग बताते है, हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा प्रसिद्ध रामेश्वर तीर्थ की महिमा में भी यहां से निकली पनार नदी का उल्लेख है। भगवान विष्णु श्री हरि पद्मनाभ के श्री चरणों से निकली यह पावन नदी आगे चलकर अनेक नदियों से मिलती है। जिनमें सरयू के साथ रामेश्वर के प्रवेश द्वार में पनार नदी का मिलन होता है और इस मिलन में महादेव शिव का पूजन पितरों के उद्धार के लिए परम फलदायी माना गया है।

डोल एकादशी पर दीपदान से कर्ज उतरता है

प्राचीन अल्मोड़ा के डोल में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी के इस धाम की महिमा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। वैसे इस क्षेत्र का डोल नाम भी श्री विष्णु जी को बेहद प्रिय है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है उसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। महायज्ञ के समान फलदायी इस व्रत को रखने से जीवन के समस्त संकटों, कष्टों का विनाश हो जाता है। डोल के श्री हरि विष्णु धाम में डोल ग्यारस को श्री हरि का स्मरण, पूजन कीर्ति को बढ़ाने वाला कहा गया है। कहा जाता है कि डोल एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंदिर में दीपदान करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है तथा धन सम्पदा व वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए अल्मोड़ा जिले में यह पावन मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख भगवान श्री हरि विष्णु मंदिरों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। प्राचीन समय में इसे नागद्यो नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर की धर्मिक मान्यताएं स्कंद पुराण-मानस खंड के 58 वें अध्याय में इस प्रकार है...।

दारूकानन संलग्नो नाम्ना शाल्मती पर्वतः

पश्चिमे मुनि शाइला राजते नाम संशयः

अन्नापुण्याः सुसरितो बहतः सन्ति वै दिजाः

तपस्विनो महाभागाः सत्य धर्म परायणा।।

अर्थात सालम पर्वत के पश्चिम में पद्मगिरि नामक स्थान पर श्री हरि विष्णु भगवान का मंदिर है, जहां से पवित्र नदियां बहती हैं। जहां पर सत्यव्रती मुनियों एवं शिव ब्रह्मा का निवास है। वास्तव में यहां श्री विष्णु, शिव, ब्रह्मा के मंदिर हैं तथा कई स्थानों से जल धराएं (नौले) प्रवाहित होती हैं। लोकमान्यता के अनुसार यहां सूर्यकुंड से एक रत्ती सोना प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या काल में बहता है। यहां से पनार नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। पनार नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। स्कंद पुराण मानस खंड में इसकी पवित्राता इस प्रकार बताई गई है...।

निमज्यं पर्णपत्रायां त्रिरात्रां ये चरन्ति हि।

ते यान्ति विष्णुः सदनं पुनरावृति दुर्वाभम।।

अर्थात पनार (पदमावती नदी) में लगातार तीन दिन स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है, विष्णु लोक प्राप्त होता है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। पुराणों में वर्णित राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसी नागद्यो नामक स्थान पर हुआ है। राजा जन्मेजय द्वारा जब समस्त नागों का यज्ञ किया जा रहा था तब एक नाग अपने प्राण बचाने देवराज इंद्र के पास चला गया तथा इंद्रदेव से अपने वंश को बचाने की याचना की व इंद्र के सिंहासन में छिप गया। राजा जन्मेजय ने देवराज इंद्र से नाग, यज्ञ के लिए मांगा पर इंद्र ने शरणागत की रक्षा करते हुए नाग देने से इंकार कर दिया और नाग को अभयदान दे दिया। तब राजा जन्मेजय को क्रोध आ गया। उसने यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से इंद्र को सिंहासन सहित होम कर देने को कहा। ब्राह्मणों के तप से इंद्र सिंहासन सहित नागद्यो नामक स्थान पर आ गए। इस प्रकार के अनर्थ को बचाने के लिए यहां पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। उन्होंने चैरासी लाख योनियों में से एक योनि सांप वंश के समाप्त होने पर चिंता प्रकट की तथा जन्मेजय को समझाया तब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के बीच बचाव से नाग वंश की रक्षा हो सकी, लेकिन सांप जाति को श्राप दिया गया कि जा आज से तू बच्चों को स्वयं खा लेगा। लोक कहावत भी है कि सांप अपने बच्चे स्वयं खा लेता है।

- **जब कभी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो मंदिर परिसर के नौले से जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु मंदिर को अर्पित किया जाता है और वर्षा की प्रार्थना की जाती है, तब क्षेत्र में निश्चित ही वर्षा होती है और खुशहाली छा जाती है।**
- **प्राचीनकाल में भगवान विष्णु का अभिषेक यहां एक देवदार के वृक्ष से निकलने वाले दूध से किया जाता था, जिस देवदार के पेड़ से पहले दूध निकलता था वह पेड़ आज भी यहां मंदिर परिसर में मौजूद होने का दावा किया जाता है।**

इस मंदिर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़े पत्थर की गुफा है। जिसे 'नागचुला' कहा जाता है। प्राचीन समय में श्री हरि विष्णु मंदिर के अंदर से नागचुला तक अंदर ही अंदर रास्ता था, जिससे होकर पुजारी दोनों जगह पूजा करते थे। परंतु वर्तमान में गुफा में मात्र रास्ते का निशान बचा है। जिसे स्पष्ट कर पाना कठिन है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं, न ही कोई पुरातात्विक धरोहर है। लोकमान्यता है कि सदियों पूर्व भाजा और भूप सिंह फर्तयाल जाति के दो भाईयों ने लोहाघाट से यहां आकर यह श्रमदान से मंदिर बनवाया और यहीं बस गए। बाद में नव निर्माण लोगों द्वारा किए गए हैं। जिससे प्राचीन पुरातात्विकता का मापदंड समाप्त हो गया। जिस कारण पुरातन विभाग के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत यह मंदिर नहीं आ सका और न ही पर्यटन के मानचित्र पर। सरकार चाहे तो इस एतिहासिक मंदिर को भविष्य में पर्यटन का प्रमुख आकर्षण एवं धर्मिक आस्था का पावन संगम बना सकती है। जिससे तीर्थाटन निश्चित ही बढ़ेगा और क्षेत्र खुशहाल होगा।

वन्यजीव मानव संघर्ष

2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ तब से लेकर सितंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में लेपर्ड, हाथी, बाघ, भालू, सांप, जंगली सूअर, बंदर, लंगूर, मगरमच्छ, ततैया, मॉनिटर छिपकली जैसे वन्यजीवों के हमलों में 1256 इंसानों की मौत हुई है।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

उत्तराखंड जैव विविधता से समृद्ध राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य से इस पहाड़ी राज्य में पिछले एक दशक में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विशेष रूप से तेंदुओं द्वारा आवासीय क्षेत्रों में प्राणघातक हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। जंगलों में बाघों की बढ़ती आबादी तेंदुओं को जंगल से बाहर खदेड़ रही है। इसलिए तेंदुए मानव आबादी में घुस रहे हैं। जिससे मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जंगल और आबादी के बीच तेंदुए इंसानों और बाघों की नजरों से बचकर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेंदुओं की इस दशा को लेकर वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही उससे सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग में भी 57 बाघों की मौजूदगी है। तराई के जंगलों में तेजी से बढ़ती बाघों की संख्या तेंदुओं के लिए खतरा बन रही है। बाघ अब तेंदुओं के घर यानी जंगल के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। ऐसे में बाघ, तेंदुओं को जंगल से खदेड़कर आबादी की ओर जाने के लिए विवश कर रहे हैं। तेंदुए मानव आबादी में घुस कर कुत्ते-बिल्ली तथा पालतू पशुओं का शिकार करने को मजबूर हैं। कई बार भूखे तेंदुए मानव पर हमला कर देते हैं। जिससे वन्यजीव-मानव संघर्ष की घटनाएं इंसानों के लिए जनहानि और शारीरिक जख्म के रूप में देखी जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वन्यजीव के हमले के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कभी कोई बात नहीं होती। नतीजा ये होता है कि वन्यजीव के हमले से घायल लोगों के शारीरिक जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन मानसिक आघात से उन्हें जीवन भर गुजरना पड़ता है। उत्तराखंड के सैकड़ों परिवार खूंखार वन्यजीवों के हमलों से पीड़ित हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है तो बहुत से घायल लोग सालों तक उस खौफ को अपने जहन से निकाल नहीं पाए हैं। ये हालात न केवल हमले के बाद जीवित रहने वालों की जिंदगी को डिस्टर्ब कर देती है, बल्कि उनके रोजगार और जीवनशैली को भी प्रभावित करती है। राज्य में ऐसे एक या दो मामले नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के बाद जो लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना होता है। क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद कई लोग अवसाद का शिकार हो जाते हैं। जिससे उन्हें पूरी जिंदगी मानसिक रूप से कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है।हालांकि प्रमुख वन संरक्षक कहते हैं कि इसके लिए पहली बार वन विभाग डॉक्टरों से भी बात करते हुए इसके हल पर काम करने का प्रयास कर रहा है।

इसी साल 27 मार्च को राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्तराखंड में होने वाली जनहानि का मुद्दा उठाया था, उन्होंने ऐसे नरभक्षी वन्यजीव के शीघ्र उन्मूलन के लिए नियमों में सुधार की केंद्र सरकार से मांग की है।

दस साल में 1256 लोगों की मौत

71.05 प्रतिशत वन भू-भाग वाले उत्तराखंड में आए दिन वन्यजीवों के हमले सुर्खियां बनते हैं। यद्यपि इसकी रोकथाम के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस सबको देखते हुए समस्या के समाधान के लिए अब तात्कालिक के साथ ही दीर्घकालिक उपायों पर आगे बढ़ने की योजना है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ तब से लेकर सितंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में लेपर्ड, हाथी, बाघ, भालू, सांप, जंगली सूअर, बंदर, लंगूर, मगरमच्छ, ततैया, मॉनिटर छिपकली जैसे वन्यजीवों के हमलों में 1256 इंसानों की मौत हुई है। मानव-वन्यजीव संघर्ष का सबसे बड़ा कारण जंगलों का सिमटता दयारा है। यानी वन्यजीवों का जो घर है उसका दायरा कम होता जा रहा है। इंसान अपनी मानव बस्ती बढ़ाते जा रहे हैं। कभी विकास के नाम पर तो कभी खेती के नाम पर या फिर कभी मानव बस्तियां बसाने के नाम पर जंगलों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। यही वजह है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष में तेजी से वृद्धि हो रही है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण आर्थिक नुकसान, सुरक्षा जोखिम, भोजन और जल की कमी, संरक्षण और विकास में टकराव पैदा हो रहा है। जिसमें आर्थिक नुकसान में फसल और मवेशियों की क्षति होती है। साथ ही बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। संसाधनों के लिए भी मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष होता है। विशेष रूप से जल स्रोतों के लिए, जो मानव समाज और वन्यजीवों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वन्यजीवों की वजह से गांव खाली हुए

मानव तथा वन्यजीव अस्तित्व के समाधान के लिए एक नीतिगत पहल होनी चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना, संघर्ष से होने वाले नुकसान के लिए पुख्ता योजना बनाने और ग्राम स्तर पर ही अंतर विभागीय समितियां का गठन होना चाहिए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाया जा सकता है। यह इंसानों के लिए खेती के लिए और रेलवे ट्रैक पर कारगर सिद्ध हो सकता है। निगरानी के लिए ड्रोन और सामुदायिक जन जागरूकता के लिए हॉटलाइन नंबर्स का उपयोग किया जा सकता है। समुदाय आधारित दृष्टिकोण भी आवश्यक है, यानी स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करना और उनके पारंपरिक ज्ञान को महत्व देना जरूरी है। बुनियादी ढांचे का निर्माण भी पुख्ता किया जाना चाहिए। जानवरों को मानव बस्तियों से दूर रखने के लिए अवरोधों या फिर बाड़ों या सोलर फेंसिंग का निर्माण करना होगा। शहरों के विस्तार के कारण या फिर शहरों की प्लानिंग में पर्यावरण और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके ही इसकी योजना बनानी होगी। जन जागरूकता और शिक्षा, मानव-वन्यजीव अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण समाधान है। जिसमें लोगों को वन्यजीवों के महत्व और संघर्ष के समाधान के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। चाहे वह स्कूल हो या फिर गांव की पंचायत। क्योंकि उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव सबसे ज़्यादा होता है। पहाड़ी राज्य में गुलदार और भालू के हमलों से लोग दशकों से परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में 1256 से ज़्यादा लोगों की जान ऐसे हमलों में जा चुकी है, जबकि 6433 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें लेपर्ड द्वारा 543, हाथियों द्वारा 230, बाघ द्वारा 105, भालू द्वारा 69, सांप द्वारा 260, जंगली सूअर द्वारा 29, मगरमच्छ द्वारा 9, सियार द्वारा एक, ततैया द्वारा 9 और मॉनिटर छिपकली के हमले से एक व्यक्ति की मौत हुई है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में गुलदार, भालू और बंदरों के बढ़ते आतंक के कारण लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कई गांव तो लगभग खाली हो चुके हैं। क्योंकि वन्यजीवों के हमले में मारे गए लोगों और घायलों का यह आकंड़ा वास्तव में परेशान और हैरान करने वाला है।

सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता

विशेषज्ञों का कहना है कि वन्यजीव के हमले से प्रभावित लोगों के लिए केवल मुआवजा बढ़ाना काफी नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जंगलों से सटे गांवों में सुरक्षा उपाय, जागरूकता अभियान और मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन योजना को जमीन पर उतारा जाना चाहिए। मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए समर्पित एक नई शाखा भी स्थापित की गई है। सूचना के त्वरित प्रसार के लिए टोल-फ्री नंबर को और अधिक सक्रिय और डिजिटल प्रणालियों से एकीकृत किया गया है। हालांकि ये कदम मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। विशेषज्ञ संघर्ष वृद्धि के लिए विभिन्न पारिस्थितिक और मानवीय कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वन विभाग इस समस्या से निपटने के लिए जन जागरूकता को एक प्रमुख रणनीति के रूप में महत्व देता है। विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि जंगलों के भीतर बड़े पैमाने पर अघोषित वनों की कटाई और हिरण, काकड़ आदि जैसे वन्यजीवों का अवैध शिकार जंगली जानवरों को भोजन और पानी की तलाश में जंगलों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक दीर्घकालिक रणनीति जरूरी है। राज्य में वन्यजीव आवासों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों को देखते हुए सह-अस्तित्व के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आवास पुर्नस्थापन, सख्त शहरी नियोजन और निरंतर जनभागीदारी पर जोर दिया जाए। मानव-वन्यजीव से संबंधित वर्तमान स्थिति इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है।

- **बाघ. तेंदुओं को जंगल से खदेड़कर आबादी की ओर जाने के लिए विवश कर रहे हैं, लिहाजा तेंदुए मानव आबादी में घुस कर कुत्ते-बिल्ली तथा पालतू पशुओं का शिकार करने को मजबूर हैं, कई बार भूखे तेंदुए मानव पर हमला कर देते हैं, जिससे जनहानि होती है।**
- **विशेषज्ञों का दावा है कि जंगलों के भीतर बड़े पैमाने पर अघोषित वनों की कटाई और हिरण, काकड़ आदि जैसे वन्यजीवों का अवैध शिकार जंगली जानवरों को भोजन और पानी की तलाश में जंगलों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है।**

राज्यसभा में गूंजा संघर्ष का मुद्दा

इसी साल 27 मार्च को राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्तराखंड में होने वाली जनहानि का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे नरभक्षी वन्यजीव के शीघ्र उन्मूलन के लिए नियमों में सुधार की केंद्र सरकार से मांग की। सदन में अनुपूरक प्रश्न के जरिये उन्होंने देवभूमि की इस गंभीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ऐसी दुर्घटनाओं में हुई मानव क्षति के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 161 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिसमें तेंदुए ने 66, हाथी ने 28, बाघ ने 13, भालू ने पांच तथा सांप ने 14 लोगों को शिकार बनाया है। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इन घटनाओं के दोषी नरभक्षी जानवरों के उन्मूलन के लिए अनुमति मिलने में कई बार देर हो जाती है। उन्होंने पूछा क्या सरकार इस संबंध में नियमों को लेकर शिथिलता देने पर विचार कर रही है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर में कहा कि वन्यजीव अधिनियम के तहत, शेड्यूल 1 में आने वाली प्रजाति को लेकर वन्यजीव अधिकारी को ही ऐसे जानवरों को मारने की अनुमति देने का अधिकार है। दूसरी श्रेणी में आने वाले जानवरों को लेकर ये अधिकारी इस अनुमति को नीचे भी स्थानांतरित कर सकते हैं।

छोटे से गांव में कार्तिके मंदिर

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में छोटा सा कनकचौरी गांव है जिससे 3 किलोमीटर की छोटी पैदल यात्रा करके कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचते हैं, 3 किलोमीटर का यह ट्रैक उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से भी रुबरु कराता है, यहीं 200 साल पुराना कार्तिक स्वामी मंदिर हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है।

हरीश भट्ट
रामनगर

वैसे तो उत्तराखंड खूबसूरती का खजाना है, लेकिन यहां कई ऐसे धार्मिक स्थल है, जहां दूर-दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। उत्तराखंड असंख्य मंदिरों का घर है, जिनमें से कई पौराणिक काल से संबंध रखते हैं। इस हिमालय की घाटी में सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि अन्य देवी-देवताओं के मंदिर भी हैं, ऐसा ही पौराणिक काल का मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है जो शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर को लेकर कई ऐसी मान्यताएं और कथा है, जिनकी जानकारी आम तौर पर लोगों को कम ही होती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में घूमने आए लोग बिना इस मंदिर में मत्था टेके वापस नहीं जाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में छोटा सा कनकचौरी गांव है जिससे 3 किलोमीटर की छोटी पैदल यात्रा करने के बाद कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचा जा सकता है। 3 किलोमीटर का यह ट्रैक उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से भी रूबरू कराता है। यहीं 200 साल पुराना कार्तिक स्वामी मंदिर हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। स्थानीय ग्रामीण कार्तिक स्वामी मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना बताते हैं। गढ़वाल में यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3050 मीटर ऊंचाई पर है। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक किवदंती है। कहा जाता है कि इस जगह पर कार्तिक ने अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित की थी। शिव पुराण में केदारखंड के कुमार खंड में वर्णित है कि भगवान शिव ने एक बार अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए कार्तिकेय और गणेश को ब्रह्मांड के सात चक्कर लगाने के लिए कहा था और भागवान शिव ने कहा था कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा उसे सभी देवी देवताओं से पहले पूजने का सौभाग्य मिलेगा। लिहाजा भगवान कार्तिके ने अपनी सवारी मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गए। गणेश जी ने अपनी सवारी मूसे पर सवार होकर भगवान शिव और पार्वती के चारों ओर यह कहते हुए परिक्रमा लगाई कि उनके लिए तो माता-पिता ही ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव और पार्वती उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें अपने वचनानुसार वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले समस्त देवी-देवताओं के इतर सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। यानी भगवान गणेश को सबसे पहले पूजने का आशीर्वाद और सौभाग्य मिला। ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे कार्तिके को जब पता चला कि गणेश को पहले पूजने का सौभाग्य मिला है तो उन्होंने क्रोधित होकर श्रद्धा के रूप में अपने शरीर के मांस और हड्डियों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए उत्तराखंड के पौराणिक महत्व के मंदिर में भगवान कार्तिके की अस्थियों की पूजा की जाती है। गढ़वाल के रुद्रप्रयाग में स्थित, मंदिर में संगमरमर की चट्टान पर कार्तिक स्वामी की प्राकृतिक रूप से नक्काशीदार मूर्ति है। चारों ओर एक गहरी घाटी के साथ एक संकीर्ण रिज के अंत में ये मंदिर हिमालय के क्रौंच पर्वत का शानदार 360 डिग्री दृश्य दिखाता है। संध्या आरती या शाम की प्रार्थना, मंत्रों का जाप और मंदिर में आयोजित महा-भंडारा या भव्य उत्सव कभी-कभी भक्तों और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण होते हैं।

12 महीने खुलता है कार्तिके मंदिर

कार्तिके का यह मंदिर बारह महीने भक्तों के लिए खुला रहता है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना व सर्दियों में बर्फ लिए रहता है। मंदिर परिसर से हजारों फीट नीचे घाटी में देखने पर सुंदर गांव दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने कोई सुंदर सा पोट्रेट बनाकर घाटी में छोड़ दिया हो। मौसम की एक करवट बदलते ही सारे बादल घाटी में तैरने लगते हैं और जैसे ही बादल छंटते हैं सूर्य की किरणों तले धवल पर्वत श्रेणियां चमक उठती हैं। प्रकृति का यह नजारा कार्तिके स्वामी मंदिर से 360 डिग्री का ऐसा दृश्य देता है जो आपको एक अद्भुत अनुभव व रोमांच से भर देता है। मंदिर के आसपास का मौसम यदि साफ होता है तो हिमालय की तमाम चोटियां जैसे चौखंबा, मद्यमहेश्वर, केदार पर्वत, मेरु-सुमेरु पर्वत, त्रिशूल, पंचाचूली, नीलकंठ, नंदा देवी, कामेट, नंदाघुंटी, रुद्रनाथ, दूनागिरी, कौसानी आदि का चौतरफा खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। कहते हैं इस मंदिर से हिमालय की लगभग 80 प्रतिशत चोटियां साफ नजर आती हैं। मंदिर के रास्ते में दोनों ओर खूबसूरत बांज के जंगल, बुरांश के पेड़ व पक्षियों का कलरव आपकी यात्रा में इतनी सुगमता व मनोरमता भर देता है कि पता ही नहीं चलता कब आप हिमालय की गोद में स्थित क्रौंच पर्वत पर बसे इस मंदिर के आहाते तक पहुंच जाते हैं। कार्तिके स्वामी मंदिर तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग-पोखरी मार्ग पर रुद्रप्रयाग से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर कार्तिके स्वामी का मंदिर है। रुद्रप्रयाग से टैक्सी भी किराए पर ली जा सकती है या साझा टैक्सी ले सकते हैं।

कार्तिके स्वामी का विशाल भंडार

दक्षिण भारत में भगवान कार्तिके को बाल्य रूप में छह तीर्थों में पूजा जाता है, मगर उत्तराखंड में भगवान कार्तिके का एकमात्र तीर्थ क्रौंच पर्वत पर विराजमान है। क्रौंच पर्वत के आंचल तथा प्रकृति की अत्यंत सुरम्य वादियों में बसे उसनतोली बुग्याल के निकट बीहड़ चट्टान पर एक गुफा में भगवान कार्तिक स्वामी का प्राचीन भंडार होने का दावा किया जाता है। हालांकि भंडार की अत्यधिक ऊंचाई के कारण इसके दर्शन करना दुर्लभ है। ऐसी मान्यता है कि इस भंडार से एक मार्ग कुबेर पर्वत की ओर जाता है। युगों पूर्व इस भंडार के दर्शन भगवान कार्तिके स्वामी के दो परम उपासक ही कर पाए थे। ऐसी मान्यता है कि बीहड़ चट्टानों के बीच इस भंडार में भगवान कार्तिके स्वामी के अनमोल बर्तन हैं। स्थानीय पंडितों के अनुसार इस तीर्थ के चारों तरफ 360 गुफाएं और 360 जलकुंड हैं। इन गुफाओं में आज भी अदृश्य रूप में साधक जगत कल्याण के लिए साधना करते हैं। क्रौंच पर्वत तीर्थ से लगभग तीन किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा उसनतोली बुग्याल के पास बीहड़ चट्टान के मध्य भगवान कार्तिके स्वामी के प्राचीन भंडार की अपनी विशिष्ट पहचान है। मान्यता के अनुसार इस भंडार में भगवान कार्तिक स्वामी का अमूल्य भंडार है। इसलिए इस जगह का नाम भंडार पड़ा।

ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे कार्तिके को जब पता चला कि गणेश को पहले पूजने का सौभाग्य मिला है तो उन्होंने क्रोधित होकर श्रद्धा के रूप में अपने शरीर के मांस व हड्डियां भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दी, इसलिए पौराणिक महत्व के इस मंदिर में भगवान कार्तिके की अस्थियों की पूजा की जाती है।

शिव पुराण में केदारखंड के कुमार खंड में वर्णित है कि भगवान शिव ने एक बार अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए कार्तिके और गणेश को ब्रह्मांड के सात चक्कर लगाने के लिए कहा था, भागवान शिव ने कहा था कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा उसे सभी देवी देवताओं से पहले पूजने का सौभाग्य मिलेगा।

कहा जाता है कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व उसनतोली बुग्याल में एक पशुपालक रहता था। वह हमेशा भगवान कार्तिक स्वामी की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन भगवान कार्तिके स्वामी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में प्राचीन भंडार के दर्शन करवाए। एक और मान्यता है कि युगों पूर्व एक नेपाली साधक अपनी तपस्या के बल पर भंडार के दर्शन कर चुका था। इनके अलावा आज तक तीसरे व्यक्ति ने इस भंडार के दर्शन नहीं किए हैं। स्थानीय मतानुसार पूर्व में जब भगवान कार्तिके स्वामी की देवता पूजा करते थे तो इस भंडार से तांबे के बर्तन निकाल कर अनेक पकवान बनाए जाते थे। पकवान बनाने के बाद पुनः बर्तनों को भंडार में रखा जाता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्राचीन भंडार में असंख्य धातुओं का भंडार है, जिसका अनुमान आज तक नहीं लगाया जा सका है।

प्रकृति की गोद में कनकचौरी गांव

रुद्रप्रयाग जिले में बसा अनोखा गांव कनकचौरी ऐसा छिपा हुआ रत्न है जो अपने मनमोहक दृश्यों, जीवंत संस्कृति और स्वागतशील स्थानीय लोगों के लिए प्रसिद्ध है। कनकचौरी उन लोगों के लिए अनूठा अनुभव प्रदान करता है जो भारत के अनछुए खजानों को देखना चाहते हैं। समुद्र तल से लगभग 1,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, कनकचौरी से आसपास की हिमालय पर्वतमालाओं का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह गांव हरे-भरे जंगलों, लुढ़कती पहाड़ियों और सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनोरम स्थल बनाता है। ताजी पहाड़ी हवा और शांत वातावरण विश्राम और स्फूर्ति के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कनकचौरी गांव अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। यह क्षेत्र औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों से समृद्ध है, जिनका उपयोग सदियों से पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धतियों में किया जाता रहा है। कनकचौरी के आसपास के जंगलों में विभिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते हैं, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। यह क्षेत्र अपनी जीवंत तितलियों की आबादी के लिए भी जाना जाता है, जो यहां के परिदृश्य में रंगों की एक झलक भर देता हैं। गांव में कई नदियां और झरने हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। अलकनंदा की एक सहायक नदी मंदाकिनी पास में ही बहती है, जो मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने जैसी गतिविधियों के अवसर देती है। कीर्तिनगर झरने जैसे झरनों की कलकल ध्वनि क्षेत्र के शांत वातावरण में चार चांद लगा देती है। कनकचौरी गांव गढ़वाली लोगों की पारंपरिक जीवनशैली का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर देता है। यहां के ग्रामीण अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगंतुकों के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पत्थर और लकड़ी के घरों से बनी स्थानीय वास्तुकला क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और पहाड़ी वातावरण को दर्शाते हैं। कनकचौरी की सांस्कृतिक जीवंतता स्थानीय त्योहारों और समारोहों के दौरान सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दिवाली, होली और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के दौरान यह गांव संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठनों से जीवंत हो उठता है। ये आयोजन क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रदर्शित करते हैं। कनकचौरी का स्थानीय व्यंजन खाने के शौकीनों के लिए एक आनंददायक अनुभव होता है। यहां का खाना सादा लेकिन स्वादिष्ट होता है, जो स्थानीय सामग्री से तैयार किया जाता है। काफुली (पालक से बना व्यंजन), चैनसू (काले चने की दाल से बना व्यंजन) और आलू के गुटके (मसालेदार आलू से बना व्यंजन) जैसे पारंपरिक व्यंजन जरूर आजमाएं। इस क्षेत्र की स्थानीय जड़ी-बूटियों और मसालों का इस्तेमाल खाने में एक अनोखा स्वाद भर देता है। कनक चौरी की यात्रा जड़ी-बूटियों से बनी और गुड़ के साथ परोसी जाने वाली स्थानीय चाय का स्वाद लिए बिना अधूरी है।

समीक्षा

जीवनीय दर्शन बताती कविताएं

गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा-संगीत के विकास की बात करने वाले मुखर तो हो रहे हैं, पर सामाजिक व्यवहार में लाने में उनमें से अधिकांश के प्रयास बस किताबी ही हैं, लोक साहित्यकार संदीप रावत जैसे विरले ही हैं जो गढ़वाली साहित्य रचने से ज्यादा उसको गढ़वाली समाज की जीवंत भाषा बनाने के लिए जवान हो रही पीढ़ी और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं।

अमूमन यह कहा जाता है कि जो समाज में प्रचलित और घटित हो रहा है, वह उसके समसामयिक साहित्य में स्वतः प्रकट हो जाता है। परंतु इस धारणा के विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि जो सामाजिक प्रचलन में अप्रासंगिक हो रहा है, ठीक उसी समय उसकी अभिव्यक्ति तत्कालीन साहित्य और संगीत में प्रमुखता से होने लगती है। सोशल मीडिया और आधुनिकता के दौर में लोक भाषाएं और लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य सामाजिक व्यवहार से हट रहे हैं, परंतु लोकभाषा और लोक संगीत रचने का शोर चहुंओर है। गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा-संगीत के विकास की बात करने वाले आए दिन और मुखर हो रहे हैं, पर उसको सामाजिक व्यवहार में लाने में उनमें से अधिकांश के प्रयास बस किताबी या मौखिक ही हैं। लोक साहित्यकार संदीप रावत जैसे विरले ही हैं जो गढ़वाली साहित्य रचने से ज्यादा उसको गढ़वाली समाज की जीवंत भाषा बनाने के लिए आम लोगों विशेषकर जवान हो रही पीढ़ी और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। संदीप रावत कवि, गीतकार, गितार, विज्ञान शिक्षक और शोधार्थी हैं। गढ़वाली कविता, गीत, कहानी, शोध-लेखन, व्यंग और समीक्षाएं संदीप रावत के रचना संसार के प्रमुख आधार हैं। संदीप रावत की चर्चा उनके खबरसार पत्र में धारावाहिक लेख 'गढ़वाली भाषा कि ऐतिहासिक विकास यात्रा' से साहित्य बिरादरी में हुई। उनकी रचनाएं सामाजिक सरोकारों में आ रहे बदलावों की तरफ पाठ्कों को ले जाती हैं। लोक परंपराओं के टूटने का दर्द उनकी कहानियों और कविताओं का एक मुख्य हिस्सा होता है। मानवीय संवेदनाओं से लबालब इस युवा साहित्यकार से गढ़वाली साहित्य के और समृद्ध होने की आशा बलवती होती है। संदीप आकाशवाणी और दूरदर्शन के नियमित वार्ताकार हैं।

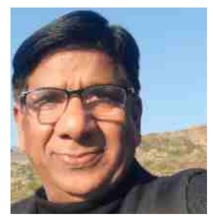

अरुण कुकसाल
चामी, पौड़ी गढ़वाल

संदीप रावत की प्रकाशित रचनाओं में 'एक लपाग' (गढ़वाली कविता-गीत संग्रह), 'गढ़वाली भाषा अर साहित्य कि विकास जात्रा' और 'लोक क बाना' (शोधपरक गढ़वाली निबंध संग्रह), 'उदरोळ' (गढ़वाली कथा संग्रह), 'तू हिटदि जा' (गढ़वाली गीत संग्रह), 'आखर' (दिसा-धियाण्यूं का प्रथम गढ़वाली कविता संग्रह) और 'तीस' (गढ़वाली कविता संग्रह) शामिल हैं। संदीप रावत की 'एक लपाग' (गढ़वाली कविता-गीत संग्रह) प्रथम प्रकाशित कृति है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत एक लपाग (कदम) से होती है। और संदीप ने साहित्य के क्षेत्र में 'मुझण न दे जिकुड़ि की आग, मार त सैहि एक लपाग' के मजबूत इरादों से की है। 'गढ़वाली भाषा अर साहित्य कि विकास जात्रा' और 'लोक क बाना' (शोधपरक गढ़वाली निबंध संग्रह) गढ़वाली भाषा-साहित्य के ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से लोक साहित्य के जानकार एवं शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शी की भूमिका में हैं। 'उदरोळ' (गढ़वाली कथा संग्रह) कहानियों के माध्यम से गढ़वाली जन-जीवन की खूबसूरती और उसकी खामियों को बताने में कोई संकोच नहीं किया है। 'तू हिटदि जा' (गढ़वाली गीत संग्रह) की कविताएं और कहानियां गीतमय निरंतरता के प्रवाह में आगे बढ़ती हैं। 'आखर' (दिसा-धियाण्यूं का प्रथम गढ़वाली कविता संग्रह) कविता संग्रह के संपादन में उनके साथ साहित्यकार गीतेश सिंह नेगी शामिल हैं। गढ़वाली में प्रथम महिला कवियत्री विद्यावती डोभाल (तीन गढ़वाली गीतिका' विद्यावती डोभाल प्रकाशन वर्ष-1975 से गढ़वाली कवित्रियों का कविता लेखन प्रारंभ माना जाता है।) से लेकर आने वाली पीढ़ी की संभावनाशील कवियत्री प्रिय रवीना राणा की कविताओं की काव्ययात्रा का यह एक बेहतरीन प्रस्तुतीकरण है।

'तीस' (गढ़वाली कविता संग्रह) संदीप रावत की नवीनतम रचना है। उत्तराखंड संस्कृति विभाग के आंशिक आर्थिक सहयोग से रावत डिजिटल, बुक पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद द्वारा वर्ष- 2024 में प्रकाशित 104 पृष्ठों के इस कविता संग्रह में 78 छोटी-छोटी कविताएं और 18 क्षणिकाएं हैं। पुस्तक में सुपरिचित साहित्यकार गीतेश सिंह नेगी की बेहतरीन भूमिका है। साथ ही डॉ. नन्द किशोर ढौंडियाल ने संदीप रावत के संपूर्ण लेखन पर सजीव और सटीक टिप्पणी की है। 'सै बात त य छ कि जथगा बानि का मनखि, उतगै बानि तीस। अलग-अलग लोगूं अलग-अलग तीस, बनि-बनि तीस। जख पाण्या तीसन् हमारि गौळि सुखि जान्द त वखि हौरि बानिक तीस हमारि गुद्धि-बुद्धि बि सुखै जान्द, मन तैं बि उबै जान्द। जिंदगि भर हमारि तीस बुझदि ही नी। पण ! असल बात त य बि छ कि 'तीस' ही एक पर्चो बि छ मनखि को ज्यूंदो होणा कु।' ये सच है कि मानव की जीवंतता का मूल आधार उसके जीवन जीने की 'तीस' (प्यास) की प्रबलता पर निर्भर करता है। जीवनभर ये तीस खत्म नहीं होती है। इसका समाप्त होना मतलब जीवन का समाप्त होना है-

औवु सब जगौं मेरू नाम, होवु सब जगौं मरि हाम,...
लोग कर्यां मरि जै-जै कार, य तीस अब बढ़दै जाणी,
एक चाऽना खत्म होणी, झट्ट हैंकि उपजि जाणी
यि चाऽना अब मि तैं, भितरैं-भित्र खाणी...।

संदीप ने आदमी की 'तीस' उत्पन्न होने की विविध मनोवृत्तियों से उसकी असल मनोवृत्ति को कविताओं में उभारा है। तीस में ही छिपा है जीवन का आनंद और वही उसके अवसान का भी आधार है। ये आदमी पर निर्भर है कि उसकी तीस जनकल्याण की है या स्वार्थपरख है। जीवनीय इच्छाओं के लिए विशालता की नहीं मधुरता की जरूरत होती है-

समोदर भौत बड़ो, पण ! रूखो अर खारो,
पंदेरु छ्वटो सि अर छाळो,
पण ! ना झाणि, कथगौं कि, तीस बुझाळो...।

'तीस' कविता संग्रह में छोटी-छोटी कविताएं हैं। अपने स्वभाव में हर समय एक मधुर मुस्कान लिए यह संकोची युवा कवि अपनी कविताओं में प्रखरता से पाठकों की ओर मुखातिब होता है। गढ़वाली भाषा के भूले-बिसरे शब्दों की जीवन्तता ने संदीप की कविताओं को बखूबी सजाया-संवारा है। ये छोटी-छोटी कविताएं जीवनीय संचेतना को बखूबी उद्घाटित करती हैं।

जिंदगि कि दौड़ मा, जो पिछनै छन खड़ा, पण ! सच्चा,
तड़तड़ा, अऽर खड़खड़ा, दरअसल् वी छन बड़ा... ।

संदीप की कवितायें सार-सलाह-संचेतना से आगे जीवन के गूढ़ दर्शन को सहजता से बताती हैं। संदीप कहते हैं कि 'पाणि सि ब्वगणू बगत, फिर्बि नि छौ समझणा...'। जीवन को सार्थक बनाने की राह आसान नहीं है। इसलिए हम मनुष्यों की भीड़ का एक हिस्सा मात्र न बन कर रह जाएं-

बगत का अणस्येळा मा, खूब तप्येंदु अर धुप्येंदु,
कर्मों का सिलोटा मा, खूब थिंच्येंदु अर पिस्येंदु।
तब जैकि आन्द 'मनखि' परैं, मनखि सि अन्वार,
अर ! खुलदन वे कि असल जिंदगि का मोड़-संगाड़...।

'तीस' किताब में 78 कविताओं के बाद 18 क्षणिकाएं हैं। इन क्षणिकाओं में भी मानव जीवन की नियत और नियति को सटीकता से उजागर किया है। ये क्षणिकाएं आज के जीवन की विडंबनाओं पर खूब चटकारें लेती हैं-

जौं का पास, ना जाण-पछ्याण, अर ! न कळ्दार,
वूं तैं ही ठगौण लग्यां, आजकाळ गळादार...।

लोकसाहित्य के लिए समर्पित आखर के संस्थापक और अध्यक्ष संदीप रावत प्रयोगधर्मी हैं। एक जगह ठहरना उनके स्वभाव में नहीं है। निरंतर सक्रीयता उनकी आदत में शुमार है और जब आदतें सामाजिक दायित्यों के निर्वहन के लिए हो तो वह जीवन की सार्थकता और व्यापकता को निखारती ही हैं। संदीप अपने अध्यापन, साहित्य और संगीत कर्म को इसी भाव से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गढ़वाली लेखक एवं शिक्षक संदीप रावत कोलंबिया पेसेफिक वर्चुअल विश्वविद्यालय, मथुरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुए हैं। यह मानद डॉक्टरेट उपाधि उन्हें गढ़वाली साहित्य एवं लोक संस्कृति में कार्य करने, नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा व लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रदान की गई। मथुरा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू दिलेर (राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश) व विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉ. रश्मि शर्मा के हाथों प्रदान की गई। संदीप रावत की साहित्य प्रतिभा निरंतर निखरेगी ऐसी आशा सभी साहित्य प्रेमियों को है। गढ़वाली साहित्य संसार में पूरी तैयारी के साथ मजबूत एक लपाग में उपस्थिति दर्ज करवाने वाले इस संभावनाशील युवा का स्वागत एवं भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। ●

- **लोक परंपराओं के टूटने का दर्द संदीप रावत की कहानियों और कविताओं का एक मुख्य हिस्सा होता है, मानवीय संवेदनाओं से लबालब इस युवा साहित्यकार से गढ़वाली साहित्य के और समृद्ध होने की आशा बलवती होती है, संदीप रावत आकाशवाणी और दूरदर्शन के नियमित वार्ताकार हैं।**
- **लोकसाहित्य के लिए समर्पित आखर के संस्थापक और अध्यक्ष संदीप रावत प्रयोगधर्मी हैं, एक जगह ठहरना उनके स्वभाव में नहीं है, निरंतर सक्रीयता उनकी आदत में शुमार है और जब आदतें सामाजिक दायित्यों के निर्वहन के लिए हो तो वह जीवन की सार्थकता और व्यापकता को निखारती हैं।**

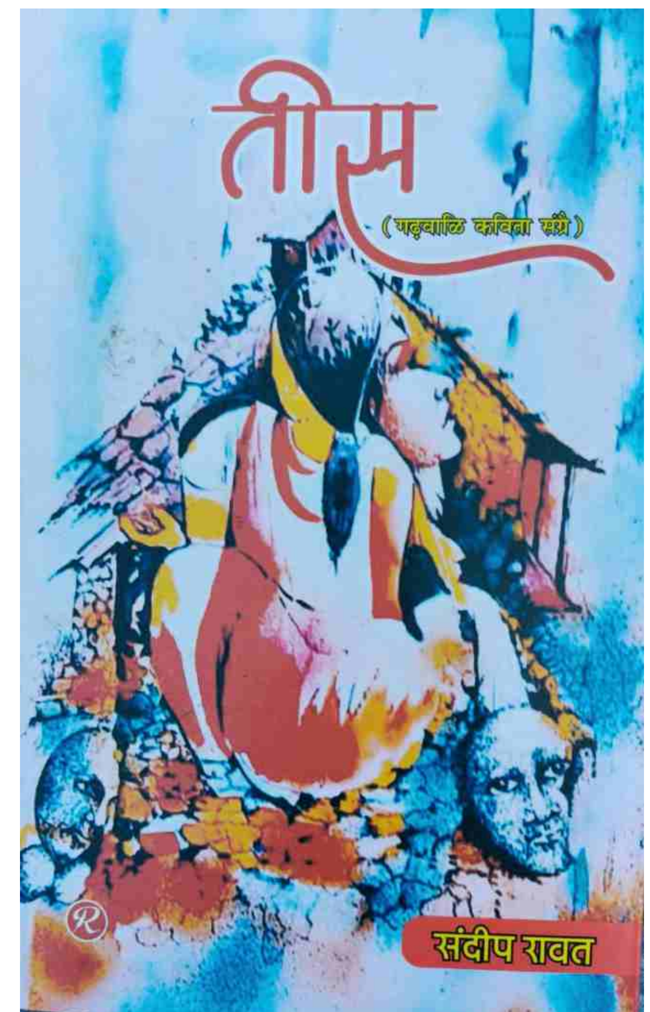

अमेरिका के टारगेट पर मोदी ?

ढाका के होटल में मृत मिले सीआईए एजेंट टेरेंस अर्वेल जैक्सन को सतही तौर पर बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर सेना प्रशिक्षण के लिए तैनात दिखाया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसका असली मिशन भारत के भीतर और खासकर पीएम मोदी के खिलाफ गुप्त कार्रवाई करना था।

उदयभान सिंह
लेखक

भारत की तरक्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता से जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट ही नहीं आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक बौखलाए हुए हैं। इसलिए भारत विरोधी ताकतें संगठित होकर भारत को हर तरह का नुकसान पहुंचाने में लगी हैं, लेकिन डीप स्टेट कोहर मोर्चे पर मुंह की ही खानी पड़ रही है। इसका एक नमूना पड़ोसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के होटल में अमेरिकी स्पेशल फोर्स (सीआईए) एजेंट टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमय मौत है, जिसने पूरे दक्षिण एशिया में खुफिया हलचल मचा दी है। आर्गेनाइजर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि यह मौत महज एक हादसा या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम करने का नतीजा हो सकती है। हालांकि इन दावों की किसी भी सरकारी एजेंसी ने अब तक पुष्टि नहीं की है। ऑर्गनाइजर की रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त को सीआईए अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन ढाका के द वेस्टिन के कमरा नंबर 808 में मृत पाए गए थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज में कोई अनियमित गतिविधि नहीं दिखी। उनका शव पोस्टमार्टम के बिना ही ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया। टेरेंस अर्वेल जैक्सन अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े थे और 'सुरक्षा प्रशिक्षण मिशन' पर बांग्लादेश में तैनात थे। ऑर्गनाइजर की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका असली मिशन कुछ और था, यानी दक्षिण एशिया में भारत को टारगेट करना। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण एशिया में सीआईए की गतिविधियां तेज हुई हैं। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के हालिया घटनाक्रमों के पीछे अमेरिकी दखल की संभावना पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब टेरेंस अर्वेल जैक्सन की मौत ने इस संदेह को और गहरा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जैक्सन को सतही तौर पर बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर सेना प्रशिक्षण के लिए तैनात दिखाया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसका असली मिशन भारत के भीतर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुप्त कार्रवाई को अंजाम देना था। जैक्सन की मौत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में चीन के तियानजिन में थे। सम्मेलन के बाद नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार में 45 मिनट तक गुप्त बातचीत की थी। तब मीडिया रिपोर्ट में किसी को ये अनुमान नहीं था कि पुतिन और मोदी 45 मिनट तक कार में किस कारण थे। अब सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गरम है।

पुतिन व मोदी के कार में बैठने का रहस्य

एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 45 मिनट तक कार में साथ रहे मोदी और पुतिन के बीच हाई-प्रोफाइल एजेंडा और दक्षिण एशिया में चल रही खुफिया गतिविधियों पर चर्चा हुई होगी। ऑर्गनाइजर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार में दोनों नेताओं ने एक गुप्त सुरक्षा खतरे पर चर्चा की होगी, जिसे रूस और भारत की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर नाकाम किया। क्योंकि उसी शाम जैक्सन ढाका में मृत पाया गया था। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में जैक्शन की मौत की टाइमिंग और बिना पोस्टमार्टम कराए लाश को अमेरिकी दूतावास को सौपने तथा गुपचुप तरीके से जैक्शन की लाश अमेरिका ले जाने पर सवाल उठाए तो तियानजिन में पुतिन और मोदी के 45 मिनट तक कार में रहने का रहस्य सामने आया। चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में भाग लेकर दिल्ली लौटने के बाद 2 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यहां उनके स्वागत में तालिया बजी तो पीएम मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था 'क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वापस आया हूं?' सम्मेलन में मोदी की इस रहस्यमयी टिप्पणी पर तब ठहाके लगे थे। लेकिन अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यह वाक्य किसी गहरे संकेत से भरा हुआ था। विश्लेषकों का मानना है कि सेमीकॉन सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने खुद ही जानलेवा खतरे के प्रति संकेत दिए थे।

दो सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन सम्मेलन में हिस्सा लिया था, यहां उनके स्वागत में तालिया बजी तो पीएम मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था 'क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वापस आया हूं?' इसके मायने समझे जा सकते हैं?

- **ट्रंप पीएम मोदी के लिए कठिन माहौल बनाने वाली राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ भी लगा रखा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम पड़ोसी देशों को परेशान करने के बाद अब अमेरिका, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है?**
- **अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए दुनियाभर में सरकारों को गिराने, नेताओं की हत्या करने, दो देशों के बीच युद्ध कराने के लिए बदनाम है, नागरिक विद्रोह भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बनाने, सरकारें गिराने और अमेरिका का अधिपत्य स्थापित कराने के लिए कुख्यात है।**

दुनिया में बदनाम सीआईए

अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी सीआईए दुनियाभर में सरकारों को गिराने, नेताओं की हत्या करने, देशों के बीच युद्ध कराने जैसे कामों के लिए बदनाम रही है। सीआईए नागरिक विद्रोह को भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बनाती है, सरकारें गिराती है और अमेरिका का अधिपत्य स्थापित करती है। जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हाल के कुछ वर्षों में हुआ है। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ सालों से लगातार सीआईए काफी एक्टिव है और पिछले कई सालों में आप जो भी गतिविधियां भारत के पड़ोसी देशों में देख रहे हैं, उसमें सीआईए की बड़ी भूमिका है। इसलिए अमेरिकी सैन्य अधिकारी टेरेंस आर्वेल जैक्सन की रहस्यमय मौत मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक अटकलों का कारण बन रही है। दक्षिण एशिया में सीआईए की बढ़ती गतिविधियों और भारत के पड़ोस में उसकी मौजूदगी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के छिपे एजेंडे पर सवाल खड़े करें हैं। यह आशंका भी जताई जा रही है कि सीआईए ने कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश तो नहीं रची थी? जिसे भारत और रूस की संयुक्त खुफिया कार्रवाई ने विफल कर दिया। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ऐसे षडयंत्र रचने के लिए विश्व में बदनाम है। सरकारों को गिराना, विरोध भड़काना और भू-राजनीतिक परिदृश्य को अपने हित में मोड़ना, ये सब सीआईए के जाने पहचाने हथकंडे हैं। दक्षिण एशिया में भी अमेरिका की गतिविधियां कोई नई बात नहीं हैं। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से लेकर हाल ही में बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता सब कुछ दक्षिण एशिया में सीआईए का ही षडयंत्र है। अब ढाका के एक होटल में सीआईए एजेंट टेरेंस आर्वेल जैक्सन की रहस्यमय मौत ने इन शंकाओं को और पुख्ता कर दिया है। आशंका ये है कि यही अमेरिकी सीआईए अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा था? लेकिन मोदी और पुतिन के नेतृत्व में भारत और रूस की एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर ढाका में उस अमेरिकी अधिकारी को निष्क्रिय कर दिया।

ये मोदी का नया भारत है

भारत को अस्थिर करने या अराजकता फैलाने की सीआईए की कोशिशें नई नहीं हैं। दशकों से ऐसे प्रयास जारी हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये गतिविधियां और आक्रामक हुई हैं, क्योंकि आज भारत में एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार है जो किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और भौगोलिक अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अमेरिका या किसी भी अन्य विदेशी शक्ति की मनमानी को भारत अब स्वीकार नहीं करता है। चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप का भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का बेबुनियाद और भ्रामक दावा हो या फिर रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला, भारत ने हर बार अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। यही 'नया भारत' है जिसकी पहचान अब दृढ़, आत्मविश्वासी और अडिग भारत के रूप में होती है। हालांकि कुछ विदेशी ताकतों को भारत का यह आत्मनिर्भर और मजबूत रुख असहज करता है। वे भारत की विकास गति को रोकने या राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना भी उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगा, अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा और नया भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा।

भारत-अमेरिका के संबंध प्रभावित होंगे

ऑर्गनाइजर की रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई गई है कि क्या अमेरिकी अधिकारी जैक्सन को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। ऑर्गेनाइजर ने एक्सपर्ट्स के हवाले से अनुमान लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की योजना और कोशिश हो सकती है। रिपोर्ट में कई सुराग और घटनाओं को जोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि जैक्सन भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गुप्त कार्रवाई या असाइनमेंट पर तैनात किया गया था, लेकिन उसका प्लान नाकाम हो गया। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दावतें दे रहे हैं। पीएम मोदी के लिए कठिन माहौल बनाने वाली राजनीतिक बयानबाजी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ भी लगा रखा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम पड़ोसी देशों को परेशान करने के बाद अब अमेरिका, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? क्या सीआईए डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत को अस्थिरता की आग में झोंकना चाहती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में हुआ है? हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अगर ऑर्गनाइजर की ये रिपोर्ट सच है तो भारत-अमेरिका संबंध को बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है।

विनोद खन्ना की फिल्मी जिंदगी

उच्च शिक्षा की पढ़ाई के दौरान ही विनोद का झुकाव फिल्मों की तरफ हुआ और उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का मन बना लिया। विनोद के पिता चाहते थे कि विनोद उनका कारोबार संभाले, लेकिन विनोद नहीं माने। कॉलेज के दिनों से ही विनोद खन्ना ने थियेटर में काम करना शुरू कर दिया था।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे विनोद खन्ना की गिनती बीते जमाने के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में होती थी। विनोद खन्ना के माता-पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। विनोद खन्ना एक उद्यमी परिवार से संबंध रखते थे। उनके परिवार के किसी भी सदस्य का अभिनय जगत से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। ऐसे में बॉलीवुड में उनके लिए पैर जमाना आसान नहीं था। विनोद खन्ना के पिता का कपड़ों और केमिकल उत्पादन का कारोबार था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पेशावर से मुंबई चला आया। विनोद खन्ना ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की। 1957 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। विनोद खन्ना की बाकी की शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। तीन साल बाद उनका परिवार फिर से मुंबई पहुंचा। जहां सीडेनहम कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक किया था। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के दौरान ही विनोद का झुकाव फिल्मों की तरफ हुआ और उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का मन बना लिया। विनोद के पिता चाहते थे कि विनोद उनका कारोबार संभाले, लेकिन विनोद नहीं माने। कॉलेज के दिनों से ही विनोद खन्ना ने थियेटर में काम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उनके पिता को विनोद खन्ना की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने विनोद खन्ना को दो साल का समय दिया। इस दौरान विनोद ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार उन्हें सफलता भी मिली। विनोद खन्ना को सुनील दत्त की 1968 में आई फिल्म 'मन का मीत' में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने विलेन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने 'आन मिलो सजना', 'पूरब और पश्चिम', 'सच्चा झूठा', 'मेरा गांव मेरा देश', 'मस्ताना' जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। विनोद खन्ना की गिनती उन अभिनेताओं में होती है, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत खलनायक के रूप में की, लेकिन फिल्म जगत में अपने शानदार अभिनय की बदौलत मशहूर नायक के रूप में स्थापित हुए।

अभिनेता से राजनेता बने

1971 में आई फिल्म 'हम तुम और वो' में विनोद को लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इसी साल विनोद खन्ना ने गीतांजलि से शादी कर ली। गीतांजलि-विनोद खन्ना की कॉलेज की दोस्त और मॉडल थी। विनोद और गीतांजलि के दो बच्चे हुए अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, जो अभिनेता हैं। इस दौरान विनोद खन्ना ने कई मुख्य भूमिका और मल्टी स्टारर फिल्मों में अभिनय किया जिनमें 'मैं तुलसी तेरे आंगन की', 'जेल यात्रा', 'ताकत', 'दौलत', 'हेरा-फेरी', 'अमर अकबर एंथनी', 'द बर्निंग ट्रेन', 'खून-पसीना' आदि शामिल हैं। एक समय ऐसा था जब विनोद खन्ना की गिनती बॉलीवुड के सबसे टॉप अभिनेताओं में होने लगी थी, लेकिन अचानक उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया। इस खबर से पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस स्तब्ध थे। संन्यास लेने के बाद विनोद खन्ना 1982 में आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में जाकर रहने लगे। पत्नी गीतांजलि ने विनोद खन्ना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो संन्यास छोड़ने को तैयार नहीं हुए लिहाजा 1985 में गीतांजलि से उनका तलाक हो गया। ओशो के शरण में लगभग पांच साल रहने के बाद 1987 में विनोद ने संन्यास छोड़कर बॉलीवुड में फिल्म 'इन्साफ' से कमबैक किया। मुकुल आनंद निर्देशित इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने कुछ फिल्मों में लीड रोल करने के बाद चरित्र अभिनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' विनोद खन्ना अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म थी, जो राजमाता विजय राजे सिंधिया पर बनी थी जिसे गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने लिखा था। 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। विनोद ने 1990 में दूसरी शादी कविता से कर ली। विनोद और कविता के दो बच्चे बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा है। 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पंजाब में गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। वह 1998, 1999, 2004 और 2014 में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुए। 2002 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें संस्कृति और पर्यटन मंत्री बना दिया था। इसके बाद सिर्फ 6 माह में ही उन्हें अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया था। एक सफल अभिनेता से सफल राजनीतिज्ञ तक का सफर तय करने वाले विनोद खन्ना का 27 अप्रैल, 2017 को 70 वर्ष की उम्र में मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। 2018 में उन्हें मरणोपरांत भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद खन्ना आज नहीं है लेकिन विनोद खन्ना को अपने शानदार अभिनय के लिए हिंदी सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा।

'मन का मीत' से करियर की शुरुआत

70 के दशक का बॉलीवुड अपने बेहतरीन फिल्मों और फैशन के नए तरीकों के कारण जाना जाता था। इस दशक में कई प्रसिद्ध चेहरे फिल्म इंडस्ट्री में आए। ज्यादातर लोग हीरो बनने के लिए इससे जुड़े। लेकिन इतने सारे लोगों में से एक स्टार निकल कर आया। जिसका नाम था विनोद खन्ना। दरअसल एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। जिन्होंने विनोद खन्ना को फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। जिसके बाद सुनील दत्त के भाई सोम दत्त अभिनीत फिल्म 'मन का मीत' (1968) में खलनायक की भूमिका मिली। सिनेमा में लीड रोल मिलने से पहले कई सितारों की मौजूदगी वाली फिल्में विनोद खन्ना ने की। जिसमें अमर अकबर एंथोनी, बर्निंग ट्रेन, एक और एक ग्यारह और मुकद्दर का सिकंदर शामिल है। 'मेरे अपने' फिल्म का निर्देशन गुलजार ने किया था। निर्देशक के तौर पर ये उनकी पहली फिल्म थी। इसमें अभिनेता के तौर पर उन्होंने विनोद खन्ना को लिया था। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के नेता के तौर पर विनोद खन्ना इस फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं। उनकी युवाओं के नेता की भूमिका को सराहा गया। विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्में की है। अमिताभ उस वक्त अपने करियर के शिखर पर थे। दोनों कलाकारों के बीच खटास की कई खबरें भी आई, लेकिन विनोद खन्ना हमेशा कहते थे कि अमिताभ उनके अच्छे दोस्त हैं।

फिल्म जैसी जिंदगी

बॉलीवुड में जब भी रौबदार अंदाज, करिश्माई पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग की बात होती है, तो विनोद खन्ना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन जितने बड़े स्टार वो पर्दे पर थे, उतनी ही दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरी उनकी रियल लाइफ भी रही। उन्होंने प्यार किया, शादी की, सब कुछ छोड़कर संन्यास लिया, फिर लौटे और दोबारा प्यार में पड़े। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही। बॉलीवुड में करियर सेट होते ही विनोद ने पर्सनल लाइफ को सीरियसली लेना शुरू किया। 1971 में उन्होंने गीतांजलि से शादी कर ली। फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां इस शादी में शामिल हुईं। 1972 में उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ और 1975 में छोटे बेटे अक्षय ने इस फैमिली को पूरा कर दिया। विनोद खन्ना का फैमिली के लिए एक सिंपल रूल था संडे को कोई शूटिंग नहीं। वो उस दिन पूरा समय पत्नी और बच्चों को देते थे। फीमेल फैन फॉलोइंग के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी। सब कुछ होते हुए भी विनोद खन्ना के मन में एक खालीपन था। उन्हें लगता था कि शोहरत और पैसा सब कुछ नहीं है। इसी तलाश में वो ओशो के आश्रम से जुड़े और धीरे-धीरे इतने गहरे उतर गए कि एक्टिंग छोड़ अमेरिका चले गए, जहां वो आश्रम के कामकाज संभालते थे। इस दौरान वो फोन पर फैमिली से जुड़े रहते थे, लेकिन बच्चों और पत्नी को उनकी मौजूदगी की जरूरत थी। गीतांजलि ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने तलाक का फैसला लिया। इस तरह 1985 में दोनों अलग हो गए। विनोद खन्ना जब अमेरिका से लौटे, तो करियर और फैमिली दोनों पीछे छूट चुके थे। इंडस्ट्री के दोस्तों ने उन्हें दोबारा अपनाया। 1987 में उनका अमृता सिंह के साथ एक छोटा-सा अफेयर भी हुआ, लेकिन अमृता की मां को रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। फिर 43वें बर्थडे पर उनकी मुलाकात कविता डाफ्टरी से हुई। शुरुआत में कविता को लगा कि विनोद घमंडी हैं, लेकिन एक लंबी ड्राइव ने सब कुछ बदल दिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और 15 मई 1990 को उन्होंने शादी कर ली। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'दयावान' में एक साथ नजर आए थे। कहा जाता है कि 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक किसिंग सीन के दौरान विनोद खन्ना खुद को रोक नहीं पाए। सीन के बाद भी वह माधुरी को किस करते रहे। डायरेक्टर के बार-बार कट बोलने पर भी वो अपने आपको रोक नहीं पाए। 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए फिल्म 'हिमालय पुत्र' का निर्माण किया। फिल्म बुकिंग खिड़की पर बुरी तरह से नकार दी गई। अपने चार दशक के लंबे सिने करियर में विनोद खन्ना ने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले विनोद खन्ना 27 अप्रैल, 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।

- **विनोद खन्ना की गिनती उन अभिनेताओं में होती है, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत खलनायक के रूप में की, लेकिन फिल्म जगत में अपने शानदार अभिनय की बदौलत मशहूर नायक के रूप में स्थापित हुए।**
- **बॉलीवुड में जब भी रौबदार अंदाज, करिश्माई पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग की बात होती है, तो विनोद खन्ना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन जितने बड़े स्टार वो पर्दे पर थे, उतनी ही दिलचस्प उनकी रियल लाइफ भी रही, उन्होंने प्यार किया, शादी की, सब कुछ छोड़कर संन्यास लिया, फिर लौटे और दोबारा प्यार में पड़े।**

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष:-

इस माह धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। आपके वरिष्ठ इस माह देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। अप्रेल में आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे-साथ ही आपको आकस्मिक उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं मिलेंगे। उपाय: मानसिक हिंसा से बचे, प्रभु में विश्वास रखें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृषभ:-

इस माह आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने-पहचाने से महसूस होंगे। यह माह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। घरेलू जिंदगी सुकूनभरी और रुशनुमा रहेगी। इस माह आपको सब-कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। कार्यालय में कोई आपको बढ़िया खबर दे सकता है। उपाय: गणेशजी की चार परिक्रमा लेकर आशीर्वाद ले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मिथुन:-

इस माह खीज और चिढ़चिढ़ेपन के अहसास को खुद पर हावी न होने दें। इस माह धन योग है। आप काफी धन कमा सकते हैं। बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और सुकून देंगे। प्रिय के साथ बाहर जाते समय अपने पहनावे और बरताव में नयापन दिखाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। जीवनसाथी के साथ शांत रहे ताकि लड़ाई-झगड़ा न हो। उपाय: काले चने, उड़द, तिल, सरसो का तेल दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

कर्क:-

इस माह बिना वजह के वाद-विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई बेहतरीन विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। अपने शब्दों पर काबू रखें, वरना परिवार के बुजुर्ग आहत हो सकते हैं। उन्हें अहसास कराएं कि आप उनका खयाल रखते हैं। इस माह के अंत में कारोबार के लिए की जाने वाली यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी आपका काम बिगाड़ सकता है। धैर्य रखें। उपाय: काला-सफेद कपड़ा साधु संतों को दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1

सिंह:-

इस माह आपका आत्मविश्वास और आसान कामकाज आपको आराम के लिए समय देंगे, लेकिन धन आपकी मुट्ठी से सरक सकता है। आपके अच्छे सितारे आर्थिक तंगी नहीं आने देंगे। ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती हैं, जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता होगा। कार्यालय में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। उपाय: गुरु या पिता की आज्ञा का पालन करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कन्या:-

इस माह रियल एस्टेट संबंधी निवेश अच्छा-खासा मुनाफा दे सकता है। घर में कुछ बदलाव भावुक बना सकते हैं। अपने प्रिय जीवनसाथी के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में चीजें वाकई बेहतरी की ओर बढ़ सकती हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरुकता में वृद्धि करेंगे। आपके लिए यह माह खूबसूरत रोमानी रहेगा। सेहत का ख्याल रखे वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय: धर्म स्थान पर झंडा दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7

तुला:-

लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि इस माह आपको मिल जाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाने का समय है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: अपने पार्टनर को गुलाब दें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृश्चिक:-

रिश्तेदारों का सहयोग तनाव कम करेगा। सगे संबंधियों से मिलन होगा। उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें। बच्चे और परिवार को केंद्र में रखें। किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात की प्रबल संभावना है। अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं वह टल सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। जीवनसाथी प्रेम से भरपूर रहेगा। उपाय: पूजा स्थान पर सफेद शंख स्थापित करें, कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2

धनु:-

इस माह खुद को किसी सृजनात्मक काम में व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन धन का व्यय आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। प्रिय से रोमांटिक मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती। जीवनसाथी यह बताएगा कि आप उसके लिए कितने कीमती हैं। उपाय: सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखे सुबह घर के बाहर पेड़ पौधों में डाले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मकर:-

यह माह मौज-मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें। मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है। जल्दी ही आपको जीवन-साथी मिलने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आने का प्रबल योग है। उपाय: किसी तरह का घमंड न करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कुंभ:-

इस माह कमीशन, लाभांश या रायल्टी के जरिए फायदा होने का योग बन रहा है। आपको ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाने में सहायक हों। आपका प्यार आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। लेखन और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बड़ी ख्याति प्राप्त होने से प्रसन्नता होगी। अपने व्यक्तित्व और रंग-रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

मीन:-

यह माह फायदेमंद साबित होगा। आप किसी पुरानी बीमारी से राहत और आराम महसूस करेंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपकी बचत को मुश्किल बना देगा। आप अपनी कामयाबी की फेहरिस्त में एक नया मोती जड़ेंगे। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। इस माह आपको निराशा हाथ लग सकती है। उपाय: अपने प्रिय को पिंक कलर के मोती या सिप की बनी हुई वस्तु गिफ्ट करें। कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 3